3 राजधानी
पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ जनअभियान आज से

6 अभिमत
अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा

10 राष्ट्रीय
असम 2041 तक मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा

11 विदेश
अमेरिका स्वर्णिम युग की दहलीज परः ट्रंप

RNI NO.UPHIN/2010/36547
वर्ष 14 अंक 267
लखनऊ, शनिवार, 20 जुलाई, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
लखनऊ
नगर संस्करण

लखनऊ, नई दिल्ली और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

हार्दिक का मुंबई इंडियंस के नेतृत्व करने पर संदेह
स्पोर्ट्स-12

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से भारत समेत कई प्रमुख देश प्रभावित

वैश्विक स्तर पर उड़ानें, बैंक, मीडिया आउटलेट बाधित

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

वैश्विक स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट में आई दिक्कत के चलते भारत समेत दुनिया में कई देशों में सेवाएं बाधित हुईं। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवाओं में व्यवधानों के बारे में बता रही है। आउटेज के कारण के रूप में एक नए क्राउडस्ट्राइक (साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर फर्म) अपडेट का हवाला दिया जा रहा है, जिसने विंडोज-आधारित डेस्कटॉप और लैपटॉप को प्रभावित किया है।

विश्व स्तर पर भारत सहित अमेरिका, यूरोप और एशिया में हवाई अड्डों पर लंबी कतारें लग गईं क्योंकि एयरलाइंस ने चेक-इन और बुकिंग सेवाओं तक पहुंच खो दी है, जब कई यात्री गर्मी की छुट्टियों पर जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में समाचार आउटलेट - जहां दूरसंचार गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था - को घंटों तक प्रसारित नहीं किया गया। अस्पतालों और डॉक्टरों के कार्यालयों में उनकी नियुक्ति प्रणालियों में समस्याएँ थीं, जबकि दक्षिण अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड के बैंकों ने अपनी भुगतान प्रणाली या वेबसाइटों और ऐप्स में रुकावट की सूचना दी। ओलंपिक से पहले पेरिस आने वाले कुछ एथलीटों और दर्शकों को उनकी वर्दी और मान्यता के आगमन में देरी हुई, लेकिन खेल आयोजकों ने कहा कि व्यवधान सीमित थे और इससे टिकटिंग या मशाल रिले पर कोई असर नहीं पड़ा।

बड़े पैमाने पर वैश्विक आउटेज

'मेती वैश्विक आउटेज के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के संपर्क में है'
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव

के बीच, जिसने दुनिया भर में एयरलाइंस, बैंकों और व्यवसायों के संचालन को प्रभावित किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह तीसरे पक्ष के सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म से अपडेट के कारण विंडोज़ उपकरणों को प्रभावित करने वाली समस्या से अवगत है। माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रवक्ता ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि कोई समाधान आने वाला है।'

प्रवक्ता ने कहा, हम तीसरे पक्ष के सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म से अपडेट के कारण विंडोज़ डिवाइसों को प्रभावित करने वाली समस्या से अवगत हैं। इस रुकावट ने दुनिया भर में व्यवसायों और प्रणालियों के संचालन को अधर में डाल दिया। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर पर उपयोगकर्ताओं ने लाइन-अप में समस्याओं की सूचना दी। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह विभिन्न माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स और सेवाओं तक पहुंचने में उपयोगकर्ताओं की क्षमता को प्रभावित करने वाले मुद्दे की जांच कर रहा है। सोशल मीडिया पर माइक्रोसॉफ्ट 365 स्टेटस पोस्ट के अनुसार, हमारी सेवाओं में अभी भी निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है, जबकि हम शमन कार्रवाई करना जारी रख रहे हैं। इस गड़बड़ी के कारण उपयोगकर्ताओं को ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ त्रुटि संदेश देखने को मिले और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस, बैंकों और मीडिया आउटलेट्स में व्यवधान की व्यापक रिपोर्टें हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार वैश्विक आउटेज के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है और आश्वासन दिया कि राज्य संचालित एनआईसी नेटवर्क प्रभावित नहीं होगा। आईटी मंत्री ने कहा कि इस आउटेज के कारण की पहचान कर ली गई है और समस्या के समाधान के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। सर्ट ने भी एक तकनीकी सलाह जारी की। यह बताया गया है कि क्राउडस्ट्राइक एजेंट फाल्कन सेंसर से संबंधित विंडोज होस्ट उत्पाद में प्राप्त हालिया अपडेट के कारण आउटेज का सामना कर रहे हैं और क्रैश हो रहे हैं। संबंधित विंडोज होस्ट फाल्कन से संबंधित ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ (बीएसओडी) का अनुभव कर रहे हैं। व्यापक माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण भारत सहित दुनिया भर में उड़ानें, बैंक, मीडिया आउटलेट और कंपनियां बाधित हो गईं। प्रौद्योगिकी कंपनी ने कहा कि वह माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स और सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करने वाले मुद्दे को धीरे-धीरे ठीक कर रही है, जिसके कुछ घंटों बाद तक व्यवधान बढ़ता रहा। माइक्रोसाफ्ट सेवाओं में बड़े पैमाने पर रुकावट ने विश्व स्तर पर आईटी प्रणालियों को प्रभावित किया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यवधान उत्पन्न हुआ।

आरबीआई ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं में रुकावट से 10 बैंकों और एनबीएफसी पर मामूली व्यवधान पड़ा, जिन्हें या तो सुलझा लिया गया है या हल किया जा रहा है। आरबीआई ने एक बयान में कहा, ज्यादातर बैंकों के महत्वपूर्ण सिस्टम क्लाउड में नहीं हैं और इसके अलावा, केवल कुछ बैंक ही क्राउडस्ट्राइक टूल (शेष पेज 9)

देश में कई एयरपोर्ट पर उड़ानों में पड़ा व्यवधान

राजेश कुमार। नई दिल्ली

बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज के बीच केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु में यात्रियों की भीड़ लगी रही। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट और अकासा ने शुक्रवार को मैन्युअल रूप से यात्रियों की जांच शुरू की, हस्तलिखित बोर्डिंग पास जारी किए। वैश्विक माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण नेविटेयर प्रस्थान नियंत्रण प्रणाली ठप हो गई। पीटीआई

माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्लाउड सेवा में रुकावट के कारण शुक्रवार को देश भर में कई हवाई अड्डों और एयरलाइन परिचालन को बड़े व्यवधान का सामना करना पड़ा। कई हवाई अड्डों ने परिचालन निलंबित कर दिया क्योंकि बोर्डिंग पास जारी करने सहित बुकिंग, चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रिया जैसी सेवाएं मैन्युअल रूप से की गईं, जिससे अपेक्षा से अधिक समय लगा और हवाई अड्डों पर लंबी कतारें लग गईं। इसने कई कम लागत वाली एयरलाइनों के लिए अराजकता पैदा कर दी, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा हो गईं।

इस रुकावट के कारण एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा एयरलाइंस और स्पाइसजेट सहित कई एयरलाइनों की बुकिंग और चेक-इन सेवाएं प्रभावित हुईं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे पहले से ही हवाईअड्डे पहुंचें, क्योंकि मैन्युअल चेक-इन में अधिक समय लगता है। उनसे यह भी आग्रह किया गया है कि इंतजार बढ़ने की स्थिति में वे सूखे खाद्य पदार्थ और पानी ले जाएं। यात्रियों को देरी के बारे में चेतावनी देने के लिए एयरलाइंस अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपडेट पोस्ट कर रही हैं। व्यवधान की इस अवधि के दौरान यात्रियों को हवाई अड्डे के कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह देते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने कहा कि वह असुविधा को कम करने और सभी यात्रियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हवाई अड्डों और एयरलाइन परिचालन, जिनके सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट पर आधारित थे, को शुक्रवार सुबह लगभग 10.40 बजे से महत्वपूर्ण व्यवधानों का सामना करना पड़ा। इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया और अकासा ने अपने नेटवर्क पर ऑनलाइन चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रियाओं में व्यवधान देखा, जिससे उन्हें मैन्युअल मोड पर स्विच करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एयरलाइंस को नई बुकिंग करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; यात्रियों से एक यात्रा के लिए एकाधिक बुकिंग न करने का आग्रह किया गया और उनसे कॉल सेंटरों से संपर्क न करने का आग्रह किया गया - जो उड़ान में देरी के कारण जबरदस्त कॉल वॉल्यूम का सामना कर रहे हैं - जब तक कि उनकी उड़ान 24 घंटे में प्रस्थान करने वाली न हो।केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि उनका मंत्रालय और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) वैश्विक माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से उत्पन्न स्थिति का सक्रिय रूप से प्रबंधन कर रहे हैं, जिसने देश में हवाई अड्डे और एयरलाइन संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। नायडू ने एक बयान में कहा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एएआई के सहयोग से परिचालन निरंतरता बनाए रखने के लिए मैनुअल बैकअप सिस्टम लागू किया है। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई सहित देश के प्रमुख हवाई अड्डे बड़े पैमाने पर तकनीकी खराबी के कारण ठप हैं। दिल्ली हवाईअड्डे ने कहा कि उसकी कुछ (शेष पेज 9)

सीएम योगी के ताजा आदेश को लेकर एनडीए में बेचैनी

पायनियर समाचार सेवा, नई दिल्ली/लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कांवड़ तीर्थयात्रियों के मार्ग में व्यवसायियों को नेमप्लेट प्रदर्शित करने का निर्देश देने के एक ताजा आदेश ने पार्टी सदस्यों के एक वर्ग के साथ-साथ जेडीयू और एलजेपी जैसे एनडीए में भाजपा के सहयोगियों के बीच बेचैनी पैदा कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने भी इसका अनुसरण किया और हरिद्वार से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों और उसके मालिकों के सत्यापन के अलावा इसी तरह के निर्देश जारी किए। ताजा आदेश मुजफ्फरनगर पुलिस के विवादास्पद निर्देशों के बाद आया है, जिसमें रास्ते में भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया था, जिसे बाद में यह कहते हुए वापस ले लिया गया कि यह सिर्फ स्वैच्छिक सलाह थी। न केवल विपक्ष बल्कि वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी सहित कई अन्य लोगों ने निर्देशों पर चिंता व्यक्त की। कांग्रेस ने इसे 'संविधान पर हमला' बताया और आदेश वापस लेने की मांग की। भाजपा, जो केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, ने इस उपाय का बचाव करते हुए दावा किया है कि यह उपवास करने वाले हिंदुओं को अनुमति देता है जो शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां में खाना चाहते हैं, जहां उन्हें 'सात्विक' भोजन परोसे जाने की संभावना अधिक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने-पीने की दुकानों पर नेमप्लेट लगानी होगी। यह निर्णय कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। हलाल प्रमाणीकरण वाले उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि हिंदू देवी-देवताओं के नाम वाले ज्यादातर आउटलेट मुस्लिमों द्वारा चलाए जाते हैं और वे मांसाहारी भोजन बेचते हैं। उन्होंने कहा कि उन दुकानों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।मंत्री ने कहा, यह हर फूड कार्ट का मामला नहीं है। जो लोग हरिद्वार से जल लेकर 250-300 किमी की यात्रा करते हैं, वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इस मार्ग को पार करते हैं। हमने जिला प्रशासन से आग्रह किया था कि ऐसे सभी लोग जो हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर अपना ढाबा/होटल चलाते हैं, वे ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से हैं। कांवड़िए उनकी दुकानों पर जाते हैं जहां मांसाहारी भोजन बेचा जाता है। तो, दुकान का नाम एक हिंदू देवता के नाम पर है, लेकिन वहां मांसाहार बेचा जाता है; ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उनकी पहचान की जानी चाहिए।

अग्रवाल ने कहा कि वे मांसाहारी भोजन की बिक्री के खिलाफ नहीं हैं लेकिन कांवड़ियां ऐसी दुकानों से खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा, हमें मांसाहारी भोजन की बिक्री पर कोई आपत्ति नहीं है, कांवड़िया इसे नहीं खरीदेंगे। हमने केवल इतना आग्रह किया है कि हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर दुकानें खोलकर मांसाहारी भोजन नहीं बेचा जाना चाहिए; इसलिए प्रशासन ने तदनुसार कार्रवाई की है। नेता इसे हिंदू-मुस्लिम एंगल दे रहे हैं. लेकिन ये हिंदू-मुस्लिम का मामला नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का मामला है। लोग जहां चाहें बैठ कर खा सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए (शेष पेज 9)

संसद के मानसून सत्र में छह नए बिल पेश करेगी सरकार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्र ने सोमवार से शुरू होने वाले आगामी संसद सत्र में छह नए विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें विमानन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है।

वित्त विधेयक के अलावा, सरकार ने 'आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक' को भी परिचय, विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। बृहस्पतिवार को जारी लोकसभा बुलेटिन में कहा गया है कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता लाना है। भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करना चाहता है। 22 जुलाई से शुरू होने वाला सत्र 12 अगस्त को समाप्त होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार, 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। सत्र के दौरान पेश होने और पारित होने के लिए सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता-पूर्व युग के कानून को बदलने के लिए बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं।लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) का भी गठन किया है, जो संसदीय एजेंडा तय करती है।

स्पीकर की अध्यक्षता वाली समिति में सुदीप बंद्योपाध्याय (टीएमसी), पी पी चौधरी (बीजेपी), लावु श्री कृष्ण देवरायलु (टीडीपी), निशिकांत दुबे (बीजेपी), गौरव गोगोई (कांग्रेस), संजय जयसवाल (बीजेपी), दिलेश्वर कामैत (जेडीयू), भर्तृहरि महताब (बीजेपी), दयानिधि मारन (डीएमके), बैजयंत पांडा (बीजेपी), अरविंद सावंत (शिवसेना-यूबीटी), कोडिकुन्निल सुरेश (कांग्रेस), अनुराग ठाकुर (बीजेपी) और लालजी वर्मा (एसपी) सदस्य हैं। केंद्र ने मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह बैठक संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुलाई है। यह विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए सभी दलों के फ्लोर नेताओं की पारंपरिक सत्र-संध्या बैठक में पहली बार होगा यदि वह इसमें भाग लेते हैं। विपक्षी खेमे की एक अन्य बड़ी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ने खेद व्यक्त किया है कि वह बैठक में शामिल नहीं होगी।

हरियाणा में किसी की नहीं होगी तीन हजार से कम मासिक पेंशन

मनोहर लाल की घोषणा को नायब सरकार ने किया पूरा सवा लाख पुराने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

शिखा शर्मा। चंडीगढ़

हरियाणा में अब तीन हजार रुपये से कम मासिक पेंशन वाले कर्मचारी भी बुढापा पेंशन के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी की घोषणा के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा सरकार में करीब सवा लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें ईपीएफ की पेंशन राशि राज्य में बुढ़ापा पेंशन से भी काफी कम है। प्रदेश में इस समय 3000 रुपये मासिक बुढापा पेंशन मिल रही है। जिसे बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पहले ही मंथन कर रही है। सत्ता में आने पर कांग्रेस छह हजार तो इनेलो-बसपा गठबंधन 7500 रुपये बुढापा पेंशन का ऐलान कर चुका है। इस बीच सरकार को पता चला कि प्रदेश में एचएमटी, एमआईटीसी आदि समेत कई विभागों के ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी मासिक पेंशन समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन से भी कम है। इन कर्मचारियों को ईपीएफ से पेंशन की राशि एक हजार रुपये से लेकर दो हजार रुपये मासिक तक ही मिल पा रही है। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने अंतिम बजट में इन कर्मचारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन सुविधा के दायरे में शामिल करने का ऐलान किया था।अब मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा जून माह के दौरान किए गए ऐलान के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करके साफ कर दिया है कि जिन रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन या इपीएफ राशि 3000 से कम है, वो भी बुढ़ापा पेंशन के पात्र होंगे, उन्हें अभी मिलने वाली राशि और तीन हजार के अंतर की राशि का भुगतान पेंशन के रूप में सरकार द्वारा किया जाएगा।

राज्यपालों को छूट देने वाले संवैधानिक प्रावधान की समीक्षा करेगा उच्चतम न्यायालय

पीटीआई। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 361 के उन प्रावधानों की समीक्षा करने पर शुक्रवार को सहमत हो गया जो राज्यपालों को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से पूर्ण छूट प्रदान करते हैं। शीर्ष अदालत ने यह आदेश पश्चिम बंगाल राजभवन में संविदा पर कार्यरत उस महिला कर्मचारी की याचिका पर दिया है, जिसने राज्यपाल सी वी आनंद बोस पर छेड़छाड़ करने और अधिकारियों द्वारा उसे गलत तरीके से बंधक बनाए रखने का आरोप लगाया है।प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल राजभवन की महिला की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को भी नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी। शीर्ष (शेष पेज 9)

खेडकर के खिलाफ यूपीएससी ने दर्ज कराई एफआईआर

संघ लोक सेवा आयोग ने उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं और चयनों से वंचित करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने फर्जी पहचान दिखाकर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी का लाभ उठाने के लिए परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करने सहित कई कार्रवाई शुरू की है। आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा-2022 की उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं और चयनों से वंचित करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया।आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आयोग ने बृहस्पतिवार को खेडकर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने कहा, शिकायत के बाद, पुलिस ने सिविल सेवाओं में उसकी उम्मीदवारी हासिल करने में जालसाजी, धोखाधड़ी और दिव्यांगता कोटा के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और दिव्यांगता कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। 2023 बैच की परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी खेडकर पर हाल ही में महाराष्ट्र में पुणे जिला कलेक्टरेट में अपने प्रशिक्षण के दौरान उन लाभों और सुविधाओं की मांग करके शक्ति और विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप है, जिनकी वह हकदार नहीं थीं।

उन पर आसपास के सभी लोगों को धमकाने और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक निजी ऑडी (लक्जरी सेडान) कार के ऊपर एक लाल-नीली बत्ती (उच्च पदस्थ अधिकारी का संकेत) लगाने का आरोप लगाया गया था, जिस पर 'महाराष्ट्र सरकार' भी लिखा था।

पुणे जिला कलेक्टर द्वारा मामले को उजागर करने के बाद, खेडकर को विदर्भ क्षेत्र में वाशिम जिला कलेक्टरेट में स्थानांतरित कर (शेष पेज 9)

स्लो प्वाइजन के रूप में धमनियों में जा रहा फर्टिलाइजरः योगी

प्राकृतिक खेती पर आधारित क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

● बोले सीएम, यूपी में जल्द एक कृषि विश्वविद्यालय होगा प्राकृतिक खेती को समर्पित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

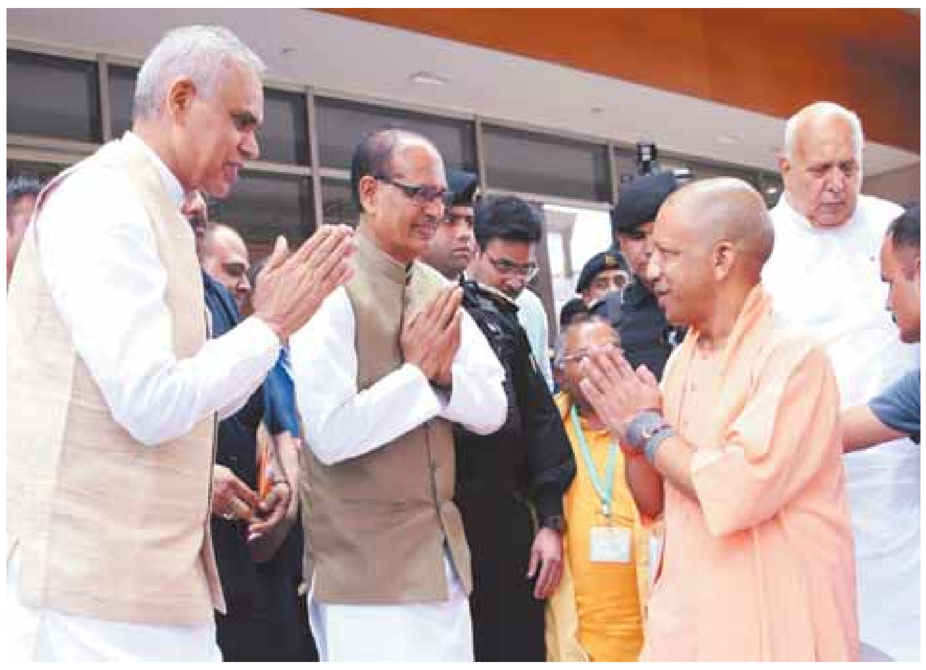

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के एक राज्य में कृषि कार्य में अत्यधिक फर्टिलाइजर के उपयोग का हश्र ये हुआ कि आज वहां से 'कैंसर ट्रेन' चलानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति से कृषि उत्पादन जरूर बढ़ा, मगर ये अधूरा सच है। आज फर्टिलाइजर की अधिकता के कारण एक 'धीमा जहर' हमारी धमनियों में घुस रहा है। ये दुष्प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि पशु-पक्षी भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि देश में कई इलाके ऐसे भी थे जहां प्राकृतिक ढंग से भी कृषि उत्पादन अधिक था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें बीज से लेकर बाजार तक कृषि उत्पादों के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में जल्द ही एक कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक खेती के लिए समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत रहे। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि हरित क्रांति का लाभ अन्न उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में हुआ है, मगर ये अधूरा सच है। हमें 17वीं और 18वीं सदी के भारत के उन प्रांतों में प्राकृतिक खेती से होने वाले उत्पादन दर को भी देखना होगा जब धरती अपने प्राकृतिक स्वरूप में थी और अन्न उत्पादन भी ज्यादा था। सीएम योगी ने कहा कि हमें खेती को लेकर पिछले सौ-डेढ़ सौ वर्ष में जो पढ़ाया गया है, उसमें और पुराने समय के विज्ञान में कितना अंतर है। हमें इतिहास के पन्नों को फिर से पलटना होगा। हरित क्रांति के बाद जब खेती में फर्टिलाइजर का उपयोग हुआ तो कुछ समय तक उत्पादन तो बढ़ा, मगर आज एक स्लो प्वाइजन के रूप में वह हमारी धमनियों में घुसता जा रहा है।

सीएम योगी ने कहा कि फर्टिलाइजर का दुष्प्रभाव केवल मनुष्यों में ही नहीं देखने को मिल रहा बल्कि पशु-पक्षी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरोहा में निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल में 12 से 14 गाय अचानक मर गईं, जब हमने वहां विशेषज्ञ भेजे तो ये पता लगा कि चारे में बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर मिला था, जिसके कारण उनकी मौत हुई। हमें समझना होगा कि जब गाय अत्यधिक फर्टिलाइजर को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है तो मनुष्य की स्थिति क्या होगी।

सीएम योगी ने कहा कि उनके पास मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए बड़ी संख्या में लोग धन की मांग करते हैं, इसमें सर्वाधिक मामले कैंसर के होते हैं। आज से कुछ साल पहले इतनी भयावह स्थिति नहीं थी। आज गांव-गांव में युवाओं में कोई किडनी, कोई हार्ट तो कोई कैंसर से पीड़ित हो गया है। इसका कारण है कि हमारा खानपान कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है। जिसने नई-नई बीमारियों को जन्म दिया है। इससे बचाव का नया मंत्र पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती का दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें बीज से लेकर बाजार तक कृषि उत्पादों के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा। यूपी में इसके लिए बड़ी संभावना है। हमारे पार देश की 12 प्रतिशत भूमि है। यूपी में देश की 17 प्रतिशत आबादी रहती है। हम देश के खाद्यान का 20 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन है। हमें आज की आवश्यकता के अनुरूप उस क्वालिटी पर ध्यान देना होगा जो हमारे हैपिनेस इंडेक्स को ऊंचाई पर ले जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। हमारे पास अभी 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, पांचवां बनने जा रहा है। 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और दो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। हमने कह रखा है कि प्राकृतिक खेती से जो भी प्रोडक्ट आता है, उसके सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम को तेज गति से आगे बढ़ाना है। बीज से इसकी शुरुआत हो और बाजार तक पहुंचने पर अच्छा दाम मिल सके, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं हम। हमने प्रदेश के कृषि विश्वविद्यलयों को कह दिया है कि सर्टिफिकेशन लैब्स को अपग्रेड कीजिए, धन सरकार देगी।

प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी देगी भारत सरकारः शिवराज सिंह चौहान

● केंद्रीय कृषि मंत्री बोले, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया चिंतित मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए केमिकल और फर्टिलाइजर के प्रयोग का परिणाम हम सबके सामने है। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंतित है, लेकिन इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इससे ये सिद्ध हो गया है कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी। ऐसे में हमें समय रहते संभलना होगा। इसके लिए हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। ये बातें शुक्रवार को प्राकृतिक खेती पर आधारित 'भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति' कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, को आत्मसात कर आगे बढ़ने वाला देश है। भारत की यह भावना प्राचीन खेती में भी निहित थी। उस समय खेती में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता था। ऐसे में धरती उपजाऊ होती थी और अन्न पोषक पैदा होते थे। वहीं धीरे-धीरे धरती पर दबाव बढ़ता गया और उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होने लगा। साथ ही नई-नई वैराइटी के लिए ऐसे बीज का प्रयोग होने लगा जिसमें ज्यादा खाद, पानी और कीटनाशक की जरूरत पड़ने लगी। इससे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन बीमारियां भी बढ़ती गयीं। इसके लिए कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलानी पड़ीं। आज हम सभी अपनी सेहत को लेकर काफी गंभीर हैं। यही वजह है कि लोग बिना केमिकल फर्टिलाइजर के कृषि उत्पाद को खरीदने के लिए दोगुने दाम देने को तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन में कमी आएगी, यह लोगों का भ्रम है। प्राकृतिक खेती से न तो उत्पादन कम होगा और न ही भंडारण में कमी आएगी। उन्होंने ऐसे किसानों को बधाई दी जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कीटनाशक दवाइयों के इस्तेमाल से धरती की उर्वरक क्षमता प्रभावित होती है। इससे कीट मित्र जमीन से खत्म होते जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि दुनिया में आपदाएं बढ़ती जा रही है। यह मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा है। ऐसे में हमे समय रहते सावधान रहना होगा और धरती के अस्तित्व को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत सरकार धरती के अस्तित्व को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए भारत सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी देगी। इसके लिए उन्हे प्राकृतिक खेती के सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था करेगी। साथ ही तीन साल तक किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए उनके खातों में पैसा भेजेगी।

ठगों के गिरोह के लिए बैंक खाते संचालित करने वाले सरगना सहित तीन गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

एसटीएफ ने टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम स गूगल पर टास्क पूरा करने पर धन दोगुना करने का लालच देकर ठगी करने वाले संगठित गिरोह के लिए कमीशन पर लिए गए बैंक खातों का संचालन कर रुपए को यूएसडीटी में विभिन्न एप के माध्यम से कनवर्ट कर गैंग के वालेट में ट्रांसफर करने वाले सरगना सहित 3 अभियुक्तों को जोधपुर (राजस्थान) से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया सरगना प्रकाश नवल जोधपुर, राजस्थान का रहने वाला है। इसके अलावा अन्य दोनों अभियुक्त सतीश नवल उर्फ मोन्ट और कैलाश चन्द्र सुकेरिया भी राजस्थान के हैं। गिरफ्तार अभियुक्त प्रकाश नवल ने पूछताछ में बताया कि मैने वर्ष 2014 में आईटीआई की है। वर्ष 2016 से 2020 तक एसबीआई व आईसीआईसीआई बैंक में केडिट कार्ड डिपार्टमेंट में काम किया तथा वर्ष 2020 से 2023 तक जयपुर में भारत-पे में टीम लीडर के पद पर कार्यरत रहा। इसी दौरान सितम्बर-2023 में मेरे टेलीग्राम पर मैसेज आया कि आप को यूपीआई पेमेंट पोर्ट मल्टीनेशनल कंपनी में कलेक्शन मैनेजर के पद पर जाब का आफर है, यदि आप काम करना चाहे तो कर सकते है। हमारी कम्पनी क्रिप्टो में इनवेस्ट कराती है कस्टमर द्वारा आपके बैंक खाते में रूपये भेजे जायेंगे। जिसको आपको 12 प्रतिशत कमीशन काटकर यूएसडीटी में कनवर्ट करके कम्पनी के वालेट में ट्रांसफर करना होगा।

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **नेहा रस्तोगी प्रॉपराइटर मेसर्स श्री गोल्ड्स, विवेक रस्तोगी और निशांत अग्रवाल** को 14.02.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.M002XXXI-01 **(आइएचएफएल का पहले लोन खाता नं.HLAPBRL00372197)** की राशि रू.1,39,42,645.64/- **(रुपए एक करोड़ उनतालीस लाख बयालीस हजार छ सौ पैंतालीस और चौसठ पैसे मात्र)** और 09.02.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। इसके अलावा आईएचएफएल ने दिनांक 21.08.2023. के असाइनमेंट करार द्वारा **इंडियाबुल्स एआरसी-XXXI के ट्रस्ट के ट्रस्टी** के रूप में **इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के पक्ष में उपरोक्त सभी ऋणो के अधिकार, शिर्षक और इन्ट्रेस्ट को सोंपा गया है।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वियन करके 16.07.2024 को संपत्ति पर **आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एततद्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशी रू.1,39,42,645.64/- (रुपए एक करोड़ उनतालीस लाख बयालीस हजार छ सौ पैंतालीस और चौसठ पैसे मात्र)** 09.02.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियो को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय प्लॉट नं. 12ए, बंगलो नं.13ए का भाग, मापित 201.50 स्के.मी. सिविल लाइन्स पर स्थित, तहसील और जिला बरेली , बरेली -243001 , उत्तर प्रदेश, जो निम्नुंसार परिबद्ध है:
पूर्व : रोड 16 फीट 9 इंच चौड़ा उसके बाद सुधा अग्रवाल और रूपाली का मकान
पश्चिम : वन विभाग की जमीन
उत्तर : संजय गुप्ता और अन्य का मकान
दक्षिण : रोड 17 फीट 6 इंच चौड़ा, उसके बाद अशोक जी का मकान और गांधी का मकान
दिनांक :16.07.2024
स्थान :बरेली

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
इंडियाबुल्स एआरसी-XXXI के ट्रस्टी की ओर से

सपा ने मनाई पूर्व मंत्री शारदा नंद अंचल की जयंती

लखनऊ। सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री स्व. शारदा नंद अंचल की जयंती शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ और बलिया जनपद के मौरहवा में सादगी से मनाई गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने राज्य मुख्यालय लखनऊ में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डॉक्ट राजपाल कश्यप पूर्व एमएलसी, रामकुमार पूर्व विधायक, विजय प्रकाश अंचल, व्यासजी गोंड, रीबू श्रीवास्तव, शशि भूषण यादव, बृजेश सिंह बैचलर, अशोक यादव आदि नेताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किये।

आरएसएस का एजेंडा लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही थोपनाः अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है और उसके मातृ संगठन आरएसएस का एजेंडा लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही थोपना है। इन दोनों की कोशिश है कि विधानसभा के उपचुनाव में साजिश करके जैसे तैसे लोकतंत्र की पवित्रता भंग की जाए। समाजवादी पार्टी भाजपा की इन साजिशों से सतर्क है और उनके किसी भी कुत्सित इरादे को सफल नहीं होने देगी। जनता भी भाजपा को करारी शिकस्त देने के लिए मन बना चुकी है।

यादव शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ के डॉ. लोहिया सभागार में एकत्र पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा में सत्ता संघर्ष छिड़ा हुआ है। इस कारण राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही है। थाना- तहसील और दूसरे विभागों में जनता भटक रही है, बिना रिश्वत कोई काम नहीं हो रहा है। जनता त्रस्त है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। यादव ने कहा कि भाजपा ने नफरत फैलाने के अपने एजेंडा के तहत उत्तर प्रदेश-उत्तराखण्ड में होटल, ढाबा और ठेला लगाकर जीवनयापन करने वालों को अपना नाम लिखने का सरकारी आदेश देकर साबित कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर सौहार्द और भाईचारा नहीं रहने देना चाहती है।

अखिलेश यादव ने कहा कि विगत लगभग आठ वर्ष में भाजपा ने सरकार में रहते हुए विकास का कोई काम नहीं किया है। विकास भाजपा सरकार में पूरी तरह ठप्प है। भाजपा की सरकार में नौजवानों को धोखा मिला है। उनकी रोटी-रोजगार के प्रति सरकार जरा भी फिक्रमंद नहीं है। उनका भविष्य अंधकार में है। नौकरियों में छंटनी हो रही है।

यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में किसान सर्वाधिक उत्पीड़ित है। किसानों की आय दोगुनी करने का झांसा दिया गया था, उसे भी पूरा नहीं किया। उसकी फसलों का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। भाजपा किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार नहीं देना चाहती है। भाजपा सरकार में बाजार पर पूंजी घरानों का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। महंगाई चरम पर है। जनसामान्य के उपयोग की सभी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। भाजपा सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है।

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना के लिए प्रतिबद्ध है। पीडीए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों, महिलाओं, गरीबों की साझा ताकत के आगे भाजपा कहीं भी टिक नहीं सकती है। भाजपा तो जनता के जनादेष को कुचल कर सत्तासीन है। विधानसभा उपचुनाव और 2027 के विधानसभा के आम चुनाव में अब जनता जनार्दन भाजपा का सूपड़ा साफ करने को तैयार है।

संगठन को ताकत देकर 2027 के चुनाव में प्रदेश में बनानी है कांग्रेस की सरकारः अजय राय

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी निशक्तजन (विकलांग) प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों एवं सभी जिला-शहर चेयरमैन की एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक की अध्यक्षता प्रकोष्ठ के चेयरमैन मनीष प्रसाद श्रीवास्तव तथा संचालन प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार वर्मा ने की।

इस मौके पर अजय राय ने कहा कि जो जज्बा आपके पास है, आप के अन्दर जो दृढ़ इच्छा शक्ति है आप लोग किसी भी तरह कमजोर नहीं हैं, इतनी दूर-दूर से आप लोग आये हैं, इसी जज्बे और मेहनत से संगठन को ताकत देकर आने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनानी है। आप निश्चित मान लीजिए उप्र में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। राय ने कहा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको मेरी जहां और जिस तरह की आवश्यकता होगी पूरा कांग्रेस परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। किसी भी संघर्ष में हम पीछे नहीं रहेंगे। राय ने प्रदेश के कोने-कोने से आये निशक्तजन (विकलांग) प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनता आज कांग्रेस की ओर देख रही है, जनता का समर्थन पूरी तरह मिल रहा है। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस हर वर्ग के लिए संघर्ष कर रही है।

उन्होंने कहा कि वह आज सुबह अयोध्या गए वहां एक पुराने मामले में जिलाध्यक्ष को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं जेल पहुंचकर उनसे मिला तो जिलाध्यक्ष ने कहा कि आपके आने से जो बल मुझे मिला है आम जनता की सेवा के लिए चाहे मुझे साल भर भी जेल में रहना पड़े तो मैं खुशी से रहा लूंगा। राय ने कहा कि मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग खुद को कमजोर व अकेला न समझें पूरी ताकत से काम करें, किसी भी समस्या पर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। बैठक के दौरान दिव्यांगजनों की समस्याओं को लेकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन मनीष प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो वादे किये थे आज भी वह जस के तस हैं।

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **नेहा रस्तोगी प्रॉपराइटर मेसर्स श्री गोल्ड्स, विवेक रस्तोगी और निशांत अग्रवाल** को 26.05.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.M002XXXI-02 **(आइएचएफएल का पहले लोन खाता नं.HLAPBRL00449153)** की राशि रू.28,09,148.36 /- **(रुपए अट्ठाईस लाख नौ हजार एक सौ अडतालीस और छत्तीस पैसे मात्र)** और 25.05.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। इसके अलावा आईएचएफएल ने दिनांक 21.08.2023. के असाइनमेंट करार द्वारा **इंडियाबुल्स एआरसी-XXXI के ट्रस्ट के ट्रस्टी** के रूप में **इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के पक्ष में उपरोक्त सभी ऋणो के अधिकार, शिर्षक और इन्ट्रेस्ट को सोंपा गया है।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वियन करके 16.07.2024 को संपत्ति पर **आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एततद्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशी **रू.28,09,148.36 /- (रुपए अट्ठाईस लाख नौ हजार एक सौ अडतालीस और छत्तीस पैसे मात्र)** 25.05.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियो को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय मकान संपत्ति नं.13ए के सभी भाग और खंड, प्लॉट नं.12ए का भाग, मापित 201.50 स्के. मी., सिविल लाइन्स पर स्थित, बरेली -243001 , उत्तर प्रदेश, जो निम्नुंसार परिबद्ध है:
पूर्व : रोड 16 .9 फीट चौड़ा उसके बाद सुधा अग्रवाल और रूपाली का मकान
पश्चिम : वन विभाग की जमीन
उत्तर : संजय गुप्ता का मकान
दक्षिण : रोड 17 .6 फीट चौड़ा रोड, उसके बाद अशोक जी का मकान और गांधी का मकान
दिनांक :16.07.2024
स्थान :बरेली

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
इंडियाबुल्स एआरसी-XXXI के ट्रस्टी की ओर से

पायनियर वर्गीकृत

सूचना

मैंने अपना नाम जफरूददीन सरफराज खान से बदलकर मोहम्मद जफरूददीन खान पुत्र सरफराज जाहिद खान निवासी 546, रहमत बाबा ललौली, फतेहपुर कर लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए,

सूचना

मेरा आर्मी नम्बर 4289325H NK M/K अविनाश सिंह पुत्री आयूषी सिंह ग्रा० गौरा बरामऊ पोस्ट गौरा लोहरिया थाना बल्दीराय तहसील बल्दीराय जिला सुल्तानपुर पिन 227806 (उ०प्र०) यूनिट सत्तरह कोरप्स कैम्प सेना के दस्तावेजों में मेरी पुत्री की जन्मतिथि 15–07–2013 अंकित है जबकि उनकी सही जन्म तिथि 20–04–2015 है। अतः सही जन्म तिथि मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज की जावे।

सूचना

मैं अविरल राज पुत्र श्री अवधराम निवासी– म.स. 4/287 L सेक्टर–H जानकीपुरम लखनऊ, मेरा हाईस्कूल वर्ष–2023,रोल न.–1234946 का अंकपत्र वास्तव में कहीं खो गया है।

NOTICE

It is for general information that I NEETU W/O AJAB SINGH R/O 1-365, JAHANGIR PURI BHALSWA JAHNGIR PUR, NS MANDI, NORTH WEST DELHI-110033 declare that name of mine has been wrongly written as RINA in my minor daughter namely KOMAL KUMARI aged 14 years in her school record. The actual name of mine is NEETU which may be amended accordingly

बुंदेलखंड में 8 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत

जीबीसी 4.0 में 69 हजार करोड़ की निवेश परियोजनाओं का हुआ था शुभारंभ

● 5 माह में बुंदेलखंड में कुल निवेश परियोजनाओं का 11 प्रतिशत उतरा धरातल पर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश में कभी पिछड़े क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाले बुंदेलखंड को योगी सरकार ने निवेश का नया गंतव्य बना दिया है। फरवरी माह में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चौथे संस्करण (जीबीसी 4.0) में पीएम मोदी ने बुंदेलखंड के लिए करीब 69 हजार करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। शुभारंभ के 5 माह के अंदर बुंदेलखंड में करीब 8 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, जिससे हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। शुरू हो चुकी परियोजनाओं की यह राशि जीबीसी 4.0 में बुंदेलखंड के लिए निर्धारित परियोजना राशि की 11 प्रतिशत है और शेष परियोजनाओं के भी जल्द से जल्द शुरू होने की संभावना है।

प्रदेश में निवेश प्रक्रियाओं की निगरानी के साथ ही निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में अब तक कुल 1,14,345 करोड़ रुपए की 3984 परियाजनाओं का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। इनमें बुंदेलखंड में 7894 करोड़ रुपए की 156 परियोजनाएं शामिल हैं। यह राशि जीबीसी 4.0 में निर्धारित परियोजना राशि का 11 प्रतिशत है। जीबीसी 4.0 के दौरान बुंदेलखंड की 693 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया था, जिनकी कुल निवेश राशि 68,933 करोड़ रुपए थी। यह जीबीसी 4.0 में कुल 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का 7 प्रतिशत था। परियोजनाओं की शुरुआत से बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। साथ ही, बुंदेलखंड में लोगों को रोजगार के लिए प्रदेश के अन्य क्षेत्रों या दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना होगा।

बुंदेलखंड के जिलों की बात करें तो झांसी में सर्वाधिक 6,237 करोड़ की 62 परियोजनाओं ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इससे यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। जीबीसी 4.0 के दौरान झांसी में 27,533 करोड़ की 246 परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ था। इस लिहाज से अभी यहां 21 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं शुरू होनी शेष हैं, जो जल्द ही पूरी होंगी। इसी तरह, हमीरपुर में 963 करोड़ की 14 परियोजनाएं, ललितपुर में 246 करोड़ की 23 परियोजनाएं, महोबा में 195 करोड़ की 24 परियोजनाएं, बांदा में 58 करोड़ की 15 परियोजनाएं, जालौन में 46 करोड़ की 11 परियोजनाएं और चित्रकूट में 22 करोड़ की 7 परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। जीबीसी 4.0 में हमीरपुर में 2,187 करोड़, ललितपुर में 15,735 करोड़, महोबा में 1,682 करोड़, बांदा में 1060 करोड़, जालौन में 13,577 और चित्रकूट में 7,157 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया था।

चित्रकूट में टस्को लि. 4700 करोड़, सहस्त्रभुज फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि. 500 करोड़, वरुण बेवरेजेस लि. 496 करोड़, श्री सीमेंट्र प्रा. लि. 202 करोड़ का निवेश कर रहा है। वहीं, हमीरपुर में राजेंद्र सिंह शर्मा 660 करोड़, हिंदुस्तान यूनिलिवर लि. 230 करोड़, यूजीआर साइलस हमीरपुर प्रा. लि. 54 करोड़ का निवेश कर रहा है। जालौन में बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लि. 6000 करोड़, संचय न्यू एज डेवलपर्स प्रा. लि. 1000 करोड़, रोमिंग सोल्स टेक्नोलॉजी प्रा. लि. 900 करोड़ तो पालीवाल फूड्स प्रा. लि. 55 करोड़ के निवेश के लिए जीबीसी 4.0 में शामिल रहा है। झांसी में टस्को लि. 3430 करोड़, आरवीएनएल लि. 2840 करोड़, फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्रा. लि.1200 करोड़ और सन सोर्स एनर्जी 600 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है। इसी तरह, ललितपुर में टस्को लि.3450 करोड़, यूजीआर साइलस 48 करोड़, वी एंड एस एंटरप्राइजेस 30 करोड़ का निवेश धरातल पर उतार रहा है। महोबा में टस्को लि. 1008 करोड़, आईबी वोओजीटी सोलर फोर प्रा. लि. 80 करोड़, देसी भोग 50 करोड़ और जीआरएस होटल प्रा. लि. 50 करोड़ से परियोजना पर काम कर रहा है। वहीं, बांदा में अवादा इंडसोलर प्रा. लि. 350 करोड़ रुपए के निवेश को तैयार है।

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **नेहा रस्तोगी प्रॉपराइटर मेसर्स श्री गोल्ड्स, विवेक रस्तोगी और निशांत अग्रवाल** को 26.05.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.S039XXXI **(आइएचएफएल का पहले लोन खाता नं.HLAPBRL00513229)** की राशि रू.19,18,208.17 /- **(रुपए उन्नीस लाख अठारह हजार दो सौ आठ और सत्रह पैसे मात्र)** और 25.05.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। इसके अलावा आईएचएफएल ने दिनांक 21.08.2023. के असाइनमेंट करार द्वारा **इंडियाबुल्स एआरसी-XXXI के ट्रस्ट के ट्रस्टी** के रूप में **इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के पक्ष में उपरोक्त सभी ऋणो के अधिकार, शिर्षक और इन्ट्रेस्ट को सोंपा गया है।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वियन करके 16.07.2024 को संपत्ति पर **आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एततद्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशी **रू.19,18,208.17 /- (रुपए उन्नीस लाख अठारह हजार दो सौ आठ और सत्रह पैसे मात्र)** 25.05.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियो को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय मकान, बंगलो, संपत्ति नं.13ए के सभी भाग और खंड , प्लॉट नं.12ए का भाग, मापित 201.50 स्के.मी. सिविल लाइन्स पर स्थित, बरेली -243001 , उत्तर प्रदेश, जो निम्नुंसार परिबद्ध है:
पूर्व : रोड 16 फीट 9 इंच चौड़ा उसके बाद सुधा अग्रवाल और रूपाली का मकान
पश्चिम : वन विभाग की जमीन
उत्तर : संजय गुप्ता का मकान
दक्षिण : रोड 17 फीट 6 इंच चौड़ा, उसके बाद अशोक जी का मकान और गांधी का मकान
दिनांक :16.07.2024
स्थान :बरेली

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
इंडियाबुल्स एआरसी-XXXI के ट्रस्टी की ओर से

पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जनअभियान का आज शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री

पूरे प्रदेश में 36.50 करोड़ पौधरोपित कर इतिहास रचेगी राज्य सरकार

● जिलों में सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि करेंगे अभियान का नेतृत्व

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कुकरैल नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से अनधिकृत कब्जों से खाली कराए गए अकबरनगर क्षेत्र में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधरोपण करके 'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जनअभियान-2024' का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' आह्वान पर शुरू हो रहे इस जनअभियान में प्रदेश सरकार एक दिन में 36.50 करोड़ से अधिक पौधरोपण करके इतिहास रचेगी।

सीएम योगी के निर्देश पर सभी प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि अपने-अपने जनपदों में इस जनअभियान का नेतृत्व करेंगे। इस जनअभियान में आमजन के साथ-साथ आधे दिन तक सभी सरकारी कार्यालय, विद्यालय व अन्य संस्थाओं से जुड़े लोग भी शामिल होंगे।

उल्लेखनीय है कि सीएम योगी ने गुरुवार को ही प्रदेश के महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए वृक्षारोपण को जनांदोलन बनाने और जनसहभगिता से पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विगत 7 वर्ष में प्रदेश के अंदर 168 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जिसमें 75-80 प्रतिशत पौधे अब भी सुरक्षित हैं। अभियान के तहत सभी 18 मंडलों में पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लखनऊ मंडल में सर्वाधिक चार करोड़ एक लाख 73 हजार से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। वहीं, कानपुर मंडल में 2.96 करोड़, चित्रकूट में 2.89 करोड़, झांसी में 2.82 करोड़, मीरजापुर में 2.62 करोड़, अयोध्या में 2.39 करोड़, देवीपाटन में 2.14 करोड़, प्रयागराज में 2.07 करोड़, बरेली में 1.91 करोड़, वाराणसी में 1.76 करोड़, मुरादाबाद में 1.83 करोड़, आगरा में 1.68 करोड़, गोरखपुर में 1.65 करोड़, आजमगढ़ में 1.30 करोड़, अलीगढ़ में 1.22 करोड़, मेरठ मंडल में 1.16 करोड़, बस्ती में 1.11 करोड़ व सहारनपुर मंडल में 90.23 लाख पौधे लगेंगे। पौधरोपण स्थलों की जियो टैगिंग भी होगी। पौधरोपण के लिए विभागवार लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन को 14.29 करोड़, ग्राम्य विकास विभाग को 13 करोड़, कृषि को 2.80 करोड़, उद्यान विभाग को 1.55 करोड़, पंचायती राज को 1.27 करोड़, राजस्व को 1.05 करोड़, नगर विकास को 44.97 लाख, उच्च शिक्षा को 22.54 लाख, रेशम को 14.19 लाख, लोक निर्माण को 14.93 लाख, रेलवे को 12.66 लाख, जलशक्ति को 13.41 लाख, बेसिक शिक्षा को 15.43 लाख, स्वास्थ्य विभाग को 19.91 लाख, एमएसएमई को 15.55 लाख, औद्योगिक विकास विभाग को 7.73 लाख, माध्यमिक शिक्षा विभाग को 11.63 लाख, गृह को 10 लाख, पशुपालन को 7.26 लाख, ऊर्जा को 5.60 लाख, सहकारिता को 7.60 लाख, आवास विकास को 8.38 लाख, रक्षा को 4.95 लाख, प्राविधिक शिक्षा को 8.06 लाख, श्रम को 2.69 लाख, परिवहन विभाग को 2.53 लाख से अधिक पौधरोपण का लक्ष्य दिया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पूरे उत्साह और उमंग के साथ वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण को जनांदोलन बनाएं। पीएम/सीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सहजन का पौधा लगाने को दें। सड़कों के किनारे-किनारे व डिवाइडर पर पौधे लगाए जा सकते हैं। नदियों के किनारे भी उपयुक्त स्थान पर पौधे लगाए जाने चाहिए। विविध प्रकार के पौधे लगाए जाएं। कहीं छायादार वृक्ष हों, कहीं फलदार तो कहीं इमारती लकड़ी वाले तो कहीं औषधीय पौधे लगाएं। नदियों के किनारे, अमृत सरोवर के पास वृक्षारोपण करें। पीपल, पाकड़, जामुन, आम, नीम, गुटेल, बरगद, हरसिंगार, मौलश्री, चितवन, अर्जुन आदि के पौधे लगाएं। पूर्वजों, महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों की स्मृति में वाटिका बनाएं। पौधरोपण के साथ ट्री-गार्ड भी लगाएं। यह सुनिश्चित करें कि किस पौधे की देखभाल कौन करेगा-कैसे करेगा। पौधों के साथ सेल्फी लें और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड भी करें।

स्वामी प्रसाद मौर्य व संघमित्रा फरार, अदालत ने उद्घघोषणा जारी करने का दिया आदेश

● बिना तलाक के कथित रूप से दूसरी शादी का मामला

विधि संवाददाता। लखनऊ

बिना तलाक़ दिए दूसरी शादी करने व मारपीट, गाली गलौज, जानमाल की धमकी तथा साज़िश रचने के मामले में एमपी एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य व उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्या को फरार मानते हुए उद्घघोषणा का आदेश जारी किया है। विशेष अदालत ने यह आदेश दीपक कुमार स्वर्णकार की ओर से दाखिल परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिया है। इससे पहले विशेष अदालत ने इन दोनों के अलावा तीन अन्य अभियुक्त नीरज तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला व रितिक सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। अदालत ने इन तीनों को भी फरार घोषित किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

इससे पूर्व स्वामी प्रसाद और संघमित्रा की तरफ से विशेष अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट व परिवाद की कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने दोनों को कोई राहत देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद दीपक कुमार स्वर्णकार की ओर से विशेष अदालत में एक अर्जी दाखिल कर अभियुक्तों के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही की मांग की गई। इनके वकील रोहित त्रिपाठी का कहना था कि स्वामी प्रसाद और संघमित्रा ने गैर जमानती वारंट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के इस आदेश को अखंडित रखा। उन्हें कोई राहत नहीं दी। इस प्रकार अभियुक्तों को अपने विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट की जानकारी थी। बावजूद इसके वो इस अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। लिहाजा उनके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 की कार्यवाही की जाए।

मामला-: पत्रावली के अनुसार सुशांत गोल्फ सिटी के रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार ने अदालत में दाखिल अपने परिवाद में आरोप लगाया है कि वर्ष 2016 से वह एवं संघमित्रा लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। संघमित्रा और उसके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसे बताया था कि संघमित्रा की पूर्व शादी से तलाक़ हो गया है। लिहाज़ा उसने तीन जनवरी 2019 को संघमित्रा से उसके घर पर शादी कर लिया। हालांकि बाद में जब उसे पता चला तो शादी की बात उजागर नहीं होने पाए इसलिए उस पर जानलेवा हमला कराया गया। विशेष अदालत ने अभियुक्तों को मुकदमे के विचारण के लिए तलब किया लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे हैं।

नगर निगम ने 10 करोड़ की जमीन करायी खाली

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सरोजनी नगर में नगर निगम द्वारा अवैध कब्जे से बेशकीमती जमीन खाली करायी गयी। संपत्ति अधिकारी द्वारा दाउद नगर में ऊसर श्रेणी की जमीन पर अवैध कब्जे को भूमाफियाओं से खाली कराने की कार्रवाई की गयी। सरसवां और दाउदनगर सहित अन्य इलाकों की जमीन को खाली कराया गया। नगर निगम के अभियान में 10 करोड़ रुपए की जमीन खाली करायी गयी। शुक्रवार को नगर निगम प्रशसन ने अवैध कब्जे में फंसी जमीन को खाली कराने का अभियान चलाया। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के आदेश पर संपत्ति अधिकारी ने सरोजनीनगर में अवैध कब्जे में फंसी जमीन को छुडाया। दाउदनगर में गांटा संख्या 364 की जमीन, जिसकी कीमत 15 लाख, सरसवां की 3.41 करोड़, बिजनौर में 13557 वर्गफुट भूमि और मड़ियांव इलाके में 2 करोड़ रुपए की जमीन को खाली करायी।

इस कार्रवाई में तहसीलदार संजय सिंह, लेखपाल राकेश यादव, सुभाष क ौशल, आलोक कुमार अन्य लोग शामि रहे। संपत्ति अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान लगभग 10 करोड़ रुपए की जमीन खाली करायी।

लविवि के कुलसचिव को दी गयी विदाई

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर विनोद कुमार सिंह का स्थानांतरण के बाद शुक्रवार को विवि के मंथन सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कुलपति प्रो आलोक कुमार राय ने कहा कि कुलसचिव डा विनोद सिंह बेहद कर्मठ और पूर्ण मनोयोग से काम करने वाले व्यक्ति हैं और इन्होंने पूरे बुद्धिमानी के साथ अपना कार्य किया।

हमें आशा है कि डा विनोद सिंह आगे भी ऐसा ही कार्य करते रहेंगे। हम सब की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम में प्रति कुलपति प्रो मनुका खन्ना, पूर्व प्रति कुलपति प्रो अरविन्द अवस्थी, परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी, कुलानुशासक प्रो राकेश द्विवेदी, डीन एडमिशन प्रो वी के शर्मा, समन्वयक प्रवेश प्रो पंकज माथुर, अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष प्रो केया पांडेय, लूटा महामंत्री डॉ अनित्य गौरव और शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी उपस्थित थे।

महापौर ने पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का किया शुभारंभ

लखनऊ। शहर में पोर्टेबल काम्पैक्टर ट्रांसफर का महापौर द्वारा उद्घाटन किया गया। पोर्टेबल कॉम्पैक्टर उपकरण द्वारा नगर में लगने वाले कूड़े के ढेरों को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। नगर को देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर नगर निगम बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए नगर निगम निरंतर उत्तरोत्तर बेहतर प्रयास कर रहा है। गुरुवार को महापौर ने नगर की साफसफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में जोन. 4 कैलाश कुंज में नए पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का शुभारंभ किया। लखनऊ स्वच्छता अभियान में सफ लता की ओर अग्रसर नगर निगम ने जोन 4 के पेपर मिल क्षेत्र में पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का शुभ आरम्भ किया। इस पोर्टेबल कॉम्पैक्टर उपकरण से नगर में लगने वाले कूड़े के ढेरों को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। इस अवसर पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह सहित उपनेता सुशील तिवारी पम्मी, क्षेत्रीय पार्षद राजेश सिंह गब्बर, पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी, पार्षद कौशल शंकर पांडे एवं लखनऊ स्वच्छता अभियान के प्रोजेक्ट हेड अनुपम मिश्रा जोन के पंकज शुक्ला सहित सभी कर्मचारी उपस्थित रहे।

जीआईएस समाधान दिवस पर 185 आपत्तियां निस्तारित

लखनऊ। शहर में भवनों के जीआईएस सर्वे में किए गए कर निर्धारण के विरुद्ध आपत्तियों के निराकरण के लिए जीआईएस समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जोनवार 185 आपत्तियां प्राप्त हुई जिसमें से सभी 185 आपत्तियों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शुक्रवार को जीआईएस समाधान दिवस का आयोजन नगर निगम मुख्यालय स्थित त्रिलोकीनाथ हॉल में किया गया। समाधान दिवस में भवन स्वामियों से जीआईएस द्वारा किए गए कर निर्धारण के विरुद्ध लिखित आपत्तियां साक्ष्य व भवन की वर्तमान फोटो सहित आमंत्रित की गई थी। जीआईएस समाधान दिवस में सभी अपर नगर आयुक्त, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, सभी जोनल अधिकारी, कर अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक व कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ जीआईएस सर्वे की टीम मौजूद रही। समाधान दिवस में जोनवार 185 आपत्तियां प्राप्त हुई जिसमें से सभी 185 आपत्तियों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। जीआईएस समाधान दिवस में समस्त जोनल अधिकारी अपने अधीनस्थ कर अधीक्षक एवं राजस्व निरीक्षको के साथ उपस्थित रहे, जिनके द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल ही गणना व जाँच करते हुए मौके पर निस्तारण कराया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि जीआईएस समाधान दिवस प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित करते हुए जीआईएस के सभी प्रकरणो का निस्तारण कराये जाने तक जारी रखा जायेगा।

कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर एलयू में वृहद वृक्षारोपण

लखनऊ। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में एनसीसी ग्रुप व विश्वविद्यालय के सहयोग से बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसका विषय एक कैडेट एक पेड़ पहल था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आलोक कुमार राय थे। लखनऊ एनसीसी ग्रुप के कमांडर ब्रिगेडियर नीरज पुनेठा के नेतृत्व व 64 यूपी बटालियन एनसीसी के कुशल समन्वयन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमे विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति, चीफ प्रॉक्टर, डीन एकेडामिक, कार्य अधीक्षक, द्वितीय परिसर के निदेशक, व अन्य शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। पौधरोपड़ कार्यक्रम में मुख्य रूप से 64 यूपी बटालियन, 63 यूपी बीएन, 3 यूपी नेवेल, 5 यूपी एयर और 20 गर्ल्स बीएन के लगभग 250 कैडेट्स ने वृक्षारोपण किया। बृहद वृक्षारोपण में विभिन्न एनसीसी बटालियन के कमान अधिकारियों व सभी जेसीओ, एनसीओ उपस्थित रहे। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के सभी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेट कमांडर (प्रो) डी के सिंह, मेजर (डॉ) किरन लता डंगवाल, डॉ रजनीश कुमार यादव व ग्राउंड एंड गार्डेन के डायरेक्टर व उनकी पूरी टीम उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान सभी ने वृक्षारोपण कर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजली दी और स्वस्थ पर्यावरण की तरफ एक नई पहल की शुभकामनायें दी।

एलयू में पीजी की प्रवेश परीक्षा 25 से

लखनऊ। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अंतर्गत परास्नातक स्तर पर संचालित कोर्सों में दाखिले को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुक्रवार को प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 25 जुलाई घोषित कर दी है। प्रवेश परीक्षा दो पालियों में सम्पन्न कराई जायेगी। पहली पाली सुबह 10.30 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली शाम 3 बजे से 4.30 बजे तक सम्पन्न होगी। विवि के मुताबिक 25 जुलाई को पहली पाली में एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, होमसाइंस, कम्प्यूटर साइंस, बीपीएड और पब्लिक हेल्थ की परीक्षा होगी। शाम की पली में एआईएस, अप्लाइड जियोलॉजी, बीलिव आईएससी, एजूकेशन, बायोकेमिस्ट्री, पब्लिक हेल्थ की प्रवेश परीक्षा सम्पन्न होगी। इसी तरह 26 जुलाई को सुबह की पॉली में अग्रेंजी, माइक्रोबायलॉजी,मैथ और शाम की पाली में फोरेंसिक साइंस, एमपीएड, पोलिटिकल साइंस की परीक्षा होगी। 27 जुलाई को बॉटनी, इकोनॉमिक्स और शाम की पॉली में केमिस्ट्री, स्टेटिक्स, एमआईएच की परीक्षा होगी। 28 जुलाई को सुबह की पॉली में एलएलबी, शाम की पॉली में एमबीए, एमटीटीएम की परीक्षा होगी। 29 जुलाई को जियोग्राफी, एलएलएम, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी पॉली में समाजशास्त्र और जन्तु विज्ञान की प्रवेश परीक्षा होगी। 30 जुलाई को हिदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिक्स की और शाम को जियोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी, साइक्लोजी की परीक्षा होगी। 31 जुलाई को एमएड, एमवीए, एमएफए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म एंड मॉस कम्यूनिकेशन और शाम की पॉली में सोशल वर्क और कामर्स की प्रवेश परीक्षा सम्पन्न होगी।

गजवरियन खेडा में डायरिया के दो मरीज मिले, भर्ती

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कल्ली पश्चिम के गजवरियन खेडा में डायरिया के मरीजों के मिलने की शिकायतें थम नहीं रही है। शुक्रवार को भी इलाके में दो मरीज सामान्य दस्त और उल्टी के पाये गये है। जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सामु. स्वा.केन्द्र मोहनलालगंज में भर्ती कराया गया है। जबकि पूर्व में भर्ती मरीजों में से आज 1 मरीज को स्वस्थ होने के उपरान्त डिस्चार्ज कर दिया गया।

आज सामु. स्वा. केन्द्र सरोजनीनगर, लखनऊ के चिकित्सीय दल द्वारा गजवरियन खेड ,कल्ली पश्चिम का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान क्षेत्र में 2 सामान्य उल्टी दस्त का रोगी मिले, जिन्हें सामु.स्वा.केन्द्र मोहनलालगंज में भर्ती कराया गया।साथ ही गॉव के मजरे कल्ली पश्चिम, बाबूखेडा एवं अमोल में भी चिकित्सीय दल द्वारा सघन भ्रमण किया गया। उपरोक्त ग्रामों के क्षेत्रवासियों को ओआरएस पैकेट, क्लोरीन गोलियों का वितरण का वितरण किया गया तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की गयी। क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर का छिडकाव, नालियों की साफ-सफाई का कराया गया। क्षेत्र में मोबाइल शौचालय एवं एमएमयू की तैनाती थी। गजवरियन खेडा एवं कल्ली पश्चिम में 24 घंटे चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने एवं सतत निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा जल कल विभाग को उक्त क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल टैकरों की आपूर्ति हेतु निर्देशित किया गया।

बेसिक शिक्षा विभाग के तीन जिला समन्वयकों को कारण बताओ नोटिस

लखनऊ। समग्र शिक्षा के अंतर्गत बालिका शिक्षा एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों से जुड़े कार्यक्रमों के बावत होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में शामिल न होने पर तीन जिला समन्वयकों के खिलाफ शासन स्तर पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस बावत अपर राज्य परियोजना निदेशक एकता सिंह ने एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण भी मांगा है। दरअसल, 8 से 11 जुलाई को होने वाली समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी जिला समन्वयकों (बालिका शिक्षा) को शामिल होना था। इसमें बिंदुवार चर्चा कर बालिका विद्यालयों की वस्तुस्थिति से अवगत होना ही मुख्य एजेंडा था, लेकिन चार जिला समन्वयक समीक्षा बैठक में शामिल ही नहीं हुए। इनमें से एक पीलीभीत ने अधिकारियों को भारी बारिश का हवाला देते हुए बैठक में शामिल न हो पाने की अपनी असमर्थता जता दी। लेकिन अन्य तीन जिला समन्वयकों ने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा और न ही विभागीय अनुमति ली या किसी दैवीय आपदा जैसी स्थिति का जिक्र करते हुए कोई सूचना ही दी।

एक्सपर्ट ने दी तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

टी. एस. मिश्रा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सतीश चंद्र मिश्र, प्रति कुलाधिपति कपिल मिश्र एवं कुलपति डॉ. प्रशांत त्रिवेदी के मार्गदर्शन में शुक्रवार से टी. एस. मिश्रा लॉ स्कूल द्वारा तीन नवीन आपराधिक कानून पर दो दिवसीय ऑनलाइन वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में वक्ता के रुप में जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफ़ेसर (डॉ.) एम. असद मलिक एवं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर (डॉ.) वागेश्वरी देसवाल ने विषय से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। वर्कशॉप का आयोजन टी. एस. मिश्रा लॉ स्कूल के डीन प्रोफ़ेसर (डॉ.) सी. पी. सिंह की अध्यक्षता में हुआ। उनका सहयोग देते हुए विभाग की डॉ. शिप्रा मिश्रा एवं सुश्री. अन्नपूर्णा त्रिवेदी ने कार्यक्रम का संचालन किया। प्रोफेसर (डॉ.) एम. असद मलिक ने अपने भाषण में सभी को संबोधित करते हुए देश में लागू हुए तीन नए कानूनों के फ़ायदे बताए। उन्होंने बताया कि नए कानून के मुताबिक, आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंग

बीबीएयू कुलपति यूपी-उत्तराखंड इकोनॉमिक ऐसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एन. एम. पी. वर्मा को तीन वर्षों के लिये उत्तर प्रदेश- उत्तराखंड इकोनॉमिक ऐसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। विश्वविद्यालय में आयोजित उत्तर प्रदेश- उत्तराखंड इकोनॉमिक ऐसोसिएशन की 19वीं राष्ट्रीय वार्षिक संगोष्ठी के दौरान गठित जनरल बॉडी मीटिंग में हुयी निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात प्रो. एन. एम. पी. वर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई। यह संगठन उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड दोनों राज्यों में अर्थशास्त्र को बढ़ावा देने के लिए शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और शोध विद्वानों का एक प्रमुख पेशेवर संघ है। जिसका उद्देश्य भारत के समकालीन आर्थिक मुद्दों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना एवं साक्ष्य-आधारित नीति सुझाव प्रदान है।

राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में प्रवेश के लिए आवेदन जारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून ने सत्र जुलाई, 2025 के लिए कक्षा-8 में प्रवेश हेतु सूचना जारी की है। यह विद्यालय रक्षा मंत्रालय के अधीन एक अंत: सेवा शिक्षण संस्थान है, जो 1922 में स्थापित हुआ था और इसका उद्देश्य भारत की तीनों सेनाओं के लिए छात्रों को पूरी तरह से तैयार करना है ताकि उन्हें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे में अग्रिम प्रशिक्षण हेतु भेजा जा सके। प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों और छात्राओं को लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित किया जाएगा, जो 1 दिसंबर, 2024 को लखनऊ के राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में आयोजित की जाएगी।

उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) रेखा दिवाकर ने बताया कि उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई, 2025 को 11.5 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे 1 जुलाई, 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा-7 में अध्ययनरत होना चाहिए या कक्षा-7 उत्तीर्ण कर चुका होना चाहिए। परीक्षा तीन चरणों में होगी। गणित, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी की लिखित परीक्षा, बौद्धिक ज्ञान और व्यक्तित्व परीक्षण की मौखिक परीक्षा, और अन्य राज्यों के केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान।

आवेदन पत्र राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून की वेबसाइट से ऑनलाइन भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है, जहां सामान्य जाति के उम्मीदवारों को 600 और अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को 555 रुपए का भुगतान करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र 30 सितंबर, 2024 तक उप शिक्षा निदेशक (मा.), छठा मण्डल, लखनऊ-226003 के कार्यालय में पंजीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा पहुंच जाना चाहिए।

पीजीआई में ट्रांसजेंडर क्लिनिकल केयर यूनिट का शुभारंभ

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

ट्रांसजेंडर समुदाय के इलाज को लेकर पीजीआई में शुक्रवार को ट्रांसजेंडर क्लिनिकल केयर यूनिट का शुभारंभ किया गया। उत्तर भारत में यह ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित पहली क्लीनिक है। इसकी सेवाएं साप्ताहिक ओपीडी (प्रत्येक शुक्रवार) के माध्यम से प्रदान की जाएंगी और छह बिस्तरों वाले एक समर्पित वार्ड द्वारा भर्ती की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस मौके पर समारोह की मुख्य अतिथि के रूप मे देविका देवेन्द्र एस मंगलामुखी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं सलाहकार, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार ने समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर जोर दिया। उन्होंने समाज के इस वंचित वर्ग को देखभाल प्रदान करने में संस्थान के प्रयासों की सराहना की।

संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राधा कृष्ण धीमन ने लॉन्च के बारे में अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सह्रदयतापूर्ण और उचित स्वास्थ्य देखभाल मिले। इस इकाई की स्थापना हमारे समुदाय के सभी सदस्यों को गरिमा और सम्मान के साथ सेवा देने के हमारे समर्पण को रेखांकित करती है। क्लीनिक का संचालन एंडोक्रिनोलॉजी विभाग द्वारा किया जायेगा। एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सुशील गुप्ता ने इस प्रयास को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की। क्लीनिक में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, रिडक्शन मैमोप्लास्टी जैसी सर्जिकल प्रक्रियाएं, जननांग पुनर्निर्माण सर्जरी, परामर्श, मनोरोग सहायता और त्वचा विज्ञान सेवाएं शामिल हैं। प्लास्टिक सर्जरी और बर्न विभाग (प्रो. राजीव अग्रवाल, विभागाध्यक्ष), यूरोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांटेशन विभाग (प्रो. एम.एस. अंसारी, विभागाध्यक्ष), मनोरोग विभाग (डॉ. रोमिल सैनी), त्वचाविज्ञान और यौन रोग विभाग (डॉ. अजित कुमार) और माइक्रोबायोलॉजी विभाग (प्रोफेसर रुंगमेई एस.के. मराक, विभागाध्यक्ष) प्रमुख देखभाल प्रदाता हैं। आवश्यकता पड़ने पर अन्य चिकित्सा मुद्दों का निवारण संस्थान के अन्य विभागों द्वारा किया जाएगा। बता दें कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह होता है जिसकी लिंग पहचान जन्म के समय उसे दी गई लिंग पहचान से भिन्न होती है। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का सदियों पुराना एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास है।

13 नये मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने को लेकर एनएमसी में अपील

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मानकों में परिवर्तन के चलते एनएमसी की तरफ से प्रदेश के 13 नये मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराने का प्रस्ताव खारिज किये जाने के बाद शासन के निर्देश पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) में अपील की गई है। यह अपील एनएमसी एक्ट-19 की धारा 28 (5) के तहत की है। सितंबर 2023 में प्रदेश के 13 जिलों क्रमशः बुलंदशहर, औरैया, सोनभद्र, ललितपुर, चंदौली, सुल्तानपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, कानपुर देहात, कौशांबी, बिजनौर एवं पीलीभीत के नये मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 100 एमबीबीएस छात्रों के प्रवेश के लिए एनएमसी में एलओपी के लिए आवेदन किया था। ऐसे में एनएमसी द्वारा सभी नये मेडिकल कॉलेज में एलओपी के लिए निरीक्षण शुरू किया गया, जिसे 24 जून को समाप्त किया गया था।

सुनियोजित विकास को आगे बढ़ाने में सहायक होगी फैमिली आईडी

सीएम योगी ने की जिला घरेलू उत्पाद अनुमान (डीडीपी) 2022-23 पुस्तिका के आंकड़ों की समीक्षा

● उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ जिला घरेलू उत्पाद अनुमान उत्तर प्रदेश 2022-23 पुस्तिका के प्रकाशन के संबंध में अवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार फैमिली आईडी के माध्यम से लोगों के सुनियोजित विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। फैमिली आईडी के माध्यम से डाटा एकत्रीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। डाटा को बेहतर तरीके से एकत्र किया जाए तथा इसके अद्यतन डाटा को समय पर अपलोड कराया जाए। डाटा संग्रहण के कार्य में लगे लोगों का उचित प्रशिक्षण कराया जाए। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र का बेहतर डाटाबेस तैयार किया जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अनंत संभावना का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो वर्ष 2022-23 में 22.58 लाख करोड़ रुपए था। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत की वृद्धि से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार के विगत सात वर्षों के नियोजित प्रयासों के परिणामस्वरूप इसमें और वृद्धि की संभावना है। इस पुस्तिका में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी, जनपद की डीडीपी व प्रदेश में प्रतिशत अंश एवं जनपद व प्रदेश की वार्षिक वृद्धि, जनपद की प्रति व्यक्ति आय, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, जनपद और उत्तर प्रदेश की तुलनात्मक स्थिति जैसे आंकड़ों का समावेश किया जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला घरेलू उत्पाद अनुमान पुस्तिका के आंकड़ों को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों व कृषि विज्ञान केंद्रों को भी प्रेषित किया जाए तथा उनसे संवाद स्थापित करते हुए इन आंकड़ों के आधार पर शोध कार्य आगे बढ़ाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विलेज जीडीपी, डिस्ट्रिक्ट जीडीपी की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि हमारी पंचायतें व नगरीय निकाय हमारा आधार हैं। कृषि क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। कहा कि पंचायतों व नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। विगत सात वर्षों में उत्तर प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किये गये हैं तथा अर्बनाइजेशन भी तेजी से बढ़ा है। परिणामस्वरूप लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक आत्मनिर्भर समाज ही आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बीते 7 साल में हर क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। प्रदेश की कार्य संस्कृति में बदलाव स्पष्ट दिखाई देता है। देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अन्य राज्यों की तुलना उत्तर प्रदेश इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर्वाधिक बजट खर्च करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि तकनीक के समावेश, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था के कारण बीते 7 वर्षों में प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

अवैध उर्वरक फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

मोहनलालगंज। महेश खेड़ा में अवैध रूप से संचालित उर्वरक फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद कृषि विभाग ने फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

मोहनलालगंज के महेश खेड़ा गांव की मोड़ पर कुछ माह से अवैध रूप से रासायनिक खाद बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। एसडीएम बृजेश कुमार वर्मा की सूचना पर जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह ने 17 जुलाई को टीम के साथ छापेमारी कर चार दुकानों और गोदाम में 492 बैग एमओपी 150 बैग एनपीके व 40 बैग डीएपी बरामद की थी। जबकि 1390 बैग कच्चा माल व 41 बॉक्स कीटनाशी रसायन और बैग सिलने की मशीन भी बरामद की थी। छापेमारी के बाद दुकानों और गोदाम को सील कर टीम ने चाभी पुलिस को सौंप दी थी। डीएम की परमिशन मिलने के बाद जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह ने शुक्रवार को उर्वरक कारोबारी राघव गुप्ता के विरुद्ध मोहनलालगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। एसएचओ आलोक राव ने बताया केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।

एससीआर के गठन की अधिसूचना जारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश की योगी ने शुक्रवार को एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसका दायरा 27826 वर्ग किलो मीटर और आबादी 22941300 होगा। अपर मुख्य सचिव आवास डा. नितिन रमेश गोकर्ण ने इसके गठन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। एससीआर में कुल छह जिले होंगे। लखनऊ का 2528 वर्ग किलोमीटर, हरदोई का 5986, सीतापुर का 5743, उन्नाव का 4558, रायबरेली का 4609 और बाराबंकी जिले का 4402 वर्ग किलो मीटर दायरा इसमें शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया गया है। इसमें संबंधित जिलों के डीएम को सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही नौ और सदस्य होंगे। प्रमुख विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव पदेन सदस्य होंगे। मंडलायुक्त लखनऊ व अयोध्या सदस्य होंगे। प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन सदस्य होंगे। लखनऊ के मंडलायुक्त क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। राज्य राजनधानी क्षेत्र (एससीआर) की घोषणा से इन जिलों में बुनियासदी ढांचे के विकास, परिवनह और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। इन नई व्यवस्था का उद्देश्य लखनऊ के अलावा, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी क्षेत्रों में समन्वित विकास और बेहतर प्रशासनिक सेवाओं को सुनिश्चित करना है।

वाहन पोर्टल की सुविधा से मोबाइल नंबर अपडेट करा सकेंगे वाहन स्वामी

● चालान या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही से वाहन स्वामी खुद को रख सकेंगे अपडेट

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

वाहन स्वामियों को ऑनलाइन माध्यम से परिवहन की तमाम सेवाएं उपलब्ध कराने को तत्पर योगी सरकार ने अब एक और पहल की है। अब वो वाहन स्वामी, जिनके वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट न हो या गलत पड़ा हो, वे विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर सही करा सकते हैं। विभाग की ओर से वाहन स्वामियों को घर बैठे सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। वाहन स्वामी इसका लाभ लेते हुए अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं, जिससे कि चालान या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही से खुद को अपडेट रखा जा सके।

उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त (आईटी/प्रवर्तन) ए.के. सिंह ने कहा कि प्रवर्तन टीम द्वारा जांच के दौरान यह बात सामने आ रही है कि बहुत से वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर या तो गलत पड़ा है या अपडेट नहीं है। उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए वाहन स्वामी वाहन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करें और वाहन संबंधी सेवा चुनें। इसके बाद राज्य चुने और वाहन नंबर दर्ज करें और प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। दी गई सेवाओं में से मोबाइल नंबर अपडेट (आधार आधारित) विकल्प चुने और फिर फॉर्म में पंजीकरण संख्या, पूर्ण चेचिस नंबर, पूर्ण इंजन नंबर, पंजीकरण तिथि और फिटनेस/पंजीकरण की समाप्ति तिथि भरें और शो डिटेल बटन पर क्लिक करें। आधार नंबर, आधार में अंकित नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें, एग्री चेक बॉक्स पर क्लिक करें, इसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक कर अपनी डिटेल देखें। मोबाइल अपडेट बटन पर क्लिक करें और पोर्टल द्वारा प्रदर्शित सफल संदेश देखें। आपका मोबाइल नंबर अब वाहन पोर्टल पर अपडेट शो करेगा। अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) ने बताया कि यदि आधार कार्ड 85 प्रतिशत वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में अंकित डाटा के समान है तो ही मोबाइल नंबर अपडेट होगा। अन्यथा संबंधित कार्यालय में जाकर इसे अपडेट कराना होगा।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रगति समीक्षा बैठक सम्पन्न

लखनऊ। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सभागार में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, डॉ. उज्वल कुमार की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के परिक्षेत्रीय/ जनपदीय अधिकारी, प्राचार्य मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र और मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. उज्वल कुमार ने निर्देश दिए कि खादी बोर्ड एवं माटीकला बोर्ड द्वारा निर्धारित वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति तत्परता से की जाए और संबंधित सूचनाओं को पोर्टल पर अद्यतन किया जाए। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि प्रत्येक जनपद में विभाग द्वारा वितरित टूल किट्स का फीडबैक एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाए और पिछले वर्ष वितरित किए गए टूल किट्स का वितरण सुनिश्चित किया जाए।

दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री के इस्तीफे का लेटर सोशल मीडिया में वायरल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा में जारी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को उपचुनाव से पहले किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष राज्य मंत्री (दर्जा प्राप्त) सोनम किन्नर के इस्तीफे का लेटर सोशल मीडिया में वायरल हो गया। राज्यपाल को भेजे इस्तीफे में उन्होंने इसके पीछे लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के पीछे खुद को जिम्मेदार बताया है। हांलाकि उनके इस्तीफे की पुष्टि राजभवन ने नहीं की है।

राज्यपाल को भेजे इस्तीफे में सोनम चिश्ती ने लिखा है कि मैं सोनम चिश्ती (किन्नर) उपाध्यक्ष (दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री), किन्नर कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार, जवाहर भवन, प्रथम तल कमरा नं0 15 एवं 16, लखनऊ वर्तमान में हुए सामान्य लोकसभा चुनाव साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न जनपदों/ लोकसभा क्षेत्रों के आए परिणामों/ प्रदर्शन से आहत होकर हार की जिम्मेदारी लेती हूँ एवं मैं दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री रहते हुए जनता के बीच मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में असफल रही हूं।

इस कारण मैं अपनी अन्तर्रात्मा से व्यथित होकर सरकारी पद से त्याग पत्र दे रही हूं। इसके उपरान्त मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिये संगठन में कार्य करती रहूँगी एवं भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश द्वारा जो जिम्मदारी मिलेगी उसे मैं निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूँगी। कृपया मेरा त्यागपत्र स्वीकार करने की कृपा करें। वहीं सूत्रों का कहना है कि इधर सोनम चिश्ती का तीन वर्ष का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। ऐसे में कार्यकाल पूरा होने के नजदीक इस्तीफा देने के पीछे सरकार पर किसी तरह का दबाव बनाना भी एक कारण हो सकता है।

जल-संकट का समाधान पानी के संरक्षण से ही संभवःस्वतंत्र देव सिंह

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

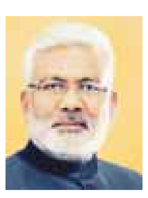

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि जल है तो कल है, जल की बर्बादी को रोकना होगा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल-संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती, हमारे कल को बचाने के लिए हमारे आज के जल को बचाना आवश्यक है।

स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को लखनऊ में जल शक्ति अभियान 'कैच द रेन-2024' नारी शक्ति से जल शक्ति थीम पर आधारित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यशाला में स्रोत स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान स्थिति एवं अवसर शीर्षक पर विभिन्न संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिक विचारधाराओं के साथ भूजल संरक्षण एवं संचयन की वैज्ञानिक विधाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यदि हम भविष्य की परिपाटी पर कुछ लिखकर जाना चाहते हैं तो हमें अपनी प्राकृतिक सम्पदाओं का संरक्षण करना होगा। बूंद-बूंद बचाना है, संकल्प को सफल बनाना है। जलशक्ति मंत्री ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहां कृषि जीवनयापन का मुख्य साधन है। जल की कमी के कारण हमारी खेती और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जल प्रबंधन करके जहां हम एक तरफ़ बाढ़ की विभीषिका से बचेंगे वहीं दूसरी तरफ़ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी उपलब्धता करायी जा सकेगी। हर साल, देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे की समस्या होती है, जबकि कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है। यह विरोधाभास हमें बताता है कि जल प्रबंधन की दिशा में हमें और भी मेहनत करनी होगी। हमें जल संचयन की प्रणालियों को सुधारने की आवश्यकता है ताकि हम वर्षा के पानी को सहेज सकें और इसे जल की आवश्यकता वाले समय में उपयोग कर सकें। जलशक्ति मंत्री द्वारा इस अवसर पर प्रदेश की नदियों, नहरों एवं जलाशयों को जीवित रखने तथा भूगर्भ जल संचयन हेतु सामुदायिक स्तर पर प्रयास किए जाने का आह्वान किया गया और वृहद् वृक्षारोपण अभियान के साथ भूजल प्रबन्धन विधाओं, भूजल स्रोतों की सुरक्षा, संरक्षण एवं जल के दुरूपयोग को रोकने के उपायों से जन समुदाय को जागरूक किया। 'कैच द रेन' अभियान का उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण करना और उसे संरक्षित करना है। इसका मुख्य उददेश्य बारिश के दौरान जल को संग्रहित करके भूजल स्तर को पुन: बढ़ाना और जल की कमी को दूर करना है।

औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित होगा हाथरस का सलेमपुर, ईपीसी मोड पर होगा निर्माण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के लिए प्रदेश में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विकास पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। प्रदेश के सभी औद्योगिक प्राधिकरणों में औद्योगिक विकास की विभिन्न योजनाओं को गति दी जा रही है। इस क्रम में, सीएम योगी के विजन अनुसार हाथरस के सलेमपुर को इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर विकसित करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई थी। अब इस कार्ययोजना को क्रियान्वित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने हाथरस के सलेमपुर की औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया को कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी की नियुक्ति और कार्यावंटन के जरिए पूरा किया जाएगा। यूपीसीडा द्वारा सलेमपुर के विकास कार्यों को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट व कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) माध्यम के जरिए दो फेज में कराया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 325.54 करोड़ रुपए व्यय होंगे तथा कार्यावंटन के बाद एजेंसी द्वारा 18 महीने की अवधि के भीतर सभी निर्धारित निर्माण व विकास कार्यों को पूर्ण करना होगा। सीएम योगी के विजन अनुसार तैयार की गई कार्ययोजना को क्रियान्वित करते हुए यूपीसीडा द्वारा सलेमपुर में 483 एकड़ क्षेत्र को फिलहाल इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर विकसित किया जाएगा। आगे जरूरत के अनुसार इस क्षेत्र को और प्रसारित भी किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मास्टर प्लान के अनुरूप पहले फेज में 7,99,899 स्क्वायर मीटर व दूसरे फेज में 3,28,572 स्क्वायर मीटर क्षेत्र को इंडस्ट्रियल प्लॉटेड एरिया के तौर पर विकसित किया जाएगा।

कोल आदिवासियों को एससी-एसटी में शामिल करने का केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग

● प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी को लिखा पत्र

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कोल आदिवासी विकास समिति ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में निवासरत आदिवासी जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित कराने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने हेतु उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी को सम्बोधित पत्र सौंपा।

कोल आदिवासी विकास समिति के अध्यक्ष जय नारायण कोल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कोल आदिवासी जाति की आर्थिक, सामाजिक स्थितियों से अवगत कराते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में जहां-जहां कोल आदिवासी निवासरत हैं वहां कोल आदिवासी जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने तत्काल प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोल आदिवासी जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल कराने हेतु भारत सरकार को अविलंब प्रस्ताव भेजने के लिए आग्रह किया। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र की प्रति संलग्न है।

समाज में भय व विद्वेष पैदा करने वाला है मुजफ्फरनगर पुलिस अधिकारियों का आदेशः कुंवर फतेह बहादुर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

रिटायर आईएएस एवं सामाजिक संस्था बहुजन भारत के अध्यक्ष कुंवर फतेह बहादुर ने कहा है कि प्रदेश में 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के क्षेत्र में आने वाले मार्ग पर दुकान व ठेला लगाने वालों के लिए पुलिस अधिकारियों के आदेश से समाज में भय और विद्वेष पैदा करने वाला है। पुलिस के इस आदेश से न केवल सामाजिक माहौल ख़राब होगा बल्कि राज्य में सांप्रदायिक स्थिति भी बिगड़ेगी। कुंवर फ़तेह बहादुर ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के रवैये से राज्य में सांप्रदायिक माहौल ख़राब होने की आशंका बढ़ेगी। इसके साथ ही इस पुलिसिया फरमान से समाज में जातीय विद्वेष भी बढेगा। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में यह भी ज्ञात नहीं है कि ये आदेश शासन स्तर पर लिया गया है या स्थानीय पुलिस अधिकारीयों द्वारा। यदि शासन स्तर से ये आदेश दिया गया होता तो ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू होती, जबकि दुकानदारों को अपनी दुकान व ठेले पर अपना नाम व मोबाइल नंबर प्रमुखता से लिखने का आदेश अभी केवल मेरठ और सहारनपुर मंडल में ही संभवत: लागू हुआ है।

संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि सम्पूर्ण कांवड़ मार्ग पर विभिन्न जातियों व सम्प्रदायों के लोगों की दुकानें लगतीं हैं, ऐसे में इस बात की आशंका है कि यदि कोई दुकान या ठेला अल्पसंख्यक अथवा दलित का है तो उसके व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों कांवड़ यात्री आते हैं और उनका व्यवहार आक्रामक होता है। वे छोटी-छोटी बातों पर किसी से भी लड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी कांवड़ यात्री का किसी अल्पसंख्यक या दलित समाज के दुकानदार से विवाद हो गया तो पूरे राज्य में सांप्रदायिक माहौल ख़राब होगा। साथ ही जातिगत आधार पर हिंसा होने की आशंका भी बढ़ेगी। कुंवर फ़तेह बहादुर ने कहा कि ऐसे मामले में अफवाह फैलाने वाले भी सक्रिय हो जाते हैं और असामाजिक और गैरजिम्मेदार लोगों द्वारा प्रदेश में हिंसा का माहौल पैदा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने वहां के जिला प्रशासन के साथ मिलकर ये निर्णय लिया है या ये पुलिस प्रशासन का अपना निर्णय है, लेकिन ये निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से अव्यवहारिक एवं अव्यवस्था फ़ैलाने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में साम्प्रदायिकता और जातीय आधार पर छोटी-छोटी बातों को लेकर असामाजिक और सांप्रदायिक तत्वों द्वारा मारपीट की जाती है, विशेषकर खानपान की दुकानों में यदि ये दुकानें अल्पसंख्यक व दलित वर्ग की हैं तो इन्हें ज्यादती का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि आज भी यूपी ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में किसी दलित के हैंडपंप से पानी भरने को लेकर, किसी दलित युवक के अपनी शादी में घोड़ी चढ़ने को लेकर उनके साथ मारपीट की घटनाएँ आम हैं, आज भी देश में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ छुआछूत की घटनाएं होती रहतीं हैं। ऐसी स्थिति में इन वर्गों द्वारा ठेला व दुकान लगाने वाले इन वर्ग के लोगों के साथ मारपीट की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में शासन-प्रशासन को गहन विचार-विमर्श करके निर्णय लेना चाहिए था। उन्हें इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और यदि जिला और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर कोई निर्णय लेते हैं तो ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना की आशंका कम होती है और अगर कोई घटना हो भी जाए तो उसे जल्दी ही नियंत्रित कर लिया जाता है।

बागवानी से बाग-बाग होंगे यूपी के बागवान

● सभी कृषि विश्वविद्यालयों में बनेंगे टिशू कल्चर लैब, रायबरेली में खुलेगा उद्यान महाविद्यालय

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

किसानों की खुशहाली शुरू से ही योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इस खुशहाली का मूलमंत्र है किसानों की आय में वृद्धि। यह कृषि विविधिकरण से ही संभव है। इसमें परंपरागत खेती के साथ बागवानी, सब्जी की खेती की सबसे अहम भूमिका है। 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के कारण उत्तर प्रदेश में इसकी भरपूर संभावना भी है। योगी सरकार इन संभावनाओं को परवान चढ़ाने की हर संभव कोशिश भी कर रही है। इसी क्रम में चंद रोज पहले राज्य मंडी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बागवानी फसलों के गुणवत्ता पूर्ण रोपण के लिए प्रदेश के चारों कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था मंडी परिषद द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार, रायबरेली में एक उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए।

विभागीय मंत्री दिनेश सिंह ने बताया कि उद्यान महाविद्यालय के लिए रायबरेली के हरचरनपुर के पडेरा गांव में जमीन चिन्हित की जा चुकी है। कृषि विभाग इसे उद्यान विभाग को ट्रांसफर भी कर चुका है। पहले चरण के काम के लिए पैसा भी रिलीज किया जा चुका है। इसमें डिग्री कोर्स के साथ अल्पकालीन प्रशिक्षण के कोर्स भी चलेंगे।उल्लेखनीय है कि योगी सरकार के लगातार प्रयास के नाते यहां के किसानों किसानों के लिए फलों एवं सब्जियों की खेती संभावनाओं की खेती बन रही है। सरकार की इस नई पहल से इस क्षेत्र की संभावनाएं और परवान चढ़ेगी। 2023 की कृषि वानिकी रिपोर्ट के अनुसार फलों एवं सब्जियों की खेती में एक दशक में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 7.2 फीसद से बढ़कर 9.2 हो गई। इसी क्रम में इनसे प्राप्त ग्रास वैल्यू आउटपुट (जीवीओ) 20.6 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये हो गया। दरअसल, इसमें योगी सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण एवं बाजार की मांग के अनुरूप खेती करने की अपील, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गुणवत्तापूर्ण पौधों का उत्पादन कर किसानों को न्यूनतम रेट में देना, संरक्षित तापमान एवं नमी नियंत्रित कर संरक्षित खेती को बढ़ावा एवं मंडियों के आधुनिकरण आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। मालूम हो कि फल एवं सब्जियों (शाकभाजी) की खेती और इनका प्रसंस्करण व्यापक संभावनाओं का क्षेत्र है। इन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर योगी सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही लगातार इनकी खेती को हर संभव प्रोत्साहन दे रही है। करीब दो साल पहले लगातार दूसरी बार योगी बनने के बाद ही अगले 5 साल के लिए इनकी खेती के क्षेत्रफल में विस्तार, उपज में वृद्धि और प्रसंस्करण के बाबत महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी विभाग के सामने रख दिया गया था। उसी के अनुरूप काम भी हो रहा है। लक्ष्य के मुताबिक 2027 तक बागवानी फसलों का क्षेत्रफल 11.6 फीसद से बढ़ाकर 16 फीसद तथा खाद्य प्रसंस्करण 6 फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद किया जाना है। इसके लिए लगने वाली प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे माल के रूप में फलों एवं सब्जियों की जरूरत होगी। हॉर्टिकल्चर में तय लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका गुणवत्तापूर्ण प्लांटिंग मैटिरियल (पौध एवं बीज) की है। इसके लिए सरकार तय समयावधि में हर जिले में एक्सीलेंस सेंटर, मिनी एक्सीलेंस सेंटर या हाईटेक नर्सरी की स्थापना करेगी। इस बाबत काम भी जारी है। 2027 तक इस तरह की बुनियादी संरचना हर जिले में होगी। ऐसी सरकार की मंशा है।

सरकार से मिले प्रोत्साहन एवं इन्हीं संभावनाओं के चलते पिछले 7 वर्षों में किसानों को प्रोत्साहित कर फलों एवं सब्जियों की खेती के रकबे में 1.01 लाख हेक्टेयर से अधिक और उपज में 0.7 फीसद से अधिक की वृद्धि की गई। किसानों को गुणवत्ता पूर्ण पौध मिलें, इसके लिए फलों एवं सब्जियों के लिए क्रमश: बस्ती एवं कन्नौज में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना हुई। नमी और तापमान नियंत्रित कर बेमौसम गुणवत्तापूर्ण पौध और सब्जियां उगाने के लिए इंडो इजराइल तकनीक पर ही संरक्षित खेती को बढ़ावा देने का काम भी लगातार जारी है।

बिजली चोरी का आरोप झेल रहे सेवानिवृत्त शिक्षक ने एमडी से लगाई न्याय की गुहार

● मानवाधिकार आयोग को भी पत्र भेजकर बताई आपबीती की निष्पक्ष जांच की मांग

संवाददाता। मोहनलालगंज

....भले सौ गुनहगार छूट जाएं लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नही मिलनी चाहिए.......कोर्ट और कानून भले ही बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस सिद्धांत को आदर्श मानते हों। लेकिन राजधानी में बिजली विभाग के अफसर अपना ही कानून चला रहे हैं। लिहाजा बेटे के नाम कनेक्शन के बावजूद बिजली चोरी की एफआईआर झेल रहे रिटायर्ड शिक्षक को ग्यारह दिन बाद भी बेगुनाही साबित करने के लिए भटकना पड़ रहा है। एक्सइएन से न्याय न मिलने से आहत पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक ने एमडी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है।

मोहनलालगंज के धनुवासांड गांव निवासी अभिषेक कुमार के घर 8 जुलाई को मॉर्निंग मास रेड करने पहुंची बिजली विभाग की टीम उनका कनेक्शन काटकर केबिल उतार लाई थी। सबस्टेशन पहुंचकर बिजली बिल की जमा रशीद दिखाने के बावजूद अधिकारियों ने अभिषेक के पिता रिटायर्ड शिक्षक सुंदरलाल पर बिजली चोरी का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करा दी। सुंदरलाल ने आरोप लगाया कि एक्सइएन ऑफिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी सुनवाई के बजाए उन्हें एक लाख छियान्नवे हजार से अधिक जुर्माने की नोटिस थमा दी गई। सुंदरलाल का आरोप है कि उन्होंने एक्सइएन एसके अग्रवाल से उन पर बेवजह एफआईआर दर्ज कराए जाने की शिकायत कि तो एक्सइएन ने कहा कि कनेक्शन चाहे जिसके नाम हो विभाग घर पर मिले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर करा सकता है। जिसे लेकर क्षुब्ध रिटायर्ड शिक्षक सुंदरलाल ने मध्यांचल डिस्कॉम के एमडी ऑफिस पहुंचकर अपना दर्द बयां किया है। सुंदरलाल ने बताया कनेक्शन के सारे दस्तावेज लेकर एमडी ऑफिस से उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया है।

रिटायर्ड शिक्षक सुंदरलाल का आरोप है कि बेगुनाह होने के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारियों ने बुढ़ापे में उन पर बेवजह बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज करा दी है। जिसे लेकर उनकी रातों की नींद छिन गई है। सुंदरलाल ने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजकर अधिकारियों की शिकायत की है। उन्होंने आयोग से स्वयं मामले की जांच कराकर उन पर दर्ज कराई गई एफआईआर रद्द कराने और अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रिटायर्ड शिक्षक सुंदरलाल ने बताया मोहनलालगंज खण्ड में डेढ़ हजार से अधिक बिजली कनेक्शन बिना मीटर के चल रहे हैं। जिनमें सैकड़ों मीटर खराब होने के बाद अब तक बदले नही जा सके हैं। वहीं कई सौ कनेक्शन ऐसे भी हैं जिन पर मीटर ही नही लगे हैं। लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ उनके बेटे के घर मीटर नही लगा पाकर रिटायर्ड शिक्षक पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज करा दी। जिसे लेकर उन्होंने पावर कार्पोरेशन के चेयरमैन और ऊर्जा मंत्री को भी पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है।

प्रमुख सचिव ने की जिला वृक्षारोपण समिति की समीक्षा बैठक

● वृक्षारोपण अभियान को बनाएं व्यापक जनसहभागिता कार्यक्रमः प्रमुख सचिव

संवाददाता। प्रयागराज

प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग एम देवराज की अध्यक्षता और प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार एवं प्रभागीय वनाधिकारी अरविंद कुमार यादव की उपस्थिति में शुक्रवार को विकास भवन के सभागार में कल होने वाले वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारियों के सम्बंध में जिला वृक्षारोपण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। प्रमुख सचिव ने कल होने वाले वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु की गयी तैयारियों के सम्बंध में उपस्थित सभी अधिकारियों से उनकी कार्ययोजना के बारे में पूछा।

उन्होंने उनके द्वारा वृक्षारोपण हेतु पौध उपलब्धता चयनित स्थलों चयनित स्थल की मिट्टी किस प्रकार की है और वहां किस प्रजाति के पौधों का रोपण करेंगे अग्रिम मृदा कार्य प्रत्येक चिन्हित स्थल पर कितने पौधों का रोपण किया जायेगा। वृक्षारोपण के बाद पौधों की देखभाल कैसे होगी आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए वृक्षारोपण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी सम्बंधित अधिकारियों से लक्ष्य के सापेक्ष पौध उठान की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए सभी अधिकारियों को अपने लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करते हुए अभियान को सफल बनाने के लिए कहा है।

प्रमुख सचिव ने बैठक में कहा कि वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल पर उन्हीं प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाये जो वहां पर आसानी से उग सके। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नहरों की दोनो पटरियों पर जामुन अर्जुन सीशम व अन्य ऐसे पौधों का रोपण किए जाने के लिए कहा है जो वहां आसानी से उग सके। उन्होंने बैठक में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को गौशालाओं में वृक्षारोपण कराये जाने के लिए कहा है। जिससे कि वहां छाया का प्रबंध भी हो सके। उन्होंने उद्यान विभाग नगर निगम डीसी मनरेगा से वृक्षारोपण की योजना के बारे में जानकारी लेते हुए व्यापक जनसहभागिता के माध्यम से वृक्षारोपण कराये जाने के लिए निर्देशित किया है।

उन्होंने वृक्षारोपण के बाद पौधों को बचाये रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन्हें गोद लिए जाने हेतु प्रेरित किए जाने के लिए कहा है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बच्चों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कराते हुए उसकी देखभाल किए जाने के लिए प्रेरित करने व जिन विद्यालयों में पौधरोपण के बाद सर्वाइवल ज्यादा हो उन्हें पुरस्कृत किए जाने के लिए भी कहा है। बैठक में उन्होंने कल होने वाले वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद भी जनपद के होटल हॉस्पिटल टोल प्लाजा मंदिर मस्जिद गुरूद्वारा मेडिकल स्टोर पर लोगो को इस माह उपहार स्वरूप पौधे दिए जाने की व्यवस्था करने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा कि इससे लोगों के अंदर वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता आयेगी और वे इन पौधों को अवश्य रोपित कर उनकी देखभाल करेंगे। उन्होंने वृक्षारोपण के इस महाअभियान को सरकारी कार्य के बजाय सामाजिक सहभागिता के रूप में लेते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराये जाने की अपील की। प्रभारी जिलाधिकारी गौरव कुमार ने वृक्षारोपण के बारे में सभी विभागों के द्वारा की गयी तैयारियों से अवगत कराते हुए कहा कि आपके निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इस वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया जायेगा।

उन्होंने कहा कि जनसहभागिता के माध्यम से वृक्षारोपण के बाद उनकी देखभाल व सुरक्षित बनाये रखने का कार्य किया जायेगा। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी भोलानाथ कनौजिया सहित अन्य सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

लाभार्थीपरक योजनाओं से पात्र लोगों को किया जाये लाभान्वितः जिलाधिकारी

संवाददाता। सोनभद्र

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शासन की विकास प्राथमिकता वाली योजनाओं की बिन्दुवार सीएम डैशबोर्ड पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, उन्होंने शासन के निर्देश के क्रम में महत्वपूर्ण योजनाओं, परियोजनाओं, सेवाओं की सम्बन्धित अधिकारियों से सीएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर बारी-बारी से समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से भवनों के निर्माण की प्रगति धीमी पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए यूपी सिडको व सीएनडीएस के एक्सीएन को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में उपस्थित न रहने पर आर0ई0डी0 के अधिशासी अभियन्ता को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये गये हैं, बन्धी प्रखण्ड द्वितीय राबर्ट्सगंज द्वारा निर्माण कार्य के धीमी प्रगति पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये जा रहे सड़कों के निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द ही पूर्ण करने के निर्देश दियें। शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की खराब प्रगति पाये जाने पर सुधार के निर्देश दिये।

पीएम कुसुम योजना की समीक्षा की, तो प्रगति की स्थिति काफी खराब है, जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि चिन्हित कृषकों के यहां शत-प्रतिशत सोलर पम्प स्थापित कराया जाये किसान सम्मान निधि में प्रगति खराब पाये जाने पर सम्बन्धित को सुधार के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने जिला पर्यटन अधिकारी को निर्माणाधीन परियोजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान श्रम निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि मातृत्व शिशु एवं बालिका श्रम योजना कन्या विवाह योजना सहायता के अन्तर्गत लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने की प्रगति की समीक्षा की गयी तो प्रगति धीमी पायी गयी, जिस पर जिलाधिकारी ने उप श्रमायुक्त पिपरी को निर्देशित करते हुए कहा कि एक सप्ताह के अन्दर लाभार्थियों से सम्बन्धित पत्रावलियों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लाभार्थीपरक योजनाओं से पात्र लोगों को लाभान्वित किया जाये।

सावन में मांस मछली की दुकानों पर पूर्ण रूप से रहेगी पाबंदी

सकलडीहा, चन्दौली। काशी विश्वनाथ मंदिर से सम्बद्ध स्वंय भू कालेश्वर नाथ मंदिर में सावन माह में हजारो शिवभक्त और कांवरिया दर्शन पूजन और जलाभिषेक करते है। शुक्रवार को एसडीएम अनुपम मिश्रा के निर्देश पर तहसील और पुलिस प्रशासन के अधिकारी संयुक्त रूप से बैठक करके दर्शन पूजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। चेताया कि मंदिर के आसपास या एक किलोमीटर के अंदर किसी प्रकार की मीट मांस की दुकान नहीं खुलेगा। निर्देश का अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। इसके साथ ही सुरक्षा और बैरिकेटिंग, साफ-सफाई और चिकित्सा शिविर सहित अन्य सुविधाओ को चुस्त-दुरुस्त रखने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। चतुर्भुजपुर में बाबा कालेश्वरनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। यहा सावन माह में काफी भीड़ उमड़ती है।आसपास के जिलों सहित बिहार प्रान्त से भी लोग कालेश्वरनाथ का दर्शन करने आते है। खासकर प्रत्येक सोमवार को आस्थावान महिला और पुरुषों का हुजूम उमड़ता है। बाबा का जलाभिषेक कर दर्शन पूजन करते है। कांवरिया गंगा घाट से जल लाकर बाबा का जलाभिषेक भी करते है। इस दौरान मंदिर के आसपास मेले जैसा दृश्य रहता है।

इनकी सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी न हो।इसके लिए तहसीलदार राहुल सिंह व बीडीओ केके सिंह पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सुरक्षा के लिए महिला व पुरुष कांस्टेबल के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती, बैरिकेटिंग, साफ-सफाई के लिए सफाईकर्मी, स्वास्थ शिविर, अग्निशमन वाहन व अस्थाई रूप से मंदिर परिसर में बिजलीं का कनेक्शन को लेकर निर्देशित किया गया। इसके साथ ही अधिकारियों ने कोई नई परम्परा शुरू न करने की बात कही।

जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकताः भूपेश चौबे

●क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण को लेकर विधायक ने डीएम से की वार्ता

संवाददाता। सोनभद्र

शुक्रवार को सदर विधायक भूपेश चौबे ने जनपद के जिलाधिकारी बी एन सिह से मुलाकात कर सदर विधानसभा क्षेत्र के विढ़मगंज कोन नकतवार होते हुए झारखंड की सीमा तक के मार्ग को चौडीकरण करने व चोपन कोटा खरौदी मार्ग को सीसी पेवमेन्ट मार्ग के सुदृढ़ीकरण करने को लेकर वार्ता करने के साथ ही निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर बैठक की। सदर विधायक श्री चौबे ने कहाकि उक्त मार्ग पर यातायात अधिक होने के कारण मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया है।
जिससें लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्ग पर उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेश के लोगों का भी बड़ी संख्या में आना जाना होता है मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ मे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आयोजित विंध्याचल मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान भी मुख्यमंत्री से कोन-खरौदी मार्ग, विढ़मगंज-कोन मार्ग, राबर्टसगंज-पन्नुगंज मार्ग स्थित रेलवे फाटक के पास रेल उपरगामी सेतु का निर्माण कार्य और नगर पालिका परिषद रावर्ट्सगंज क्षेत्र के ओवर ब्रिज के नीचे सुन्दरीकरण कार्य करायें जाने आग्रह किया था। जिसे कराये जाने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया था। सदर विधायक भूपेश चौबे ने कहाकि सरकार जन समस्याओं को लेकर गंभीर है बडे पैमाने पर जनहित से जुडे कार्य करायें गयें है। काफी कार्य चल भी रहा है जिसके पूरा होने के बाद लाभ भी आम जन मानस को मिलेगा।

इस दौरान सदर विधायक भूपेश चौबे नें पीएमजीएसवाई व लोक निर्माण विभाग के अधिकारीयों के साथ बैठक कर तत्काल उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराने का निर्देश देते हुए कहा कि उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कारवाई की जायेगी जो शासन की मंशा की अनुरूप कार्य करने में लापरवाही बरत रहे हैं।

सड़क निर्माण को लेकर सपा ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

सोनभद्र। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा के नेतृत्व में तेलगुड़वा-कोटा-कोन-कचनरवा मार्ग के जर्जर स्थिति को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। इस दौरान पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने कहा कि उक्त मार्ग वर्तमान सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के झूठे वादों का जीवंत प्रमाण है। आए दिन इस सड़क पर हादसे होते रहते हैं, इस मार्ग के मरम्मत के नाम पर भ्रष्टाचार होता चला रहा है। अब तक इस सड़क पर सैकड़ो लोग अपनी जान गवां चुके हैं, विगत कई वर्षों से पत्राचार किया जा चुका है किंतु भाजपा सरकार में शासन और प्रशासन द्वारा लगातार अनदेखी किया जा रहा है। ज्ञापन देने के दौरान छात्र संघ के नेता दीपू विजय शर्मा एवं अंकित कुमार समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष पवन पटेल समाजवादी यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष सत्यम पांडे चंदन कुमार कान्ता प्रसाद कनौजिया पारस यादव, विनय कुमार गौड़, संतोष कुमार, प्रदीप कुमार कनौजिया, संजय कुमार अकेला आतिश कुमार चंद्रवंशी कन्हैया कुमार कनौजिया समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।

केंद्र समन्वयकों के सहयोग से छात्रों की संख्या पहुंचेगी एक लाखः कुलपति

प्रयागराज। अध्ययन केन्द्र समन्वयक विश्वविद्यालय की रीढ़ हैं। केंद्र समन्वयकों के सहयोग से हम विश्वविद्यालय की छात्र संख्या को शीघ्र एक लाख तक पहुंचा सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा विविधता से परिपूर्ण है। यहां किन्नर जेल बन्दी ग्रामीण नौकरी पेशा लोगों के लिए कई तरह की सुविधा उपलब्ध है। विश्वविद्यालय कौशल विकास पर आधारित कई शैक्षिक कार्यक्रमों की शिक्षा युवाओं का प्रदान कर रहा है। यह बातें राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के वाराणसी क्षेत्रीय केन्द्र से सम्बद्ध अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य एवं समन्वयकों की शुक्रवार को संत अतुलानंद कान्वेंट स्कूल में आयोजित कार्यशाला में उपस्थित मुख्य अतिथि कुलपति प्रो सत्यकाम ने कहीं। प्रो सत्यकाम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ज्ञानात्मक अध्ययन के साथ ही कौशल का भी अध्ययन कर सकते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय कौशल युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। विद्यार्थियों के पास कौशल युक्त शिक्षा होगी तो वह नौकरी के लिए दर दर नहीं भटकेंगे। कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय कौशल युक्त शिक्षा प्रदान कर विद्यार्थियों को सशक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर नामांकन अभिप्रेरण एवं प्रतिपुष्टि विषयक कार्यशाला में विचार व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रभारी प्रो जय प्रकाश यादव ने दूरस्थ शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय एनईपी 2020 के अंतर्गत सभी शैक्षिक कार्यक्रम संचालित कर रहा है। कार्यशाला में परीक्षा नियंत्रक डी पी सिंह ने कहा कि अध्ययन केन्द्रों पर भेजे जाने वाले अंक पत्रों को छात्रों को यथा समय वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ शिक्षार्थियों को अवश्य मिलना चाहिए।

डीएम की अध्यक्षता में हुईं वृक्षारोपण अभियान व आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा बैठक

संवाददाता। अंबेडकर नगर

जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा विभागवार ऑनलाइन, मुख्यमंत्री संदर्भ समेत अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया गया।

उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी विभाग में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आईजीआरएस का निस्तारण ससमय गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए और भविष्य में ध्यान रखा जाए कि डिफाल्टर संदर्भ न होने पाए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यालयाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि आख्या अपलोड करने से पहले आप सभी स्वयं से देखें बिना देखें कोई आख्या अपलोड न किया जाए। अन्यथा की स्थिति में कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिकायतकर्ता से संबंधित अधिकारी निस्तारण से पूर्व वार्ता करें। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आइजीआरएस को गंभीरता से लेते हुए साथ समय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सी श्रेणी के संदर्भो की समीक्षा कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान डीएफओ डॉ उमेश तिवारी,मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजकुमार,अपर जिलाधिकारी डॉ.सदानंद गुप्ता, उप जिलाधिकारी, तथा संबंधित विभाग के अधिकारी ,कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

इसके साथ-साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 'एक पेड़ मां के नाम' 'पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ' वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत 20 जुलाई को होने वाले वृहद वृक्षारोपण के संबंध में विभागवार समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। वृहद वृक्षारोपण 20 जुलाई को लगाए गए पौधों के जियो टैगिंग के बारे में भी अवगत कराते हुए जियो टैगिंग से संबंधित मैन्युअल उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त मेरी लाइफ पोर्टल तथा हरितिमा अमृत वन ऐप 3.6 पर लगाए गए पौधों की फोटो अपलोड करने हेतु जानकारी दी गई। हरितमा एप्स 3.6 वर्जन सभी जिला वृक्षारोपण समिति अधिकारी इस एप्स को डाउनलोड कर ले ताकि अन्य विभागों का जिओ ट्रैकिंग किया जा सके। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि गौ आश्रय स्थलों पर वृक्षारोपण कराएं।

जिलाधिकारी द्वारा सभी से इस वृक्षारोपण जन अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने एवं लगाए गए पौधों की सिंचाई व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

धरहरा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का हुआ शुभारम्भ

सकलडीहा, चन्दौली। विकास खंड का धरहरा गांव में नित्य प्रतिदिन विकास के नये आयाम लिखे जा रहे है। शुक्रवार को प्रधान श्वेता सिंह की पहल पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया गया। सीएचसी अधीक्षक डा. संजय यादव औरप्रधान प्रतिनिधि अमित सिंह ने फीताकाटर उद्घाटन किया।यहां पर गर्भवती महिलाओं की पूर्ण जांच के साथ आसपास के गांव के ग्रामीणों को प्राथमिक चिकित्सा का निःशुल्क सहुलियत मिलेगी। मिशन कायाकल्प के तहत शुरू किय गया स्वास्थ्य सुविधा को लेकर ग्रामीणों में हर्ष है। धरहरा में खेल स्टेडियम से लेकर दिव्यांग मानसिक मंदित विद्यालय सहित विभिन्न प्रकार की विकास की कवायत चल रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को मिशन कायाकल्प के तहत धरहरा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया गया। जहां पर गांव की महिलाओं को जनरल ओपीडी, सुगर, बीपीए,एनसीडी स्क्रीनिंग, प्रसव पूर्व की सभी जांच,टेलीकन्सल्टेशन(ई-संजीवनी ओपीडी), निशुल्क मेडिसिन, होमोग्लोबिन की जांच सहित 30 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा।

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 56 टीबी मरीजों को मिली पोषण पोटली

मीरजापुर। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जनपद के नरायनपुर विकासखंड कार्यालय सभागार में दिनांक 19 जुलाई 2024 को 56 टीबी मरीजों को पोषण पोटली, एवं प्लास्टिक बाल्टी भेंट करते हुए गोद लेने कार्यक्रम चुनार एसडीएम (न्यायिक) संजीव कुमार यादव के उपस्थिति में किया गया। उपरोक्त आयोजित कार्यक्रम में होप वेलफेयर ट्रस्ट एवं मुकूल माधव फाउंडेशन वाराणसी द्वारा 51 टीबी मरीज तथा चुनार पीएचसी प्रभारी डाक्टर राकेश कुमार पटेल द्वारा 5 टीबी मरीजों को भुना चना, मूंगफली दाना, सत्तू, सोयाबीन, गुड़, बिस्कुट, साबून की पोटली के साथ-साथ प्लास्टिक बाल्टी का वितरण करते हुए उन्हें आगामी पूरे इलाज अवधि तक सहयोग देने हेतु गोद लेने का सराहनीय कार्य किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि रूप में आए एसडीएम चुनार द्वारा होप वेलफेयर ट्रस्ट के इस मानवीय कार्य की सराहना एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मरीजों से कहा गया कि आप सभी अपने खान-पान पर विशेष ध्यान रखें और नियमित दवा का सेवन करें जिससे कि आप शीघ्र स्वस्थ होकर अपनी जिम्मेदारीयों का पूर्व की भांति अच्छे से निर्वहन कर सकें। चुनार पीएससी प्रभारी डॉक्टर राकेश कुमार पटेल द्वारा ट्रस्ट द्वारा चुनार क्षेत्र में विगत कुछ माह से लगातार किए जा रहे ऐसे सहयोग की सराहना करते हुए मरीजों को सुझाव दिया कि टीबी के दवा सेवन में एक दिन भी गैप नहीं होनीं चाहिए, उन्होंने कहा कि यह रोग कोई असाध्य रोग नहीं है यदि व्यक्ति अच्छे पोषण युक्त खान-पान वह समय से दवा का सेवन करता है तो जल्द स्वस्थ हो जाता है। डाक्टर पटेल ने कहा कि टीबी मरीज को थूकते छिंकते और खांसते समय मुंह पर रूमाल या गमछा का सेवन अवश्य करना चाहिए, जिससे अन्य कोई दूसरा टीबी के वैक्टिरीया से प्रभावित होने से बचा रहे।

दूसरे रेफरेंस पर श्रम अदालत की कार्यवाही पर रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फार्मास्युटिकल कंपनी मेसर्स सनोफी इंडिया लिमिटेड के औद्योगिक विवाद को लेकर श्रम अदालत में एक रिफरेंस विचाराधीन रहते उन्हीं बिंदुओं और राहत को लेकर दुबारा भेजे गये रेफरेंस के तहत श्रम अदालत प्रयागराज में चल रही केस कार्यवाही पर रोक लगा दी है और विपक्षी संख्या पांच जसमीत सिंह श्रमिक को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सी के राय ने कंपनी के अधिवक्ता सुनील कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। इनका कहना था कि इससे पहले भी सरकार ने रेफरेंस संदर्भित किया है और उसी के समान दुबारा रेफरेंस भेजने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। इसलिए 2 जनवरी 24 को भेजा गया रेफरेंस रद् किया जाए। यह सी पी सी की धारा 10 के तहत प्रांगन्याय रेस्जुडीकेटा से बाधित है। हालांकि कि विपक्षी वकील ने इसका विरोध किया कहा औद्योगिक विवाद में सी पी सी के उपबंध लागू नहीं होंगे। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और जवाब मांगा है।

मीरज़ापुर जिले में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

संवाददाता। मीरज़ापुर

मीरजापुर जनपद में वर्तमान में स्वास्थ्य व्यवस्थायें चरमरा गई है। तथा मण्डलीय चिकित्सालय हो या ट्रामा सेंटर हर जगह दुर्व्यवस्था फैली हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण स्वास्थ्य सेवायें पूरे जनपद में फेल साबित हो रही है। पूरे जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की उदासीनता के कारण झोलाछाप डाक्टरों का आतंक व्याप्त है। साथ ही फर्जी ढंग से संचालित हास्पिटल, अल्ट्रासाउण्ड एवं पैथालाजी सेंटर से गरीब जनता त्राहि त्राहि कर रही है। उक्त सभी समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। तथा मांगो से संबंधित ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी मिर्जापुर एवं मंडला आयुक्त विंध्याचल मंडल कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी श्री शिवाकांत श्रीवास्तव को सौंपा गया।

प्रदर्शन के पश्चात उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव सुनील कुमार पांडे राजनेता ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मीरजापुर द्वारा झोलाछाप डाक्टरों के विरूद्ध तीन वर्षो से कोई भी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करायी गयी। उन्होंने अपने संबोधन ने कहा कि 2021 के पूर्व तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा झोलाछाप डाक्टरों के विरूद्ध 45 एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया था। परंतु आम जनता के प्रति लापरवाही रखने वाले डॉक्टरों व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा जनता के सुविधाओं की अनदेखी कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बी सिंह ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि मिर्जापुर जनपद में आईसीयू केंद्र बने हुए हैं लेकिन वहां कोई भी डॉक्टर का उपलब्ध नहीं रहता है मिर्जापुर जनपद के किसी भी व्यक्ति को यदि कार्डियक या हार्ट अटैक से संबंधित बीमारी होती है तो उसे तत्काल रेफर कर दिया जाता है कहने को तो मेडिकल कॉलेज खुल चुका है मंडलीय चिकित्सालय है लेकिन सुविधाओं का टोटा है।

दस मिनट लेट पहुंचने पर मरीज को बाहर निकाला

मड़िहान, मीरज़ापुर। मड़िहान क्षेत्र के सीएचसी व पीएचसीयों की बात करें तो यहां का रवैया मरीजों को लेकर बेहद खराब है। क्षेत्र के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर डाक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा मरीजों के साथ बुरा बर्ताव करते आये दिन देखा जा सकता है। ग्राम गंगा पुर निवासी राजेश अपनी आपबीती बताते हुए बताया कि। बृहस्पतिवार को 2.10 बजे मड़िहान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपने बेटे सत्यम के हाथ का एक्स रे कराने पहुंचे तो एक्स रे मशीन के आपरेटर के मौजूदगी के बाबजूद भी एक्स रे, मशीन नहीं चालू किया गया।सवाल करने पर बताया गया कि आप 10 मिनट लेट हो गए हो । मेरा बेटा एक्स रे मशीन रूम के समाने हाथ फैक्चर होने के कारण चीखता चिल्लाता रहा कोई स्वास्थ्य कर्मी का दिल नहीं पिघला। बता दें कि मड़िहान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आये दिन ऐसा मामला आता रहता है। बेखौफ स्वास्थ्य कर्मी कभी मरीजों को जांच के लिए बाहर का दरवाजा दिखाते हैं कभी दवा के लिए। अकसर मरीजों से हाथापाई भी की जाती है।

सावन माह में घर बैठे स्पीड पोस्ट से प्राप्त करें सोमनाथ मंदिर का प्रसाद

पोस्ट मास्टर जनरल केके यादव

प्रयागराज। सावन में शिव आराधना की विशेष महिमा है। हर किसी की इच्छा होती है कि वह भगवान शिव के ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूप का दर्शन और आशीर्वाद स्वरुप प्रसाद पा सके। परन्तु कुछ श्रद्धालु चाहकर भी दर्शन नहीं कर पाते। अब ऐसे श्रद्धालुओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से लोग देश के किसी भी कोने में घर बैठे गुजरात के जूनागढ़ जिला अंतर्गत प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ आदि ज्योतिर्लिंग मंदिर का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। सावन माह में डाक विभाग ने इसके लिए विशेष प्रबंध किए हैं। यह जानकारी गुजरात के अहमदाबाद परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने दी। उन्होंने बताया कि सावन माह 22 जुलाई से आरम्भ हो रहा है। बताया कि श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को घर बैठे प्रसाद उपलब्ध कराने हेतु भारतीय डाक विभाग से एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत कोई भी श्रद्धालु मैनेजर सोमनाथ ट्रस्ट प्रभास पाटन जिला जूनागढ़ गुजरात 362268 को 270 का ई मनीऑर्डर भेजकर स्पीड पोस्ट द्वारा प्रसाद मँगा सकता है। इस ई मनीऑर्डर पर प्रसाद के लिए बुकिंग अंकित करना होगा। इसके बाद श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा द्वारा संबंधित श्रद्धालु को 400 ग्राम का प्रसाद का पैकेट स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जायेगा। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि इस प्रसाद में 200 ग्राम बेसन लड्डू 100 ग्राम तिल की चिक्की और 100 ग्राम मावा की चिक्की रहेगी। यह प्रसाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से श्रद्धालु के घर पर शीघ्रता से वितरित किया जायेगा।

कर्नाटक सरकार

विवादास्पद विधेयक

कर्नाटक सरकार के विवादास्पद विधेयक में स्थानीय लोगों को 'आरक्षण' का प्राविधान किया गया था, लेकिन आईटी उद्योग की कठोर प्रतिक्रिया के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कर्नाटक सरकार को निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने वाले विधेयक को उद्योग जगत से तीखी प्रतिक्रिया के बाद रोकना पड़ा है। सरकार राज्य विधानसभा में रखने के पहले इस पर पुनर्विचार करेगी। यह निर्णय राज्य कैबिनेट द्वारा विधेयक स्वीकार करने के कुछ ही घंटे के भीतर आया जिसमें निजी क्षेत्र में प्रबंधन के पदों पर 50 प्रतिशत तथा गैर-प्रबंधन पदों पर 75 प्रतिशत कन्नड़वासियों को आरक्षण का प्राविधान था। कर्नाटक 'स्टेट इम्प्लायमेंट आफ लोकल कैंडीडेट्स इन द इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ एंड अदर स्टैब्लिशमेंट बिल, 2024' को विधानसभा में गुरुवार को रखा जाना था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तथा उनके मंत्रियों ने विधेयक की प्रशंसा करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि यह उनके 'कर्नाटक समर्थक' दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य 'कन्नड़वासियों का कल्याण सुनिश्चित करना' है। लेकिन विधेयक का आईटी उद्योग की ओर से भारी विरोध हुआ और उसने इसकी आलोचना की। उसका तर्क था कि इससे बैंगलुरू में टेक्नोलोजी क्षेत्र प्रभावित होगा तथा कर्नाटक में आईटी उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विधेयक के पीछे राज्य के निवासियों में भारी बेरोजगारी को कारण बताया गया था। इसका उद्देश्य कर्नाटक में रोजगार के अवसरों में स्थानीय प्रतिभा को प्राथमिकता देना था।

लेकिन उद्योगपतियों का मानना था कि स्थानीय लोगों के लिए

'आरक्षण' की व्यवस्था से कंपनियों को उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा को नौकरी देने में बाधा आएगी जिससे उनकी प्रतियोगिता क्षमता तथा उत्पादकता पर विपरीत असर पड़ सकता है। वैसे भी इस विधेयक के क्रियान्वयन में विधिक व संवैधानिक मुद्दे सामने आते। यह विधेयक समानता और स्वतंत्र आवागमन का अधिकार बाधित करता जिनको भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस कारण इसके सामने अदालती बाधाएं आतीं और कानूनी दांवपेंच लंबे समय तक चलते। इसके साथ ही प्रस्तावित विधेयक से क्षेत्रवाद और सामाजिक तनाव बढ़ने की आशंका थी। आशंका थी कि ऐसी नीति से स्थानीय व गैर-स्थानीय के बीच विभाजन पैदा होगा। इससे समाज में विघटन तथा संभवत: टकराव पैदा हो सकता है। फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स-फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में कुल बेरोजगारी दर 2.7 प्रतिशत है जो 4.2 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम है। लेकिन इन आंकड़ों से स्थानीय लोगों की कम रोजगार प्राप्त करने की क्षमता छिप जाती है। लेकिन इसे ठीक करने के लिए लोकरंजक उपाय सर्वोत्तम समाधान नहीं हैं। नौकरियों में आरक्षण को अनिवार्य बनाने के बजाय सरकार को स्थानीय लोगों में शिक्षा और कौशल बढ़ाने पर केन्द्रित विकास कार्यक्रम चलाने चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा बेहतरीन व्यावसायिक प्रशिक्षण देने से स्थानीय नौजवानों का सशक्तीकरण होगा तथा वे रोजगार बाजार में प्रभावी ढंग से प्रतियोगिता कर सकेंगे। हालांकि, वापस लिया विधेयक अलग स्वरूप में वापस लाया जा सकता है। विधेयक को ठंडे बस्ते में डालने के गंभीर राजनीतिक प्रभाव होंगे। कर्नाटक सरकार ने फिलहाल आईटी उद्योग व अन्य बिजनेसों से टकराव बचा लिया है, पर रोजगार के अवसरों की प्रतीक्षा करने वाला उसका वोटबैंक प्रभावित हो सकता है।

अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा

डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ हमला देश में उथलपुथल वाला राजनीतिक परिवेश रेखांकित करता है। यह अमेरिकन लोकतंत्र और समाज के लिए चिन्ताजनक है।

नीलांत इलांगमुवा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

क्या संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है? इस वर्ष के प्रारम्भ में आई एलेक्स गारलैंड की हालिया फिल्म 'सिविल वार' टकराव का एक काल्पनिक लेकिन भयावह परिदृश्य प्रदर्शित करती है। इससे हालिया दशकों में अमेरिका द्वारा शुरू किए युद्धों के परिणाम सामने आते हैं जिनका लक्ष्य अपना वर्चस्व स्थापित करना था, लेकिन अब देश में इसके अशुभ संकेत दिख रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेंनसिलवानिया के बटलर में आयोजित रैली में हत्या का प्रयास एक खतरनाक मुद्दा सामने लाता है। इस घटना के कारण अनेक कथित षडयंत्रों की चर्चा हो रही है जिनसे सीक्रेट एजेंसियों के कामकाज पर सवाल उठता है, जिनके प्रमुखों ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप की आलोचना की थी। एक पुलिस स्नाइपर ने शूटर थामस मैथ्यू क्रुक्स की फोटो लगभग आधे घंटे पहले खींची थी, जब इस 20 वर्षीय युवा ने ट्रंप पर रैली के दौरान गोली चलाई। इससे हत्या का यह प्रयास रोकने की अनेक विफलतायें सामने आती हैं। इस हमले के बावजूद ट्रंप का राजनीतिक कद मजबूत हुआ है।

उन्होंने रिपब्लिकन सिनेटर जेडी वांस को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अपना सहयोगी चुना है। वांस एक समय ट्रंप के मुखर आलोचक थे, पर अब वे उनके मजबूत समर्थक बन गए हैं तथा उनकी व उनकी नीतियों की मजबूत पैरोकारी कर रहे हैं। ट्रंप का कान छूती निकली गोली के बाद ट्रंप का राजनीतिक विमर्श बदल गया है और घायल होने के बावजूद वे और मजबूत हुए हैं। हालांकि, यह आश्चर्यजनक हमला अमेरिका में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक हिंसा के इतिहास का नवीनतम प्रकरण है। यह परिघटना अमेरिका के राष्ट्र बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या सबसे पहले हुई थी जिनको 1865 में जान विल्किस बूथ ने गोली मारी थी। गृह युद्ध में लिंकन द्वारा 'अश्वेत अधिकारों' के समर्थन का परिणाम उनकी 'मुक्ति घोषणा' के रूप में सामने आया था और यही उनकी हत्या के पीछे प्रमुख कारण था। इसके बाद राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड, विलियम मैक्किनले और जान. एफ कैनेडी भी ऐसी हिंसा का शिकार हुए थे। गारफील्ड की हत्या 1881, मैक्किनले की 1901 व कैनेडी की 1968 में हुई थी।

इनमें से प्रत्येक हत्या ने देश और उसकी राजनीतिक संरचना पर व्यापक प्रभाव डाला था। राजनीतिक हिंसा केवल राष्ट्रपतियों तक सीमित नहीं थी। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में राबर्ट एफ. कैनेडी व जार्ज सी. वैलेस पर भी निशाना लगाया गया था। कैनेडी की 1968 में हिंसा के साथ ही वैलेस 1972 में लकवे का शिकार हुए थे। जेराल्ड फोर्ड व रोनाल्ड रीगन जैसे राष्ट्रपतियों को कई बार हत्या के प्रयासों का सामना करना पडा था। इससे अमेरिकन राजनीति में हिंसा की धमकी स्पष्ट होती है। अमेरिका आजकल इस तथ्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण बन गया है कि जब नीति निर्माता बाहरी मामलों पर ज्यादा ध्यान देते हुए आंतरिक मुद्दों की अनदेखी करते हैं तो राज्य का ढांचा कमजोर हो सकता है। उदाहरणार्थ, 'फेंटानिल संकट' अमेरिकी समुदायों को प्रभावित कर रहा है और इके चलते छोटे बच्चे और शिशु लगातार इस 'ओपायड' का शिकार होते जा रहे हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार हेरोइन से 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। देश में पैदा हुआ यह आंतरिक संकट यूक्रेन और इसराइल को गोला बारूद व उत्कृष्ट हथियारों के निर्यात से नहीं रोका जा सकता है। ऐसे समाजों में समस्याओं का मुख्यकारण केवल संस्थान न होकर प्रमुख मूल्यों का क्षरण भी होता है। एक समग्र व व्यापक मूल्य व्यवस्था के अभाव में राजनीतिक प्रबंधन बहुत कठिन हो जाता है। यह द्वंद्व ऐसे समय पैदा होता है जब प्रगति से नए मूल्यों की मांग पैदा होती है, जबकि प्रमुख मूल्य बनाए रखना स्थायित्व व सद्भावना के लिए जरूरी होता है। इस संतुलन की अनदेखी करने से समाज में अराजकता तथा नैतिक संकट की स्थिति पैदा होती है। डूबते सूरज की तरह इस अपरिहार्य क्षरण को केवल शक्ति से नहीं रोका जा सकता है।

अमेरिका में पैदा राजनीतिक परिवेश उसकी वैश्विक कार्रवाइयों का परिणाम है और अनेक अभूतपूर्व घटनाओं के माध्यम से यह अवश्यंभावी पतन का संकेत देता है। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से जारी उन नीतियों का उत्पाद हैं जो अक्सर घरेलू प्रभावों की अनदेखी से पैदा होते हैं। वे अमेरिकन राजनीति में कारणों के बजाय एक लक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अमेरिकन जनता की कीमत पर दूसरे देशों का शोषण करने के इतिहास से सामने आया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि राजनीतिक हिंसा में शामिल होना एक विकृत गतिविधि है जिसके नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। किसी का जीवन छीनना नैतिक रूप से पूर्णत: गलत है, भले ही उसकी भूमिका तथा गलतियां चाहे जो हों। ट्रंप की हत्या का प्रयास अनेक सवाल खड़े करता है जिनके जवाब नहीं दिए गए हैं। इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि 'गनशाट डिटेक्टर्स' का रैली में प्रयोग किया गया था, जबकि ऐसे डिटेक्टर तेजी से शूटर का पता लगा सकते हैं। शूटर थामस क्रुक्स ने ऐसी बंदूक का प्रयोग किया जिसे विधिक रूप से उसके पिता ने विधिक रूप से खरीदा था। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या बंदूक खासतौर से उसके लिए खरीदी गई थी क्योंकि पेंसिलवानिया के कानून 20 वर्षीय लोगों को बंदूक खरीदने का अधिकार देते हैं।

खबरों के अनुसार शूटर की पहचान उसके डीएनए से हुई, इसका अर्थ है कि परिवारी सदस्यों ने नमूने दिए थे। खबरों से यह भी पता चलता है कि बंदूक का सीरियल नंबर छिपाने के कोई प्रयास नहीं किए गए थे और शूटर ने हाल ही में 50 राउंड 5.56 एमएम गोलियां खरीदी थीं। प्राथमिक एकास्टिक प्रमाणों से संकेत मिलता है कि ट्रंप पर निशाना लगाने में अनेक शूटरों का प्रयोग किया गया था। खबरों के अनुसार, शुरुआती गोली शूटर की स्थिति से चलाई गई थी, जबकि बाद में अज्ञात स्रोतों से भी गोलियां चलाई गईं। सीक्रेट सर्विस स्नाइपरों द्वारा खतरे को समाप्त करने के लिए एक गोली चलाई गई, जबकि एकास्टिक प्रमाणों से इसमें असंगति दिखाई देती है। इससे घटना की और गंभीरता से जांच की आवश्यकता उजागर होती है। एक बीस वर्षीय युवा द्वारा तोड़ी गई सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं जिसके चलते वह ट्रंप की रैली के निकट एक छत तक पहुंच गया और उसने अनेक गोलियां चलाईं। प्रमुख शूटर के तौर पर थामस मैथ्यू क्रुक्स की पहचान की गई है, लेकिन एक संभावित दूसरे शूटर का अनुमान भी लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि क्रुक्स एक अकेला व्यक्ति था और सोशल मीडिया पर उसकी कोई उपस्थिति नहीं थी। ऐसे में उसकी अप्रत्याशित भूमिका तथा उसके वाहन में बरामद हुए विस्फोटकों से घटना की और विस्तृत जांच की आवश्यकता उजागर होती है। रैली की सुरक्षा की आलोचना में खासकर बिल्डिंगों की अनुपयुक्त कवरेज पर ध्यान दिया जा रहा है जिसे शूटर को सीधे ट्रंप को देखने का मौका मिला। यह गंभीर सुरक्षा विफलता का उदाहरण है। ये कमियां सुरक्षा प्रोटोकालों में गंभीर गड़बड़ियों का संकेत देती हैं जिससे सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की आवश्यकता उजागर होती है।

इसके साथ ही यह कहना भी जरूरी है कि राजनीतिक हिंसा से विरले ही उन मुद्दों का समाधान होता है जिनके समाधान की आशा इससे की जाती है। ऐतिहासिक रूप से ऐसी हिंसा से केवल विभीषिका के दुष्चक्र पैदा होते हैं और वे उन लक्ष्यों को नुकसान हीं पहुंचाते हैं जिनको हिंसा के पैरोकार प्राप्त करना चाहते हैं। अमेरिकन संस्कृति में फैल रही आक्रामकता ने अमेरिका की संस्कृति और आध्यात्मिक विकास को घातक रूप से धक्का दिया है। इससे स्वयं लोकतंत्र को भारी नुकसान होता है। लोकतंत्र जहां लोगों को परंपरागत बाधाओं से मुक्ति दिलाता है वहीं यह आत्म-नियंत्रण व आत्म-मूल्यांकन की आवश्यकता भी उजागर करता है। विडंबना है कि परंपरागत पश्चिमी मूल्यों के क्षरण के कारण इसमें भारी बाधा आई है। सामाजिक मूल्य व्यवस्था की वास्तविक निर्देशक शक्ति के बिना किसी देश की राज्य संरचना अपरिहार्य रूप से विफल हो जाती है, जबकि यह व्यक्तियों के निर्णय तय करने में महत्वपूर्ण होती है। सामूहिक विचारों के ध्वस्त होने का सामाजिक संस्थानों व व्यवहारों से निकट संबंध है।

ट्रंप पर जानलेवा हमला अमेरिका में उन नीतियों की समीक्षा का अवसर देता है जो लफ्फाजी के साथ ही राजनीतिक हिंसा को सामान्य बना रही हैं।

सूचनाधिकार कानून के समक्ष चुनौतियां

> नई सरकार के गठन के बावजूद, रिक्तियां अभी भी खाली हैं, जिससे देरी बढ़ रही है और बचे हुए कुछ आयुक्तों पर बोझ बढ़ रहा है।

प्रियदर्शी दत्ता
(लेखक, स्वतंत्र शोधकर्ता हैं)

पिछले साल 13 सितंबर को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19 (3) के तहत इस स्तंभकार की दूसरी अपील स्वीकार की थी। अपील में सूचना देने से इनकार करने के लिए सीपीआईओ पर जुर्माना लगाने के अलावा अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कुछ प्रासंगिक सुझाव भी शामिल थे। हालांकि, 6 नवंबर को उस विशेष मंत्रालय के मामलों को देखने वाली सूचना आयुक्त सुश्री सरोज पुन्हानी अपने कार्यकाल के अंत में सेवानिवृत्त हो गईं। उसी दिन एक अन्य सूचना आयुक्त उदय माहुरकर सेवानिवृत्त हुए, जबकि उनके सहयोगी सुरेश चंद्र दो दिन पहले सेवानिवृत्त हुए थे। सुश्री वंजना एन. सरना, नीरज कुमार गुप्ता और डॉ. अमिता पांडोव जैसे कई अन्य सूचना आयुक्त पिछले साल की शुरुआत में अपने-अपने कार्यकाल के अंत में सेवानिवृत्त हो गए थे। मुख्य सूचना आयुक्त वाई. के. सिन्हा 3 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया। वर्ष 2023 के अंत तक आयोग की कुल संख्या घटकर मात्र तीन रह गई, जबकि वर्ष की शुरुआत में अधिकतम दस सदस्य थे। पिछले महीने नई सरकार के गठन के बाद भी रिक्त पदों को भरने में बहुत कम रुचि दिखाई गई है।

आयोग की संख्या में कमी के कारण सीआईसी भवन में दूसरी अपीलों और शिकायतों का बोझ बढ़ गया है। इस स्तंभकार की दूसरी अपील, जो पहले से ही दस महीने से लंबित है, में अनिश्चितकालीन प्रतीक्षा अवधि देखने को मिल सकती है। इसके परिणाम की तुलना न्यायपालिका में लंबे इंतजार से नहीं की जा सकती। सूचना नाजुक होती है और न्याय से भी तेजी से पुरानी हो जाती है। यहीं पर इस स्तंभकार के सुझाव मददगार साबित हो सकते थे। 2010 से आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में अपने सीमित अनुभव में उन्होंने पाया है कि सीपीआईओ (केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी) आम तौर पर सूचना को कर्तव्यनिष्ठा से साझा करते हैं। हालाँकि, जहाँ वे ऐसा नहीं करते हैं, वहाँ अपीलीय प्राधिकारी, जो आम तौर पर विभाग/मंत्रालय में उनके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, बहुत कम मदद करते हैं। वे अपने कनिष्ठों के साथ मिलकर सूचना को दबाते हैं, जाहिर तौर पर कार्यालय की राजनीति में एहसान/दायित्वों के बदले में।

सूचना आयुक्त के रूप में उदय माहुरकर ने कथित तौर पर 2021-22 में 5056 आरटीआई अपीलों का निपटारा किया, जो आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के वर्ष के बाद से सबसे अधिक है। हालाँकि, यह अपीलीय प्राधिकारी के पूर्ण गैर-निष्पादन का भी प्रतिबिंब है। यदि उन मामलों का विभाग के भीतर ही पहली अपील के चरण में संतोषजनक ढंग से निपटारा कर दिया गया होता, तो दूसरी अपील के लिए सीआईसी से संपर्क करने की बहुत कम आवश्यकता होती। कई कारणों से सूचना को दबाया जा सकता है। दुर्लभ मामलों में, ऐसा हो सकता है कि सीपीआईओ ने अपनी मूल क्षमता (अनुभाग अधिकारी या अवर सचिव के रूप में) में कुछ ऐसा कार्य किया हो जिसकी वह जांच करवाना चाहता हो। इस मामले में, एक व्यक्ति को झूठे आरोपों के आधार पर काली सूची में डाल दिया गया, जबकि उसका मंत्रालय के साथ कोई वित्तीय लेन-देन नहीं था।

काली सूची में डालने के आदेश पर, हालांकि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ, सीपीआईओ ने अवर सचिव के रूप में अपनी वास्तविक क्षमता में हस्ताक्षर किए थे। जब उनसे फाइल नोट्स, यदि कोई शिकायत हो, नियमों का उल्लंघन हो, आदि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह कहकर मामले को टाल दिया कि फाइल प्रस्तुत की जा रही है (आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना देने से इनकार करने का ऐसा कोई आधार नहीं है, भले ही फाइल पीएमओ या राष्ट्रपति भवन में प्रस्तुत की गई हो)। इस स्तंभकार ने एक साल बीत जाने के बाद (सीआईसी में महीनों से लंबित अपील के कारण) वही जानकारी मांगी, तो पाया कि फाइल अभी भी प्रस्तुत की जा रही है!

निष्कर्ष स्पष्ट हैं। दोनों ही अवसरों पर, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, जो एक आईएएस अधिकारी है, ने पारदर्शिता के बजाय दमन के कारण को बढ़ावा दिया। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के तहत आवेदक को सूचना देने से अनुचित तरीके से इनकार करने पर सीपीआईओ पर 25,000 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

हालांकि, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य में स्पष्ट रूप से विफल रहने या दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। अनुशासनात्मक कार्यवाही की किसी गुंजाइश के बगैर कार्यपालिका के किसी सदस्य को अर्ध-न्यायिक शक्ति प्रदान करना शक्ति के दुरुपयोग का ही एक तरीका है। अपील की सुनवाई के लिए सीआईसी नोटिस केवल सीपीआईओ को भेजा जाता है, न कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को। सीपीआईओ, जो एक जूनियर अधिकारी है, के सामने सूचना आयुक्त द्वारा डांट दिए जाने का डर प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से कार्रवाई की ईमानदारी सुनिश्चित करेगा।

प्रथम अपीलीय अधिकारी को अनुशासित करना केंद्रीय सूचना आयोग के डेस्क पर लंबित मामलों के बोझ को कम करने की कुंजी है। सरकार ने हाल ही में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जो 1975 में आपातकाल की घोषणा की याद में एक अजीब नाम है।

जबकि आपातकाल लोकतंत्र विरोधी हो सकता था, यह अनुच्छेद 352 के तहत घोषित होने के कारण अपने आप में असंवैधानिक नहीं था। अगर सरकार 21वीं सदी में लोकतंत्र को मजबूत करने में दिलचस्पी रखती है तो संविधान हत्या दिवस या यहां तक कि भारत लोकतंत्र की जननी जैसी बयानबाजी काम नहीं करेगी अगर सीआईसी की ताकत कम कर दी जाए। 2005 का आरटीआई अधिनियम पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन के लिए एक प्रमुख उपकरण था।

आप की बात

पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी

पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाना अनेक प्रकार से लाभप्रद सिद्ध होगा। वर्तमान कर व्यवस्था में उत्पादन के प्रत्येक चरण पर केंद्र और राज्यों द्वारा किए जा रहे करारोपण व राज्यों द्वारा अधिकाधिक वैट लगाने के कारण देश में डीजल व पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी होती है। इनके ऊंचे दामो से वस्तु परिवहन एवं माल भाडे की लागत बढ़ जाती है जो खाद्यान्न सहित अनेक वस्तुओं की महंगाई बढ़ने का कारण है। पेट्रोलियम उत्पदों को जीएसटी के दायरे में लाने से देश भर में इनकी मानक दरे तय होगी तथा कीमतों में एकरुपता आएगी। इससे जीएसटी का मूल उद्देश्य-एक राष्ट्र एक बाजार एक कर पूरा होगा। इससे राज्यों के बीच पैट्रोलियम उत्पादों की सुगम आवाजाही सूनिश्चित होगी, ढुलाई की लागत घटेगी और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार आएगा। शराब के बाद पेट्रोलियम उत्पादो पर कर राज्यो की राजस्व आय का प्रमुख साधन हे। इसीलिए कोई भी राज्य इस पर वैट लगाने का अधिकार छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन केंद्र द्वारा राज्यो के बीच आम-सहमति बनाने एवं पेट्रोलिमय उत्पादों पर जीएसटी से प्राप्त कर राजस्व के अलग से वितरण के प्रस्ताव द्वारा उन्हें पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लागू करने के लिए राजी किया जा सकता हे।

– **विमलेश पगारिया,** बदनावर

बाल विवाह

सिविल सोसाइटी संगठनों के नेटवर्क चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया से जुड़ी रिसर्च टीम इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ने 2011 की जनगणना से आंकड़ों के साथ एनसीआरबी और नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 की सूचनाओं का विश्लेषण किया। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 16 लाख नाबालिग लड़कियों की शादी हो रही है। हालांकि, भारत में आजादी से पूर्व 1929 में ही नाबालिगों की शादी पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब प्रशासकीय अमले के साथ-साथ सुदूर गांवों में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता तैनात हैं। इसके बावजूद नाबालिग लड़कियों की शादी प्रशासनिक व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े होते हैं। संचार क्रांति के चलते गांव-गांव तक स्मार्टफोन और टीवी के जरिए हर नागरिक को पता है कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध होने के साथ-साथ नाबालिग बच्चों के जीवन को भी बर्बाद करता है। बाल विवाह रोकने के लिए तहसील स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देश की व्यापक प्रगति के बावजूद सबसे गरीब लोगों में सामाजिक जागरूकता तथा शिक्षा का अभाव एवं सड़ी-गली पुरानी मान्यताओं का अब भी बना रहना बाल विवाह का मुख्य कारण है।

– **सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

तलाक की विभीषिका

तलाक खासकर बच्चों के लिए हृदयविदारक है जिससे उनका भविष्य चौपट हो सकता है। उन्हें असल माता-पिता का लाड़-दुलार जो एक घर में रह कर मिलता है वह माता पिता के दूर-दूर रहकर नहीं मिल सकता है। यदि बच्चे से माँ या पिता दूर रहे तो वह एक के प्यार से वंचित ही रहेगा। यदा-कदा बच्चे से मिलना और पेरेंट्स के साथ बारी-बारी से बच्चे के रहने से सामान्य जीवन की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। बेहतर यही है कि या तो युगल शादी बहुत ही सोच समझ कर करें। विवाह बंधन में बंधने और बच्चा पैदा होने के पश्चात यदि कोई विवाद हो तो उसे बच्चे के सामने आने वाली कठिनाइयों को देख कर हल करने का प्रयास करें। युवाओं को समझना चाहिए कि तलाक एक मामूली सा सम्बन्ध विच्छेद नहीं है, बल्कि इससे पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। विडंबना है कि भारत में संयुक्त परिवार टूटने तथा एकल परिवारों में भी माता पिता के अलग-अलग स्थानों में काम करने अथवा अपने साथी की सोच से समझौता न करने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण तलाक जैसी कुपृथा बढ़ती जा रही है। इस विभीषिका का सबसे हानिकारक प्रभाव बच्चों के साथ उन वृद्धों पर भी पड़ता है जो अपने युवा बेटे-बेटियों से दूर रहने पर मजबूर होते हैं।

–**शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

कांवड़ यात्रियों को सुविधा

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबा, दुकानों या ठेलों पर मालिक का नाम प्रदर्शित करने के निर्देश पर सियासी घमासान मचा है। जबकि मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश में कोई बुराई नहीं है। नाम प्रदर्शित होने से शुद्ध शाकाहारी कांवड़ियों को सुविधा मिलेगी जो कम से कम इस यात्रा के दौरान लहसुन, प्याज जैसी चीजों का उपयोग नहीं करते हैं। कई बार शुद्ध शाकाहारी लोग जाने अनजाने नाम के भ्रम में ऐसी दुकानों पर चले जाते हैं, जहां वेज व नानवेज दोनों प्रकार का भोजन बनता है। अतीत में ऐसे अनेक मामले विवाद का कारण बने हैं। विपक्षी दलों को ऐसे मुद्दों पर सियासत करने से बचना चाहिए। यह सियासत का मसला है ही नहीं। किसी भी ग्राहक को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छानुसार किसी दूकान से सामान खरीदे या नहीं। समस्या कुछ लोगों द्वारा अपनी पहचान छिपा कर फर्जी नाम से मुनाफा बटोरने के कारण पैदा होती है। दूकानों पर मालिकों का नाम प्रदर्शित होने से खाद्य वस्तुओं में मिलावट अथवा अन्य कारणों से किसी के बीमार होने पर पुलिस व प्रशासन को दोषी दूकानदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुविधा होगी।

– **हेमा हरि उपाध्याय,** खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के दृष्टिगत योजना की मंडलायुक्त ने की समीक्षा

संवाददाता। संतकबीरनगर

मंडलायुक्त बस्ती मण्डल, बस्ती अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में जनपद में आगामी 20 जुलाई 2024 को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के साथ सभी सम्बंधित विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।

इस अवसर पर एडीएम जयप्रकाश, सीएमओ जयकेश त्रिपाठी, सीएमओ डॉ0 रामानुज कन्नौजिया, प्रभागीय वनाधिकारी अशोक कुमार सिंह उपस्थित रहे। मण्डलायुक्त ने प्रभागीय वनाधिकारी से जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य 2999740 पौधों को रोपित किये जाने के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा पौधों के उठान एवं अन्य तैयारियों के बारे में जानकारी लेते हुये विभागीय अधिकारियों से आज तक किये गये पौधों के उठान के बारे में विभागवार समीक्षा किया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मण्डलायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि 20 जुलाई 2024 को वन विभाग सहित सभी विभागों द्वारा एक ही दिन में वृक्षारोपण करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य को पूर्ण किया जाना है। इस सम्बन्ध में उन्होंने विभागवार तैयारियों की गहन समीक्षा किया। मण्डलायुक्त ने शासन की मंशा के अनुरुप वृक्षापोपण का महत्व एवं स्वस्थ जीवन शैली में वृक्षों की उपयोगिता बताते हुये उपस्थित अधिकारियों को पूरे उत्साह एवं सामाजिक सहभागिता के साथ शत-प्रतिशत वृक्षारोपण कराते हुये लक्ष्य पूर्ण करने हेतु प्रेरित भी किया। बैठक में मंडलायुक्त ने उपस्थित सभी विभागध्यक्षों को लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत वृक्षारोपण की कार्य योजना बनाकर दिनांक 20 जुलाई 2024 को वृक्षारोपण करते हुए उसकी जियो टैगिंग करने तथा हरीतिमा अमृत वन मोबाइल ऐप पर अपलोड करने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के साथ-साथ सामाजिक वानिकी के प्रोत्साहन हेतु नगर पालिका क्षेत्रों, नई सड़कों के निर्माणोपरान्त किनारों पर वृक्षारोपण, मनरेगा द्वारा कराये जा रहे कार्यों, तालाबों, गोशालाओं आदि के निकट के वातावरण को हरा-भरा करने हेतु पूरे वर्ष वृक्षारोपण कराते रहने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती से जनता में मचा त्राहिमाम

लालगंज, रायबरेली। भीषण गर्मी व उमस के बीच अघोषित विद्युत कटौती से क्षेत्र की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। दिन-रात मिलाकर 12 घंटे की आपूर्ति भी सुचारू रूप से नही हो पा रही है। सबसे अधिक समस्या जर्जर तारो के सहारे हो रही आपूर्ति के चलते लो वोल्टेज की है। जिससे लोगो के कीमती विद्युत उपकरण खराब हो रहे हैं।

मानसून का समय होने के बाद भी बारिस न होने से जहां किसानो के खेत सूखे पड़े हुए है वही बढ़ती उमस से लोगो की जीना दूभर हो गया है। यह समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब विभिन्न कारणो को लेकर विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। दिन-रात ट्रिपिंग, कटौती, लो वोल्टेज से उपभोक्ता परेशान है। रात में अंधाधुध कटौती से लोगों की नींद पूरी नही हो पा रही साथ ही बीमार रोगियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हर हाल में निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति के सख्त निर्देश दिये है लेकिन लालगंज क्षेत्र में अधिकारियों पर इसका कोई असर नही देखने को मिल रहा है।

गांवों में हो रही कटौती के चलते किसानो के खेत सूखे पड़े हुए है। किसान रामराज, बबलू यादव, देवता प्रसाद, मनारे, धनपाल सिंह आदि ने बताया कि बारिस न होने से व बिजली कटौती से खेतों में पानी नही भरा जा सका जिसके कारण धान की फसल पिछड़ती जा रही है। वही रात्रि कटौती से कस्बावासी सबसे ज्यादा परेशान है। लोगों ने मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री व जिलाधिकारी से रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की मांग की है। जिससे भीषण गर्मी से लोगो को राहत मिल सके साथ ही किसानो की धान की फसल को तैयार किया जा सके।

विकास कार्यों में छोटी संसद क्षेत्र पंचायत की भूमिका अहमः के एल शर्मा

संवाददाता। तिलोई, अमेठी

सिंहपुर ब्लॉक सभागार में शुक्रवार को क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई।बैठक में आठ करोड़ से अधिक के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। बैठक की कार्यवाही गत वर्ष की बैठक की कार्यवाही के अनुमोदन के साथ हुई।

क्षेत्र पंचायत की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद किशोरी लाल शर्मा एवं एमएलसी शैलेंद्र सिंह ने लोगों को संबोधित किया। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि गांव के विकास में क्षेत्र पंचायत के बैठक की भूमिका अहम है।उन्होंने कहा कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में प्रतिनिधियों को अवश्य आना चाहिए। ब्लॉक प्रमुख अंकित पासी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि क्षेत्र पंचायत के द्वारा गांव स्तर पर अनेक प्रकार के विकास कार्य करवाए जाते हैं अगर कही नाली ,खडंजा आदि की जरूरत है तो प्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत की कार्य योजना में मांग दर्ज करा सकता है। बैठक में सहायक विकास अधिकारी कृषि डॉ पवन वर्मा ने लोगो को कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। कहा कि किसानो को रागी, ज्वार,बाजरा , उडद, मूंग, अल्हार इत्यादि बीजों का वितरण निशुल्क किया जा रहा है।

एमएलसी शैलेंद्र सिंह ने जेई को समय खराब हुई सड़को एवं खडंजो को 15 दिनो के अंदर ठीक कराने के निर्देश दिए। एमएलसी ने ग्राम प्रधानो से कहा कि जब तक खराब पड़े खड़ंजे एवं सड़के जल निगम विभाग सही न करवाते तब तक ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण कराने के संस्तुति पत्र पर हस्ताक्षर न करे। एमएलसी शैलेंद्र सिंह ने बैठक में उद्यान विभाग की ओर से कोई अधिकारी न होने पर नाराजगी जाहिर की। एमएलसी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि अन्य जनपदों में बीडीसी के समान ग्राम प्रधानों को भी क्षेत्र पंचायत की बैठक का भत्ता मिलता है।

उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों को भी बैठक का भत्ता दिलाने उनके बैंक खाते पर भेजा जाए। प्याज का बीज वितरण न होने को लेकर एमएलसी ने मामले की शिकायत सीडीओ सूरज पटेल से फोन पर की। शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बीडीओ से कहा कि ब्लॉक मुख्यालय पर सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं जानकारी के लिए शिला पट्ट लगवाया जाए। ब्लॉक मुख्यालय पर शिला पट्ट लगने से लोगो को योजनाओं की जानकारी में आसानी होगी।

अमेठी सांसद केएल शर्मा ने जगदीशपुर में की बैठक

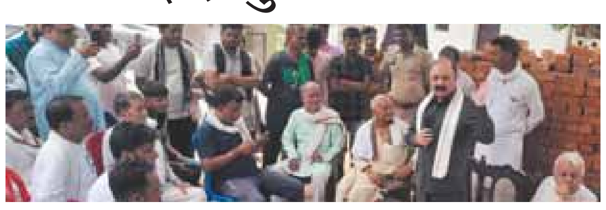

अमेठी। सांसद किशोरी लाल शर्मा अपने तीन दिवसीय दौरे के आज दूसरे दिन जगदीशपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं व विभिन्न संगठनोड्ढ के सथ बी एच ई एल गेस्ट हाउस जगदीशपुर में बैठक की। जनसुनवाई के दौरान अधिकतर समस्याएं बिजली को लेकर रही सांसद ने सभी समस्याओं के निस्तारण शीघ्र कराने का आश्वासन देते हुए आए हुए सभी लोगों के साथ एक-एक लोगों से मिलकर बातें की।

भेल अतिथि गृह से निकलकर बहुआ में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद अजहर के घर पर उपस्थित सैकड़ो लोगों को संबोधित करते हुए के एल शर्मा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव में मैं इस गांव में नहीं आ पाया था लेकिन इस गांव के लोगों ने अच्छी जीत दिलाकर आपने अपना और गांधी परिवार के रिश्ते को बड़ा सम्मान दिया है।

सांसद श्री शर्मा ने संबोधन में कहा कि मेरी राजनीतिक सेवा की शुरुआत इसी ब्लॉक से हुई थी आप सबके लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं गौरीगंज कार्यालय पर समस्या के निदान के लिए कभी भी आ सकते हैं। दिल्ली का आवास अभी तक मिला नहीं है वह भी आप लोगों का ही है । आप लोग ही रहेंगे। जब दिल्ली जाएंगे तो आप लोगों के रहने के लिए ही होगा। बहुआ, मत्तेपुर, भीखीपुर राजा फत्तेपुर सिंहपुर में जगह-जगह सांसद किशोरी लाल शर्मा का लोगों ने खूब स्वागत किया।

बेकाबू ट्रैक्टर पलटने से दबकर युवक की मौत

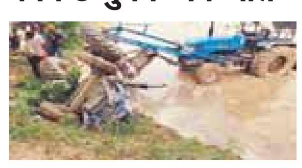

मुसाफिरखाना, अमेठी। भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र अंतर्गत मवई गांव में खेत की जुताई कर वापस लौट रास्ते में समय अनियंत्रित ट्रैक्टर पलट गया। जिसके नीचे दबकर युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वही एक अन्य घायल हो गया। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी। शुक्रवार की दोपहर करीब में नारा अढनपुर के मवई के पूरे दुखछोर गांव निवासी धनंजय चौरसिया पुत्र ढोंढे चौरसिया अपने स्वराज टैक्टर से खेत की जुताई करने गया था। जुताई कर वापस लौटते समय रास्ते में खाई पर चढ़ाते हुए ट्रैक्टर पलट गया जिससे टैक्टर पर बैठे आंसू चौरसिया व राम शरण घायल दब गए। दूसरे ट्रैक्टर की सहायता से दोनों को बाहर निकाला गया किंतु तब तक देर हो चुकी थी।

बेस्ट ब्रेन एवं स्पाईन स्पेशलिस्ट एवार्ड से नवाज़े गये डा. सलीम

लालगंज, रायबरेली। कस्बे के प्रसिद्व होम्योपैथ चिकित्सक डा. सलीम को दुबई के सात सितारा होटल बुर्ज अल अरब में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय होम्योपैथी सेमिनार में बेस्ट ब्रेन एवं स्पाईन स्पेशलिस्ट एवार्ड से नवाजा गया। डा. सलीम की इस उपलब्धि पर क्षेत्रीय लोगो ने हर्ष व्यक्त करते हुए वापस लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया।

नगर के बेहटा चौराहा के निकट हाजी अब्दुल सत्तार के नाम से चल रहे हास्पिटल में डा. सलीम कई वर्षो से जटिल रोगियों का होम्योपैथी से उपचार कर रहे है। जिनमें हजारो की संख्या में रोगी स्पाईन, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस आदि बीमारियों से ठीक होकर सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे है। उनकी इस उपलब्धि को उस समय नया मुकाम मिला जब दुबई के होटल बुर्ज-अल-अरब में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन में उन्हे बेस्ट ब्रेन एवं स्पाईन स्पेशलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बर्नेट होम्योपैथी कंपनी के तत्वाधान में आयोजित यह सम्मान उन्हे श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या, पूर्व कैबिनेट मंत्री अश्वनी चौबे, डा. नितीश चंद्र दुबे, डा. ग्रे स्मिथ ने सयुक्त रूप से प्रदान किया।

पीएसी वाहन इनोवा से टकराया 7 जवान घायल

नसीराबाद, रायबरेली। बीती रात करीब 9 बजे 11 बटालियन अमेठी के 13 जवान जायस में 11 मोहर्रम के जुलूस की ड्यूटी कर गौरीगंज वापस जा रहे थे। रास्ते में नसीराबाद थाना क्षेत्र के गांधीनगर छतोह मोड़ पर विपरीत दिशा से पहले एक तेज रफ्तार मैजिक गुजरी जिससे पी ए सी का वाहन अनियंत्रित होकर इनोवा से टकरा गई और पीएसी की गाड़ी पलट गई। दुर्घटना होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई दुर्घटना में पी ए सी के जवानों में विजय शंकर, रमेश चंद्र, रामेंद्र सिंह, अवधेश कुमार, आशीष कुमार सिंह, अमित कुमार पांडे, अशोक कुमार घायल हुए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई सूचना पाते ही कोतवाली प्रभारी जायस, नसीराबाद, गौरीगंज फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पीएसी के जवानों का असलहा कब्जे में लेकर सुरक्षित किया तत्पश्चात सभी घायलों को संयुक्त ज़िला अस्पताल असैदापुर अमेठी में भर्ती करवाया गया। उधर पुलिस ने रात में ही क्रेन बुलाकर छतीग्रस्त वाहन को मौके पर से हटा दिया।

केन्द्रीय कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण की मांग, सौंपा ज्ञापन

लालगंज, रायबरेली। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय आवाहन पर सरकारी कर्मचारियों की लम्बित समस्याओं का केंद्रीय आम बजट के अंतर्गत समाधान करने के लिये रेल कोच मजदूर संघ के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया। जिसमें रेल कोच मजदूर संघ ने अपनी मांगों के बाबत वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन महाप्रबंधक कार्मिक को सौंपा है। रेल कोच मजदूर संघ अध्यक्ष आदर्श सिंह बघेल ने बताया कि ज्ञापन में नई पेंशन स्कीम को समाप्त करके गारंटीड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और स्वायत्त शासी कर्मचारियों के वेतन भत्तों को पुनरीक्षित करने हेतु आठवें वेतन आयोग का गठन, केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न विभागों में रिक्त स्थानों को भरने की घोषणा करने की मांग की गई है। इसके अलावा कर-मुक्त आय की सीमा आठ लाख की जाय तथा मानक कटौती में भी वृद्धि करके कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाय और बचतों को प्रोत्साहित करने हेतु और अधिक छूट प्रदान की जाय। केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए बीमा की राशि न्यूनतम 15 लाख रु की जाय। वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से एक दिन पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशनरी बेनिफिट के लिये एक नोशनल इंक्रीमेंट प्रदान किया जाय। पूरे एक वर्ष सफलता पूर्वक सेवा के उपरांत इंक्रीमेंट प्रदान किये जाने का नियम है। जो कर्मचारी सफलता पूर्वक 1 वर्ष की सेवा पूरी करते है इसलिये इंक्रीमेंट प्रदान करने हेतु सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिए है जिसके आधार पर पिटीशनर कर्मचारियों को 1 इंक्रीमेंट प्रदान किया जा रहा है।

डीएम ने सीएम डैशबोर्ड एवं विकास कार्यों की बैठक में की समीक्षा

संवाददाता। उरई, जालौन

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ सीएम डैशबोर्ड एवं विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी एवं बेहतर ढंग से किया जाए, ताकि सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ा जा सके और उनकी समस्याओं का भी बुनियादी समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागीय अधिकारी सीएम डैशबोर्ड पर अपने विभाग के लक्ष्य में आपेक्षित सुधार लाएं और टीम भावना के साथ कार्य कर विकास कार्यक्रमों में तेजी लाकर जनपद को प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति में सुधार करें। यदि किसी भी विभागीय अधिकारी की प्रगति में शिथिलता पायी गई तो निश्चित ही कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

समीक्षा के दौरान कृषि विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायती राज, पर्यटन, प्राथमिक शिक्षा, पशुधन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला एवं बाल विकास आदि के कार्यक्रमों में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सन्तोषजनक न होने पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्य में तेजी लाकर अपनी देख-रेख में शत-प्रतिशत डाटा फीडिंग कराने हेतु निर्देशित किया।

उन्होंने कहा कि जिन विभागों में डाटा फीडिंग में तकनीकी समस्या आ रही है, उन विभागीय नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर निराकरण कराया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास, उप कृषि निदेश एसके उत्तम, परियोजना निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।

वृद्वाश्रम जाकर एडीजे ने किया निरीक्षण, बुजुर्गो से किया संवाद

संतकबीरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह के द्वारा वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया गया। एक-एक करके सभी बुजुर्गों से बात चीत की गई तथा उनको दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ एवं अन्य सुविधाओं के बारे में बात चीत की गई। श्री सिंह ने बताया कि माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के तहत अपनी आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण-पोषण करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

त्यौहारों पर नई परंपरा शुरू करने की इजाज़त नहीं दी जायेगीः एसपी

उरई, जालौन। प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ आईपीएस डा. दुर्गेश कुमार ने अपना परिचय देने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि हमारी उच्च शिक्षा लखनऊ और इलाहाबाद की है। जिसमें पीएचडी की उपाधि लखनऊ के राममनोहर लोहिया लॉ कॉलेज से की है। साथ ही बताया कि हमारी ज्यादातर सेवा नक्सली इलाकों में रही है। जिसमे चंदौली तीन वर्ष, वाराणसी तीन वर्ष जौनपुर तीन वर्ष, सोनभद्र, कानपुर, मेरठ और मऊ है। मऊ में 2009 से 2015 तक एसटीएफ में कार्यरत रहे और उसी तरह ढाई वर्ष तक डायल 100 डीजी के पद पर तैनात रहे है। उसी तरह लखनऊ वेस्ट जोन एसएसपी भी रह चुके है। उनका कहना था कि यह जिला तो छोटा है और यहां क्राइम बहुत कम है। फिर भी हमारी प्राथमिकता समाज को सही दिशा दिखना और पीड़ित को न्याय दिलाने की होगी।

साथ ही उन्होंने जिले की आम जनता से और मीडिया से सहयोग की अपेक्षा जाहिर की है। जिससे जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे और जिले को अपराध मुक्त रखा जा सके और समाज को सही दिशा दिखाते हुए सरकार की जीरो टालरेंश की नीति को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया अराजकतत्वों को किसी भी तरह से मनमानी करने की छूट नहीं दी जायेगी। त्यौहारों पर माहौल बिगाड़ने वालों के अरमानों को सख्ती से कुचला जायेगा। इसीक्रम में किसी भी त्यौहार पर नई परंपरा की इजाजत किसी को नहीं दी जायेगी।

जीवन सुरक्षित रखने के लिए करें श्रीअन्न का प्रयोगः डा. खादर वली

मिल्कीपुर अयोध्या। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में स्वस्थ भारत के नौवें स्थापना दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय स्वास्थ्य संसद का शुभारंभ हुआ। अमृतकाल में भारत का स्वास्थ्य एवं आहार परंपरा विषय पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मश्री डा. खादर वली मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया, सभापति स्वास्थ्य संसद कुलपति डा. बिजेंद्र सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद डा. आर.के सिन्हा, अयोध्या मेयर महंत गिरिशपति त्रिपाठी और आयुर्वेदाचार्य डा. हितेश चंद्र ने जलभरो कार्यक्रम प्रस्तुत कर किया। कार्यक्रम को बतौर मुख्यअतिथि संबोधित करते हुए पद्मश्री डा. खादर वली, मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारे शरीर में बीमीरियों का मूल कारण आहार है। उन्होंने कहा की वर्तमान समय में हमारे शरीर में एक साथ कई बीमारियां हैं। डायबिटिज, ब्लडप्रेशर, थायराइड, मेंटली परेशानी आदि बीमारी से मनुष्य जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में मनुष्य स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि अस्पताल के लिए कार्य कर रहा है। डा. वली ने कहा कि अगर मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो उसे अस्पताल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को सही रखना है तो चावल और गेहूं छोड़ना होगा और श्रीअन्न को अपनाना होगा। खाद से तैयार अनाज का सेवन मनुष्य कर रहा है जिसके कारण खून का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है और कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रहीं हैं।

चंद मिनट की बारिश ने पालिका की तैयारियों की खोल दी पोल

संवाददाता। जालौन

शुक्रवार को हुई बरसात में नगर पालिका परिषद की तैयारियों की हकीकत सामने आ गयी। नई बस्ती रोड पर नाला सड़क पर बहने लगा। स्कूली बच्चों के साथ क्षेत्र की जनता को गंदे पानी से घुसकर घरों तक जाना पडा है।

नगर क्षेत्र में नई बस्ती रामचबूतरा में बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या काफी पुरानी है और इस क्षेत्र में रहने वाली आबादी को कमोवेश प्रतिवर्ष इस समस्या से दो चार होना पड़ता है हालांकि प्रतिवर्ष समस्या आने पर प्रशासन और नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अगली बार तैयारिया पहलू से ही करने का आश्वासन भी देते रहे हैं लेकिन समस्या का अंत नहीं हो पा रहा है। जबकि बरसात के पहले पालिका परिषद द्वारा नगर सीमा के सभी नालों और नालियों की सफाई का अभियान भी चलाते हैं जिसमे लाखो रूपया खर्च होता है लेकिन समस्या का अन्त नही होता है और शुक्रवार को हुई बरसात में हाईवे से नई बस्ती को ओर जाने वाली सड़क पर नाले का पानी आ गया जिससे लोगों को उक्त गन्दे पानी से होकर गुजरना पड़ा है।

इतना ही नहीं सडक पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गये और जो जहां था वही रह गया था और यह समस्या शाम तक जारी रही। मुहल्ला निवासी मूलचन्द यादव कहते हैं यहां से गुजरे नाले की गहराई कम हो गई है जिससे सड़क पर पानी आ जाता है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वही मुहल्ले के अन्य लोगों की माने तो नालो की जमीन पर कब्जा हो गया है साथ ही नालो की सफाई भी ठीक से नही हो रही है। इस संबंध में ईओ नगर पालिका परिषद अवनीष शुक्ला की माने तो बरसात के पहले नालों की सफाई कराई गई थी लेकिन हाईवे की पुलिया ऊंची है जिससे पानी अपनी गति से नही निकल पा रहा है साथ ही पेट्रोल पम्प के पास भी नाले को सकरा किया गया है जिससे जलभराव हो रहा है लेकिन फिर भी इस क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान किया जाएगा।

शिव मंदिर में खजाने की लालच में खोद डाला गड्ढा, भक्त आक्रोशित

कालपी, जालौन। नगर के मुहल्ला तरीबुल्दा स्थित शिव मंदिर में अज्ञात लोगों द्वारा गड्ढा खोदे जाने पर आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गड्ढे को भरवाकर जांच शुरू कर दी है। नगर धार्मिक रूप से काफी संवेदनशील है यहा अक्सर ही ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिसके चलते प्रशासन ऐसे मामलों के प्रति बेहद सतर्क रहता है लेकिन फिर भी अराजक तत्वों द्वारा कुछ न कुछ ऐसा कर दिया जाता है जिससे लोगो की आस्था पर चोट हो जाती है। सूत्रों की माने तो नगर के मुहल्ला तरीबुल्दा स्थित शिव मंदिर में शुक्रवार सुबह मन्दिर मे पूजा अर्चना करने गए लोगों को शिवलिंग के पास एक गड्ढा खुदा हुआ मिला था। जिसकी जानकारी मुहल्ला और नगर में पहुंची तो वहा भीड़ पहुंच गई। मामले की सूचना पुलिस को मिली तो वह भी हरकत में आ गयी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन गड्ढे को भरवाकर मन्दिर की स्थित को सामान्य कर दिया है हालांकि अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की तहरीर पुलिस को नही दी गई है। सीओ डा. देवेंद्र पचौरी के अनुसार मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया है जिसके चलते पुलिस जांच कर रही है शीघ्र ही घटना की हकीकत से पर्दा उठाया जाएगा।

आर्यकन्या पाठशाला कर्मियों के भुगतान का मामला जस का तस, शिक्षण कार्य प्रभावित

संवाददाता। कालपी, जालौन

वेतन भुगतान को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे आर्यकन्या पाठशाला इण्टर कालेज की शिक्षिकाओं और कर्मचारियों की समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ है जिसके चलते शुक्रवार को भी उन्होंने कोई काम नहीं किया है जिससे विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित है। विदित हो कि नगर स्थिति आर्यकन्या पाठशाला इण्टर कालेज में प्रबंधन और प्रधानाचार्या के बीच काफी दिनों से जंग चल रही है जिसके चलते शिक्षिकाओं के साथ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विगत 4 माह से वेतन नही मिला है। परेशान शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने गत 1 जुलाई से कार्य बहिष्कार कर दिया था जिसके बाद शिक्षिकाओं ने भी काम बंद कर दिया था हालाकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए बिद्धालय की प्रबन्धिका ने सभी को आश्वस्त किया था कि 10 दिनों में उन्हें बकाया बेतन का भुगतान कर दिया जाएगा और इसके लिए उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को भी अवगत कराया था और समस्या के समाधान करने का आग्रह किया था लेकिन समय बीत जाने के बाद भी उन्हें वेतन नही मिला था जिसके चलते उन्होंने फिर से कार्य बहिष्कार कर दिया था जो अभी भी जारी है। हालांकि प्रबंधन ने इसके लिए प्रधानाचार्या को जिम्मेदार मानकर उन्हें निलंबित भी कर दिया है और कार्यवाहक प्रधानाचार्य के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित से व्यवस्था करने के लिए आग्रह किया है। लेकिन अभी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है जिसके चलते शिक्षिकाओं और कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। जिसके चलते विद्यालय के शिक्षण कार्य के साथ अन्य कामकाज भी ठप पड़ा है क्योंकि विद्यालय में चल रहे विवाद के चलते जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय के समस्त खाते भी बंद कर दिए हैं।

अग्निकांड पीड़ित दुकानदारों को मिले आर्थिक मददः कांग्रेस

जालौन, उरई। गुरुवार की सुबह कस्बे के पंडित दीन दयाल उपाध्याय चौराहा के पास अज्ञात कारणों से आधा दर्जन दुकानों में आग लग गई। आग लगने से आधा दर्जन दुकानों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। पीड़ित दुकानदार को आर्थिक मदद दिलाये जाने के कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी नगर अध्यक्ष कमाल अहमद, राजा भईया, अशोक चौधरी, वसीउर्रहमान सिद्दीकी, हाजी अतीक अहमद, बबलू, चंद्रशेखर वर्मा, भगवान सिंह, ओमनारायण शर्मा, सामीर अली, कपिल चंसौलिया, लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी ने शुक्रवार की सुबह गुरुवार को पंडित दीन दयाल उपाध्याय चौराहे पर हुए अग्नि कांड के प्रभावित दुकानदारों से भेंट की और आग लगने से हुई क्षति की जानकारी ली। उन्होंने पीड़ितों को ढांढस बंधाते हुए उन्हें हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। पीड़ितों से भेंट करने के बाद जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी एसडीएम अतुल कुमार के पास पहुंचे।

पेड़ रहेगा तो जीवन रहेगा, पौधों के संरक्षण पर दे विशेष बल: मण्डलायुक्त

● मण्डलायुक्त ने वृहद वृक्षारोपण अभियान की विभागावार समीक्षा कर दिये निर्देश ●वृक्षारोपण जन अभियान.2024 के अन्तर्गत जनपद में रोपे जायेंगे 61 लाख 90 हजार पौधे ●जनपदवासियों से वृक्षारोपण अभियान में सहभागिता करने हेतु अपील

कानपुर देहात। कानपुर मण्डल, मण्डलायुक्त/ नोडल अधिकारी वृक्षारोपण अमित गुप्ता की अध्यक्षता व जिलाधिकारी आलोक सिंह की उपस्थिति में दिनांक 20 जुलाई को जनपद में होने वाले वृहद वृक्षारोपण की तैयारी के संबंध में जिला वृक्षारोपण समिति के साथ समीक्षा बैठक मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। मण्डलायुक्त महोदय ने कहा कि पेड़ रहेगा तो जीवन रहेगा। उन्होंने पौधों के संरक्षण पर विशेष बल देने के निर्देश दियें। उन्होंने फलदार वृक्षों के साथ ही उपयोगी वृक्षां का चयन किये जाने के निर्देश दिये। कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी संबंधित विभागों द्वारा की जा रहीं वृक्षारोपण से सम्बन्धित कार्यवाही की निरंतर निगरानी की जायए उनके द्वारा अपलोड की जा रही फोटो आदि को देखा जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष की गई तैयारियों तथा पौधों के संरक्षण के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मण्डलायुक्त महोदय ने पौधों के संरक्षण पर विशेष बल देते हुए कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जितने भी वृक्ष लगाएए उनमें से अधिक से अधिक को बचा सके। उन्होंने सभी विभागों को लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वृक्षारोपण करनेए जियो टैगिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां पर भी वृक्षारोपण कराया जाये वहां पर एक वृक्षारोपण रजिस्टर अवश्य रखा जाए, जिसमें लगाए गए पौधों की संख्या, उनके संरक्षणकर्ता का नामए नोडल अधिकारी आदि के बारे में जानकारी अंकित की जाए।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी ने मण्डलायुक्त महोदय को बताया कि शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार सभी संबंधित विभागों को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष पौधे उठान जारी कर दिए गए हैं, सभी विभागों द्वारा स्थल चयन, गड्ढा खुदान, पौधों की उठान तथा अन्य संबंधित तैयारियां समय सारणी के अनुसार संबंधित विभागों से समन्वय कर पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि सभी विभागों को प्रत्येक घंटे अर्थ एवं संख्याधिकारी को रिपोर्ट देने, हरीतिमा ऐप पर जियो टैगिंग करने, मेरी लाइफ पोर्टल पर फोटो अपलोड करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा पूर्व से ही दिए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण हेतु ऐसे स्थान का चयन किया गया है जहां पर उन्हें संरक्षित रखा जा सकेए जैसा कि शासन के निर्देशानुसार नारा है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। नून नदी कैचमेंट एरिया में वृहद वृक्षारोपण कराया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत तीन वेटलैंडां का भी चयन किया गया है, बरिंगा वेटलैंड, मगही झीलए दुआरी तालाब। सभी विभागों को वृक्षारोपण के संबंध में बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियां के बारे में वीडियो के माध्यम से बताया गया है। इस वृक्षारोपण महाअभियान में विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों को भी जोड़ा गया है। जनपद में वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत लगभग 62 लाख पौधें लगायें जाये जायेंगे।

बैठक में पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति, सीडीओ लक्ष्मी एन., अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अमित राठौर, डीएफओ एके द्विवेदी, सीएमओ डा. एके सिंह, सहायक निदेशक सूचना सुरजीत सिंह, पीडी वीरेन्द्र सिंह, डीसी एनआरएलएम गंगाराम वर्मा, डीएसटीओ प्रतिभा सिंह, डीसी मनरेगा सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।

मुख्य विकस अधिकारी ने परिषदीय विद्यालय राजापुर का किया निरीक्षण, परखी व्यवस्थाएं

लखीमपुर खीरी। पठन पाठन की गुणवत्ता, स्कूल की साफ सफाई, शिक्षकों व छात्र.छात्राओं की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता इत्यादि का जायज़ा लेने के उद्देश्य से सीडीओ अभिषेक कुमार ने शुक्रवार को ब्लाक लखीमपुर के तहत प्राथमिक विद्यालय राजापुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने विभिन्न पंजिकाओं का अवलोकन किया। शिक्षकों की उपस्थिति के सम्बंध में भी बच्चों से ही पूछताछ की। उन्होंने स्कूल में पढ़ रहे छात्र.छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने परिवार व जिले का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

सीडीओ ने शिक्षण स्टाफ को निर्देश दिया कि बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के साथ.साथ सांस्कृतिक, खेल व उनके रूचि के अनुसार जागरूक भी करें। सीडीओ ने बच्चों से विभिन्न रंगोंए आकृतियों के बारे में पूछते हुए बच्चों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता की परख की। साथ ही पठन पाठन, साफ सफाई, मध्याह्न भोजन आदि की जांच की। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने छात्र.छात्राओं से रूबरू होते हुए उन्हें मन लगा कर पढ़ने, गुरूजनों व माता.पिता का आदर करने, स्वच्छता अपनाने की नसीहत दी।

डंपर व ट्रक की सीधे भिडंत में दोनों के चालक जिंदा जले मौत, दो घायल

संवाददाता। हमीरपुर

कल देर रात हमीरपुर कोतवाली क्षेत्र के राठ मोड़ के पास डंपर व ट्रक की आमने सामने भिड़ंत में दोनो ट्रको के चालक जिंदा जलकर मर गये। दोनो वाहन जलकर राख हो गये है। कई घंटे जाम लगा रहा। पुलिस के मुताबिक डंपर कानपुर से कबरई गिट्टी भरने जा रहा था तभी कबरई से गिट्टी भरकर कानपुर जा रहे ट्रक की सीधे भिंडंत राठ मोड़ पर हो गयी जिससे दोनो ट्रको में आग लग गयी और चालक दोनो ही फंस गये पुलिस को जानकारी होते ही मौके पर जाकर चालक को निकाला मगर तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी पुलिस ने दोनो की शिनाख्त योगेंद्र भदौरिया(38) निवासी दहेली थाना विधनू कानपुर नगर व दूसरे चालक की शिनाख्त नीरज गुप्ता(40) ग्राम इटर्रा थाना घाटमपुर जिला कानुपर नगर के रुप में की है। दो लोग

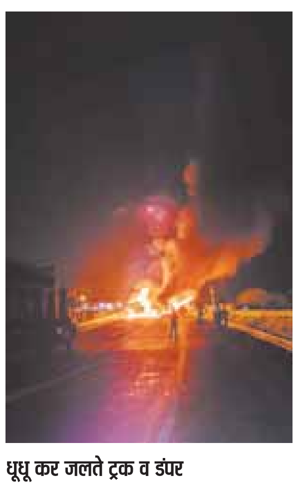
धूधू कर जलते ट्रक व डंपर

शिवबरदानी ग्राम इटर्रा थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर व एक अनू्य लोग घायल हो गये दोनो को हमीरपुर जिला अस्पताल से कानपुर रिफर कर दिया गया है। दमकल मौके पर जाकर आग पर काबू पाया,दोनो शवों को पोस्मार्मटम के लिये भेज दिया है।

भाकियू नेता ने कानूनगो पर रिश्वत का आरोप लगाया

● बोले जिलाध्यक्ष राजस्व कर्मियों के विरुद्ध जल्द होगा धरना प्रदर्शन

किसानों की समस्याओं को लेकर रणनीति बनाते जिलाध्यक्ष शमीम सिद्दीकी।

गुरसहायगंज (कन्नौज)। हजारों रुपए की सुविधा शुल्क लेने के उपरांत भी राजस्व निरीक्षक द्वारा भाकियू नेता को दो साल से पैमाइश के लिए दौडाया जा रहा है। किसान नेता ने मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से करने की चेतावनी दी है। जिलाध्यक्ष शमीम सिद्दीकी ने मामले को लेकर कहा कि लेखपाल एवं कानूनगो बेलगाम हो गए हैं। सबक सिखाने के लिए जल्दी ही जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

बिलंदपुर निवासी अनबार खान पुत्र यासीन खान एवं साकिर खान पुत्र हनीफखान द्वारा जिलाधिकारी को भेजे गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि मौजा असौलिया में उसकी लगभग 16 बीघा जमीन है। उनके पड़ोसी द्वारा उसकी जमीन का कुछ हिस्सा अवैध रूप से जोता जा रहा है। जमीन की पेमाइस के लिए तहसील दिवस में सितंबर 2022 में प्रार्थना पत्र दिया गया था। एसडीएम के निर्देश पर संबंधित कानूनगो उसके पास पहुंचे और पैमाइश करवाने एवं कब्जा दिलवाने के लिए कानून गो द्वारा उससे पचास हजार की मांग की गई। अनवर आदि ने बताया कि उसने अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखकर 42000 बतौर सुविधा शुल्क 03 अक्टूबर 2022 को कानून को छिबरामऊ को कार्यालय के निकट साकिर खान के सामने दिए। उसकी जमीन की पैमाइश की गई निशान लगाए गए। पैमाइश सही की गई लेकिन राजस्व कर्मी द्वारा दूसरे पक्ष से भी सुविधा शुल्क लेकर रिपोर्ट अनवर आदि के खिलाफ लगा दी गई तभी से लेकर अभी तक जमीन की पैमाइश के लिए उसके द्वारा डीएम सहित तमाम अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसने एसडीएम के आदेश के बावजूद भी स्थानीय लेखपाल पर कार्य में हीला हवाली करने का आरोप लगाया है। किसान नेता द्वारा जिलाध्यक्ष से मामले की शिकायत की गई। जिस पर जिलाध्यक्ष शमीम सिद्दीकी ने कहा कि उप जिलाधिकारी के कई आदेशों को लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक विपक्षी गणों से अधिकतर मामलों में मोटी रकम लेकर टालते चले आ रहे हैं।

ट्रैक्टर से टकराकर बाइक सवार वृद्धा की मौत, भाई बहन घायल

सुमेरपुर। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मुंडेरा के पास एक तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर के पीछे में जा घुसी। तो बाइक में सवार चालक, उसकी बहन घायल हो गई। जबकि उसकी नानी की मौके पर ही मौत हो गई। सिसोलर थानाक्षेत्र के बैजेमऊ गांव निवासी सत्येंद्र कुमार 28 वर्ष अपनी बहन बन्दों 25 वर्ष व नानी मुन्नी देवी 65 वर्ष के साथ बाइक से थानाक्षेत्र के मौहर गांव में शादी समारोह में शामिल होने आया था। शुक्रवार को शाम करीब 4 बजे यह तीनों बाइक से लौटकर बैजेमऊ जा रहे थे। तभी मुंडेरा मिहुना के मध्य सत्येंद्र की तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से जा घुसी। इस घटना में सत्येंद्र एवं उसकी बहन बंदों को मामूली चोटें लगी हैं। नानी मुन्नी देवी को गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस चालक विपिन कुमार, ईएमटी अभिषेक कुमार मौके पर पहुंचे और तीनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाएं।

क्विक न्यूज

महिला से अश्लील हरकतें व मारपीट कर दी धमकी

गुरसहायगंज (कन्नौज)। किसी विवाद को लेकर महिला के साथ उसकी मां सहित गांव के चार लोगों ने घर में घुसकर अश्लील हरकतें कीं। महिला व उसके पति द्वारा विरोध करने पर उक्तगणों ने मारपीट कर धमकी दी। पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्र के ग्राम निवासी पीड़िता द्वारा कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया है कि विगत 07 जुलाई की शाम 05 बजे वह अपने घर में थी। तभी गांव के ही वकील, मेहताब, अख्तर, उसकी मॉ रहमुन निंशा आए और घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए गाली गलौज की। उसके एवं उसके पति द्वारा विरोध करने पर उक्तगणों ने लात घूसों से मारपीट कर घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। मुकदमा दर्ज कर जॉच शुरू कर दी गई है।

जहरीला पदार्थ खाकर युवक ने की आत्महत्या

सुमेरपुर। थाना सुमेरपुर क्षेत्र के ग्राम बिदोखर मेदनी में शुक्रवार को एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया गंभीर अवस्था में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना सुमेरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम विदोखर मेदनी के सलमान 30 वर्ष पुत्र सुभानी शुक्रवार की सुबह घर से यह कहकर निकला कि वह इलाज कराने जा रहा हैए तभी रास्ते में अज्ञात कारणों के चलते उसने जहरीला पदार्थ खा लिया उसके पिता द्वारा गम्भीर अवस्था में जिला चिकित्सालय हमीरपुर लाया गया । इलाज के दौरान करीब डेढ़ बजे चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के शव को जिला मर्चरी हाउस हमीरपुर में रखवाया गया, थाना सुमेरपुर की पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया है।

ट्रक की टक्कर से ई-रिक्शा सवार युवक की मौत

फतेहपुर। थरियांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत खैराबाद गांव के समीप एनएच-2 में गुरूवार की देर शाम ट्रक की टक्कर लगने से ई-रिक्शा में सवार 48 वर्षीय युवक की मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सरांय डडीरा गांव निवासी स्व. नंद कुमार का पुत्र शिवबली व छत्रपाल का 35 वर्षीय पुत्र विमलेश कुमार गुजरात जाने के लिए घर से निकले थे। बस न मिलने के कारण दोनों ई-रिक्शा में सवार होकर रिश्तेदारी में जा रहे थे। जैसे ही ई-रिक्शा खैराबाद मोड़ के समीप एनएच-2 पर पहुंचा तभी तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दिया जिससे शिवबली की मौके पर मौत हो गई। वहीं विमलेश घायल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विच्छेदन गृह भेज दिया।

कुएं में गिरकर मासूम की मौत

फतेहपुर। थरियांव थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुर मजरे रामपुर में शुक्रवार की सुबह कुएं में गिरकर पांच वर्षीय मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने शव को विच्छेदन हेतु भेजा है। जानकारी के अनुसार शिवपुर मजरे रामपुर गांव निवासी कोमल सिंह लोधी का पुत्र सतीश लोधी आज सुबह लगभग नौ बजे अपने हमजोली बच्चों के साथ खेलते-खेलते गांव से पांच सौ मीटर दूर पहुंच गया। वही आस-पास के खेतों में परिवार सहित अन्य लोग काम कर रहे थे। मासूम कुएं में गिर गया। कड़ी मशक्कत के बाद मासूम को बाहर निकाला और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लाए जहां इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को विच्छेदन गृह भेज दिया।

तखत से गिरकर युवक ने तोड़ा दम

फतेहपुर। थरियांव थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुर में गुरूवार की देर शाम तखत से गिरकर 34 वर्षीय युवक घायल हो गया था। जिसकी कुछ देर बाद ही मौके पर मौत हो गई। शिवपुर गांव निवासी स्व. शिवपरसन लोधी का पुत्र जगजीत लोधी गुरूवार की देर शाम खाना खाने के बाद तखत पर लेटा था तभी अचानक मुंह के बल नीचे गिर पड़ा जिससे उसकी नाक में गंभीर चोट आ गई। कुछ देर बाद ही उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को विच्छेदन गृह भेज दिया।

आकाशीय बिजली से चरवाहे की मौत

असोथर (फतेहपुर)। थाना क्षेत्र के गांव अब्बी का डेरा मजरे राम नगर कौहन निवासी 20 वर्षीय रामू पुत्र संतोष की आज दोपहर क्षेत्र के डा. चंद्रहास सिंह का डेरा के पास भैंस चराते समय अचानक गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई।

बीसीपी डिग्री कॉलेज में हुआ स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरण

फतेहपुर। बाबू चंद्रिका प्रसाद महाविद्याल हुसैनगंज में स्वामी विवेकानन्द युवा शक्तिकरण स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरण योजना के अन्तर्गत 76 छात्र छात्राओं को स्मार्ट फ़ोन वितरित किए गए। महाविद्यालय के प्रबन्धक बृजेश कुमार शुक्ल, प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। महाविद्यालय परिसर में सरस्वती पूजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

नवॉगुतक एसएचओ ने कहा ठेलिया दुकानदार फुटपाथ को छोड़कर लगाये दुकान

कानपुर देहात। एसपी बीबीजीटी एस मूर्ति द्वारा गुरूवार की रात्रि जनपद की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने के लिये जारी की गयी तबादला एक्सप्रेस का परिणाम देखने को मिल गया, जनपद के सॅवेदनशील थाने रूरा का पदभार ग्रहण करते हुये प्रभारी निरीक्षक रामगोविन्द मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस बल ने पैदल मार्च करते हुये सडक पर अतिक्रमण किये ठेलिया दुकानदारों को चेतावनी देते हुये अपनी दुकानों को फुटपाथ से हटकर नालों के दूसरी तरफ लगाने का आदेश दिया। अर्से बाद सडकों पर पुलिस का इकबाल देखकर अराजकतत्वों व अतिक्रमणकारियों में हडकम्प मच गया। एसपी ने जनपद के महत्वपूर्ण थानों के प्रभार में व्यापक स्तर पर फेरबदल किया था। रामगोविन्द मिश्रा को रूरा थाने का प्रभारी बनाया गया था, गजनेर थाने का प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार यादव को, मुकेश कुमार सोलॅकी को रनियॉ थाने का पदभार दिया गया।

आज रोपे जाएंगे 48 लाख से अधिक पौधे

● पिछले वर्षों में रोपण के बाद नहीं बचे थे अधिकांश पौधे ●इस दफा पौधों की देखरेख को बनाना होगा जिम्मेदार

फतेहपुर। जिले में पौधरोपण कर धरती के श्रृंगार का क्रम शुरू हो गया है। आज यानी 20 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाएगा। जिसके तहत जिले में 48.53 लाख से अधिक पौधों को रोपने की योजना है। अब सवाल यह है कि पौधरोपण के लिए इनकी देखरेख व सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा। पिछले वर्षों से सबक मिला है कि धरती की गोद में जगह पाने वाले अधिकतर पौधे अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते। बीते सालों में पौधरोपण करने वाले विभाग अपने पौधों के अच्छे माली नहीं बन सके।

बीते वर्षों में जुलाई व अगस्त माह में रोपे गए लाखों पौधों में से बड़ी संख्या में पौधे अकाल मौत का शिकार हो गए। पौधों के संरक्षण के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई गई। डीएम हर बार पौधरोपण करने वाले सभी विभागों को पौधों की देखभाल का निर्देश देते हैं लेकिन धरातल पर यह नहीं दिखता है। जिसके चलते बड़ी संख्या में पौधे अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते।

26 विभागों को दिया गया है लक्ष्य: इस वर्ष भी वन विभाग द्वारा 25 नर्सरियों में करीब 64 प्रजाति के 74.76 लाख पौधे तैयार किया गया है। वन महोत्सव में 26 विभागों को दिए गए लक्ष्य के मुताबिक पौधरोपण किया जाना है। इसके शुक्रवार को पूरे जिले में पौध वन विभाग से लोग ले जाते नजर आए। विभाग ही बनते हैं पौधों के माली: वृक्षारोपण अभियान के दौरान विभिन्न विभागों को दिया जाने वाला लक्ष्य तो पूरा कर दिया जाता है लेकिन पौधों को सुरक्षित बचाने का टारगेट न मिलने से जिम्मेदार बेपरवाह हो जाते हैं। चिंतकों का मानना है कि विभागों के माली बनने के बावजूद पौधों की अकाल मौत बड़ा सबक है।

कर्ज से परेशान मजदूर का पेड़ से लटकता मिला शव

सुमेरपुर। विकास खण्ड सुमेरपुर अंतर्गत कोतवाली हमीरपुर से जुड़े गांव बड़ागांव में कर्ज से परेशान एक मजदूर का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला तो गांव में हड़कंप मच गयाए सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सुरेश निषाद 55 वर्ष पुत्र रसपाल मूल रूप से बांदा जनपद के खपटिहा गांव का निवासी है 25 वर्ष पूर्व वह अपने गांव को छोड़कर अपनी ससुराल बड़ा गांव में रहने लगा था और मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण कर रहा थाए बताया जाता है कि एक पुत्र के बाद लड़की की शादी की थी तो उसके ऊपर ढाई तीन लाख का कर्ज हो गया थाए जिसको अदा न कर पाने से वह परेशान रहता था, 19 जुलाई की रात को गांव के बाहर एक नीम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली सुबह लोगो ने देखा तो हड़कंप मच गया, नीम के पेड़ में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेने की सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है।

कृषक पुरानी पद्धति को अपनाते हुए मोटे अनाज पैदा करें: डीएम

संवाददाता। फर्रुखाबाद

फतेहगढ़ स्थित विकास भवन में किसान दिवस का आयोजन जिला अधिकारी डॉक्टर बी के सिंह के अध्यक्षता में संपन्न हुआ जिसमें आए किसान एवं किसान नेताओं ने नहर बिजली बैंक खाद एवं बालू खनन मिट्टी खनन आदि अपनी-अपनी समस्याएं रखकर निस्तारण कराए जाने की मांग की जिस पर जिला अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों गुणवत्ता पूर्ण रूप से निस्तारणकरने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा है कि हमारे बुजुर्ग लोग मोटा अनाज खाकर स्वस्थ रहते थे इस पद्धति को अपनाते हुए आप लोग मोटा अनाज पैदा कर जहां लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करें वही अपनी आमदनी भी दोगुनी करें क्योंकि मोटा अनाज काफी महंगे दामों पर बड़े-बड़े शहरों में बिक रहा है, वही किसी वैज्ञानिकों ने खाद बीज की मात्रा बताकर अधिक से अधिक जैविक खा। प्रयोग करने का आवाहन किया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, अरविंद कुमार मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल, उप कृषि निदेशक थान सिंह गौतम, जिला उ ाान आलू विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह, डा आदेश आदि संबंधित विभागों के अधिकारी एवं किसान यूनियन के पदाधिकारी विभाग कृषक मौजूद रहे।

सीपी इंटरनेशनल स्कूल में पुलिस विभाग ने छात्राओं को दिया सुरक्षा संबंधी ज्ञान

फर्रुखाबाद। सीपी इंटरनेशनल स्कूल में मिशन शक्ति के तहत पुलिस विभाग ने छात्राओं को सुरक्षा से संबंधित ज्ञानार्जन कराया। महिला पुलिस अधिकारी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि वह किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें, हर किसी को अपना नंबर नहीं दें, जब तक प्रोफाइल की सही जानकारी न हो तब तक किसी को फेसबुक पर रिक्वेस्ट न भेजें तथा कम उम्र के बच्चे अपनी अधिक आयु दर्शाकर फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आईडी न बनाएं , अनजान व्यक्ति का कोई कॉल रिसीव न करें, यदि किसी अनजान व्यक्ति का काल या वीडियो कॉल आता है तो फोन काट दें यदि धोखे से वीडियो कॉल रिसीव हो जाती है तो कैमरे पर तत्काल उंगली लगा दे जिससे आपकी फोटो उसके पास न पहुंचे और वह आपकी फोटो या वीडियो का दुरुपयोग न कर सके। इसके अलावा यदि कोई किसी भी

प्रकार की धमकी देता है या किसी प्रकार का लालच देता है तो घर में अपने माता-पिता को अथवा स्कूल आने पर शिक्षकों को अवश्य बताएं।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वाभिमान के प्रति सरकार कृत संकल्पित है लेकिन छात्राओं को भी जागरूक रहना उनका कर्तव्य तथा उनकी पढ़ाई का हिस्सा है। यदि कोई आपातकालीन समस्या आ जाती है तो महिलाओं, बालिकाओं को चाहिए कि वह वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एंबुलेंस सेवा 108 आदि टोल फ्री नंबरों से सहायता प्राप्त करें । तथा उपरोक्त नंबरों को हमेशा ही अपने पास डायरी में लिखकर रखें। ये हेल्पलाइन आकस्मिक स्थिति से लेकर कानूनी मदद करने में मददगार हैं। साइबर सुरक्षा से लेकर महिलाओं और लड़कियों पर आने वाली समस्त आकस्मिक घटनाओं पर चर्चा की तथा उनका निदान बताया।

पलिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पहुंचे डीएम, एसपी भ्रमण कर लिया बाढ़ की स्थिति का जायजा

संवाददाता। लखीमपुर खीरी

शुक्रवार सुबह सूचना मिली कि शारदा का जलस्तर इतना बढ़ गया कि भीरा.पलिया मार्ग पर भी पानी चल रहा है। इसी मार्ग से रास्ता तय करते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी गणेश प्रसाद साहा पलिया तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। सर्वप्रथम डीएम एसपी पलिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र श्रीनगर पहुंचेए आम जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। नदी की वजह से क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक का मौका मुआयना किया। एसडीएम कार्तिकेय सिंह को बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। डीएम.एसपी ने एनएचएआई के सड़क मार्ग पर अतरिया में जल निकासी दूसरी तरफ किए जाने के उद्देश्य से ह्यूम पाइप डालने वाले कार्य का निरीक्षण कियाए संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए।

डीएम.एसपी ने तहसीलए ब्लाक पलिया के बाढ़ प्रभावित गांव बसंतापुरकला, मकनपुर का भ्रमण कर पीड़ितों का दर्द जाना। उन्होंने बाढ़ की स्थिति की बारीकी से जानकारी हासिल की। मौजूद किसानों, ग्रामीणों से वार्ता कर भोजन पैकेट, खाद्यान्न किट वितरण कर अद्यतन स्थिति जानी। डीएम ने आपदा से प्रभावित लोगों से कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरा शासन.प्रशासन उनके साथ है। सरकार की ओर से हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।

डीएम ने निरीक्षण में पाया कि गन्ने की फसल काफी खराब हो गई। एसडीएम को निर्देश दिए कि जल्द ही सर्वे कार्य पूर्ण किया जाए। हालांकि एसडीएम ने ज्यादातर प्रभावितो का सर्वे करा दिया गया है। अवशेष प्रभावितो का सर्वे 02 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए। एसपी ने ग्रामीणों से संवाद किया। जाना कि उन्हें किसी बात का भय तो नहीं है।

बुखार से पीड़ित शालिनी के घर डीएम ने भेजी डॉक्टरों की टीम कराया उपचार

डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निरीक्षण के दौरान ग्राम बसंतापुरकला में मेडिकल टीम द्वारा ग्रामीणों का चेकअप कर जरूरी औषधीय प्रदान करती मिली। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एसपी गणेश प्रसाद साहा संग बाढ़ प्रभावित द्रौपदी पत्नी दुजई के घर जा पहुंचीए जहां उन्होंने परिवार से उनकी कुशलता जानी। उनकी निगाह अचानक बिस्तर पर लेटी उनकी पुत्री शालिनी पर पड़ी। डीएम के पूछने पर द्रौपदी ने बताया कि शालिनी बुखार से पीड़ित है। डीएम ने फॉरेन मेडिकल टीम भेजकर उपचार भी करवाया।

डीएम एसपी ने पलिया निघासन मार्ग पर पीडब्ल्यूडी का काम दिए निर्देश

डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एसपी गणेश प्रसाद साहा संग पलिया.निघासन मार्ग पर लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड.3 द्वारा 06.06 मीटर के चार स्पान बॉक्स कल्वर्ट के युद्धस्तर पर चल रहे निर्माण कार्य को देखा। डीएम ने मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता अनिल कुमार यादव को निर्देश दिया कि मैनपॉवर दोगुनी करते हुए इस माह के अंततक कार्य पूर्ण किया जाए। ताकि भविष्य में जलस्तर बढ़ने पर पलिया की लाइफलाइन कहे जाने वाला यह मार्ग अवरुद्ध न हो। इस दौरान एसडीएम कार्तिकेय सिंह, सीओ यादवेंद्र, सहायक अभियंता करिश्मा रावत, अवर अभियंता मान सिंह, प्रदीप कुमार भारती मौजूद रहे।

बड़ी संख्या में चेक बाउंस मामलों का लंबित रहना गंभीर चिंता का विषयः उच्चतम न्यायालय

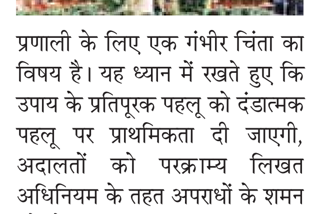

नई दिल्ली। बड़ी संख्या में चेक बाउंस के मामलों के लंबित होने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि पक्ष समझौता करने के इच्छुक हैं तो अदालतों को परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत समझौता योग्य अपराधों के निपटान को प्रोत्साहित करना चाहिए। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने चेक बाउंस मामले में पी कुमारसामी नाम के एक व्यक्ति की सजा को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है और शिकायतकर्ता को 5.25 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

पीठ ने 11 जुलाई के अपने आदेश में कहा, चेक बाउंस होने से जुड़े मामले बड़ी संख्या में अदालतों में लंबित हैं जो हमारी न्यायिक प्रणाली के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। यह ध्यान में रखते हुए कि उपाय के प्रतिपूरक पहलू को दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकता दी जाएगी, अदालतों को परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अपराधों के शमन को प्रोत्साहित करना चाहिए, यदि पक्ष ऐसा करने के इच्छुक हैं। परक्राम्य लिखत अधिनियम सभी परक्राम्य लिखतों जैसे वचन पत्र, विनिमय पत्रों और चेक संबंधी मामलों के निपटान से संबंधित है।

समझौता योग्य अपराध वे होते हैं जिनमें प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा समझौता किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि यह याद रखना होगा कि चेक का बाउंस होना एक नियामक अपराध है जिसे केवल सार्वजनिक हित को देखते हुए अपराध की श्रेणी में लाया गया है ताकि संबंधित नियमों की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। इसने अपने आदेश में कहा, परिस्थितियों की समग्रता और पक्षों के बीच समझौते पर विचार करते हुए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं तथा एक अप्रैल 2019 के लागू आदेश के साथ-साथ निचली अदालत के 16 अक्टूबर 2012 के आदेश को रद्द करके अपीलकर्ताओं को बरी करते हैं। अपीलकर्ता नंबर 2 (पी) कुमारसामी), जिसे इस न्यायालय द्वारा आत्मसमर्पण करने से छूट दी गई थी, को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

पीठ ने कहा कि 2006 में पी कुमारसामी उर्फ गणेश ने प्रतिवादी ए सुब्रमण्यम से 5,25,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन ऋण नहीं चुकाया। इसने कहा कि कर्ज चुकाने के लिए कुमारसामी ने अपनी भागीदार फर्म मेसर्स न्यू विन एक्सपोर्ट के नाम पर 5.25 लाख रुपए का चेक दिया।

पीठ ने कहा, चूंकि अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक बाउंस हो गया था, इसलिए, प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई। निचली अदालत ने 16 अक्टूबर 2012 के आदेश में अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और प्रत्येक को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसने कहा कि कुमारसामी ने अपीलीय अदालत के समक्ष दोषसिद्धि को चुनौती दी, जिसने निचली अदलत के निष्कर्षों को पलट दिया।

केरल की अदालत ने संदिग्ध माओवादी को न्यायिक हिरासत में भेजा

कोच्चि। कोच्चि की एक अदालत ने एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए संदिग्ध माओवादी को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया। उसकी सुरक्षा में कम से कम छह सशस्त्र पुलिसकर्मी मौजूद थे। मनोज ने अदालत परिसर में प्रवेश और बाहर निकलते वक्त माओवाद समर्थित नारे लगाए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, आरोपी को शनिवार को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस हिरासत संबंधी याचिका पर सुनवाई होगी। उसे आज (शुक्रवार) जिला कारागार में बंद किया गया है। केरल पुलिस के आतंकवाद-रोधी दस्ते ने मनोज को बृहस्पतिवार को दक्षिण रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। मनोज, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के 12 मामलों सहित कम से कम 16 मामलों में आरोपी है।

अदालत ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के 32 साल पुराने मामले को बंद किया

भाषा। नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने 32 साल की सुनवाई के बाद एक पूर्व आईएएस अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) का मामला बंद कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी की उम्र लगभग 90 वर्ष है और उनकी मानसिक स्थिति अस्थिर है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अनिल अंतिल ने नगालैंड सरकार के मुख्य सचिव रह चुके सुरेन्द्र सिंह अहलूवालिया के खिलाफ मामला बंद कर दिया और उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए अस्वस्थ घोषित कर दिया।

न्यायाधीश ने कहा, जब व्यवस्था विफल हो जाती है तो सत्य अन्याय की छाया में छिप जाता है। उन्होंने 12 जुलाई को पारित आदेश में कहा, यह इस मामले की पूरी कहानी और नियति है। न्यायाधीश ने कहा कि इस समय तक, मुख्य आरोपी अहलूवालिया, जो अब लगभग 90 वर्ष के हो चुके हैं, मानसिक रूप से अस्थिर और अस्वस्थ हो गए हैं और उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है (उनके खिलाफ मुकदमा पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है)।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 327 गवाहों का हवाला दिया था। न्यायाधीश ने कहा कि इनमें से 48 को होटल और अतिथि गृह जैसे अस्थाई पतों पर रहते हुए दिखाया गया था और एजेंसी को अच्छी तरह पता था कि वे कभी गवाही के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। न्यायाधीश ने कहा, शेष 200 गवाहों की या तो मृत्यु हो चुकी थी या वे अपना पता छोड़ चुके थे या अपनी बीमारियों के कारण अदालत में उपस्थित होने और गवाही देने में असमर्थ थे। अतः अंत में, वर्ष 1992 में, जब आरोप पत्र दायर किया गया था, शुरू हुए मुकदमे की इस अत्यधिक लंबी अवधि के दौरान, अर्थात लगभग 32 वर्षों के दौरान, केवल 87 गवाहों की ही जांच की गई।

सीबीआई के अनुसार, नगालैंड और नई दिल्ली में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए, अहलूवालिया ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 28 मार्च, 1987 तक अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक लगभग 68 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। न्यायाधीश ने अहलूवालिया के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह को भी बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा।

न्याय पूर्वाग्रह नही जानता, कमजोर भी ताकतवर पर हावी हो सकता है

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक भूमि विवाद पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि न्याय कोई पूर्वाग्रह नहीं जानता और इसकी मदद से कमजोर भी ताकतवर पर हावी हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा, हमारे समाज की शक्ति संरचना ऐसी है कि जो लोग कमजोर हैं वे अकसर उन लोगों द्वारा खुद को शोषित और उत्पीडि़त पाते हैं जिनके पास अधिक शक्ति है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, भूमि स्वामित्व एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम शक्ति प्रदर्शन की तलवारों को निरंतर धोखाधड़ी, छल और लालच के साथ तेज होते देखते हैं। शीर्ष अदालत की ए टिप्पणियां महाराष्ट्र के ठाणे जिले में जमीन के एक टुकड़े से जुड़े मामले में आईं। इसने कहा, न्याय कोई पूर्वाग्रह नहीं जानता और इस प्रकार, इसकी सहायता से कमजोर भी मजबूत पर हावी हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा, हालांकि हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर बाद में विस्तार से विचार करेंगे, यह उन विक्रेताओं के गलत इरादों के कारण आम आदमी द्वारा झेली जा रही निरंतर पीड़ा का एक बड़ा उदाहरण है जो या तो दबाव बनाकर या कानूनी प्रक्रियाओं में हेरफेर के माध्यम से दोहरा लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसने कहा कि कभी-कभी वादी का दुख तब और गहरा हो जाता है जब न्याय का ऐसा उपहास दशकों तक चलता है और ऐसे मामलों में कानून कमजोरों की सहायता के लिए आता है।

यमुना के डूब क्षेत्र में धार्मिक या किसी अन्य अनाधिकृत संरचना की अनुमति नहींः अदालत

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि यमुना नदी के डूब क्षेत्र (पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र) को अतिक्रमण से पूरी तत्परता के साथ संरक्षित करना पड़ेगा और इस क्षेत्र में धार्मिक या किसी अन्य संरचना को कायम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती तथा इसे आवश्यक रूप से हटाना ही पड़ेगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त करने की अनुमति दी गई है। इस मंदिर को गीता कॉलोनी क्षेत्र में नदी के पास बनाया गया है। याचिकाकर्ता प्राचीन शिव मंदिर एवं अखाड़ा समिति के पास किसी तरह की वैधता दर्शाने के लिए किसी दस्तावेज का एक टुकड़ा तक नहीं है।

खंडपीठ ने 10 जुलाई के अपने आदेश में कहा, यह स्पष्ट है कि मंदिर का निर्माण पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में अतिक्रमित भूमि पर अनधिकृत रूप से किया गया है। यदि ऐसा है, तो किसी भी धार्मिक या अन्य संरचना के मौजूद होने की अनुमति नहीं दी जा सकती और उसे आवश्यक रूप से हटाया जाना चाहिए। यमुना नदी के डूब क्षेत्र को इस तरह के अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण से तत्परता पूर्वक संरक्षित किया जाना चाहिए। इस बात का संज्ञान लेते हुए कि मंदिर की पूरी संरचना को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था, अदालत ने कहा कि आगे के विचार के लिए कुछ भी नहीं बचा है।

अपीलकर्ता ने दावा किया कि इसकी स्थापना एक प्रतिष्ठित पुजारी द्वारा एक सोसाइटी के रूप में की गई थी, जो 101 शिवलिंगों की स्थापना के लिए प्रसिद्ध हैं और यह मंदिर भी उन्हीं का हिस्सा है। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर मंदिर ध्वस्त करने के आदेश का विरोध किया कि उसे अधिकारियों से कोई औपचारिक नोटिस नहीं मिला और भूमि उत्तर प्रदेश राज्य की थी, न कि डीडीए की। अपीलकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि ध्वस्त करने की सिफारिश करने से पहले धार्मिक समिति द्वारा कोई अवसर नहीं दिया गया था।

अदालत ने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता के पास उस स्थान पर अपना स्वामित्व दिखाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, जहां मंदिर बनाया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि भूमि उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन एमओयू के अनुसार आवश्यक भूमि से किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने का काम डीडीए को सौंपा गया था। अदालत ने धार्मिक समिति द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आरोप को भी खारिज कर दिया और कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण करने वाला कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत नहीं कर सकता। अदालत ने कहा था कि भगवान शिव को किसी संरक्षण की जरूरत नहीं है और यदि यमुना नदी का किनारा एवं डूब क्षेत्र सभी तरह के अतिक्रमण से मुक्त रहता है तो वह (भगवान शिव) ज्यादा प्रसन्न होंगे।

न्यायालय चंडीगढ़-मोहाली मार्ग से प्रदर्शनकारियों को हटाने के आदेश के खिलाफ सुनवाई को सहमत

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने पर शुक्रवार को सहमति व्यक्त की, जिसमें अधिकारियों को चंडीगढ़-मोहाली मार्ग से प्रदर्शनकारियों को हटाने को कहा गया था। उच्चतम न्यायालय ने गत मई में एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के नौ अप्रैल के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शुक्रवार को एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और अन्य से नई याचिका पर जवाब मांगा। इसने इस याचिका को इसी मुद्दे को उठाने वाली एक लंबित याचिका के साथ संलग्न कर दिया। उच्च न्यायालय ने नौ अप्रैल के अपने आदेश में कहा था कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद, न तो पंजाब सरकार और न ही चंडीगढ़ प्रशासन, एसएएस नगर मोहाली और चंडीगढ़ के यात्रियों की शिकायतों का समाधान किया।

न्यायालय ने मतदाता गोपनीयता उल्लंघन संबंधी याचिका पर आदेश की समीक्षा का आग्रह खारिज किया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अपने उस आदेश की समीक्षा का आग्रह खारिज कर दिया है, जिसमें मौजूदा चुनाव प्रणाली में मतदाता गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि आदेश की समीक्षा का कोई मामला नही बनता है। इसने समीक्षा याचिका की खुली अदालत में सुनवाई के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, हमने समीक्षा याचिका और उसके समर्थन के आधारों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। हमारी राय में 17 मई 2024 के आदेश की समीक्षा का कोई मामला नही बनता है। तदनुसार, समीक्षा याचिका खारिज की जाती है। शीर्ष अदालत सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंध निदेशक एग्नोस्टो थियोस की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 17 मई के आदेश की समीक्षा का आग्रह किया गया था। थियोस ने अपनी जनहित याचिका में दावा किया था कि मतदान अधिकारी वीवीपैट पर्चियों और मतदान उपकरण में संग्रहीत डेटा को देख सकता है, जिससे मतदाता गोपनीयता का उल्लंघन होता है। उन्होंने दावा किया था, वीवीपैट पर्चियों और ईवीएम के डेटा से (पीठासीन) अधिकारी यह पहचान सकता है कि किस मतदाता ने किस पार्टी को वोट दिया है। शीर्ष अदालत ने 26 अप्रैल को ईवीएम में हेरफेर पर संदेह को निराधार करार देते हुए पुरानी मतपत्र प्रणाली बहाल किए जाने के आग्रह को खारिज कर दिया था। इसने माना था कि मतदान उपकरण सुरक्षित है और ए बूथ कैप्चरिंग तथा फर्जी मतदान को रोकते है।

1984 के दंगा मामले में दिल्ली की अदालत ने टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। दंगे के इस मामले में तीन लोग मारे गए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मामलों के विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने केंद्रीय जांच एजेंसी और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत के दो अगस्त को फैसला सुनाने की संभावना है। सीबीआई ने एक गवाह के हवाले से आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि टाइटलर एक नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाया। पूर्व केन्द्रीय मंत्री टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा था, सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है। इस घटना के बाद तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। पिछले वर्ष अगस्त में एक सत्र अदालत ने इस मामले में टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी थी। अदालत ने टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाई थी, जिनमें यह शर्तें भी थी कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नही करेंगे और बिना अनुमति के देश नही छोड़ेंगे। केंद्रीय एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (अपराध के लिए उकसाना) और 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं।

दो उच्च न्यायालयों के दस अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थाई न्यायाधीश बनाया गया

नई दिल्ली। विभिन्न उच्च न्यायालयों के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को शुक्रवार को पदोन्नत कर स्थाई न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इनमें दिल्ली उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश शामिल हैं। कानून मंत्रालय ने यह जानकारी दी। बंबई उच्च न्यायालय के सात अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थाई न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बंबई उच्च न्यायालय के ही दो अन्य अतिरिक्त न्यायाधीशों को पुन: एक साल के नए कार्यकाल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनकी नई नियुक्ति एक अक्टूबर से प्रभावी होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया, न्यायमूर्ति मनोज जैन और न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा, को भी स्थाई न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

न्यायालय एलोपैथिक, आयुष चिकित्सकों के लिए समान सेवानिवृत्ति आयु पर करेगा विचार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार की अपील पर विचार करने के लिए सहमत हो गया जिसमें कहा गया था कि एलोपैथिक चिकित्सकों और चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियों से जुड़े चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग-अलग नहीं हो सकती। एलोपैथिक चिकित्सकों की कमी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2016 से उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी जिसके कारण सरकारी आयुष (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) के चिकित्सकों की ओर से याचिकाएं दायर की गईं। सरकार द्वारा नियोजित आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि राज्य के सभी सरकारी चिकित्सकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु समान होनी चाहिए।आयुष चिकित्सकों की शिकायतों पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि वे 31 मार्च 2016 के बाद सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें 62 वर्ष की आयु तक सेवा में माना जाएगा। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राजस्थान की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर संज्ञान लिया और 10 आयुष चिकित्सकों को नोटिस जारी किए।

आरटीई आरक्षणः अदालत ने निजी स्कूलों को छूट संबंधी महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना खारिज की

भाषा। मुंबई

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से नौ फरवरी को जारी उस अधिसूचना को शुक्रवार को रद्द कर दिया जिसमें सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों के एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत आरक्षित दाखिले से छूट दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 21 और बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का

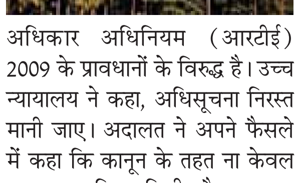

अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के प्रावधानों के विरुद्ध है। उच्च न्यायालय ने कहा, अधिसूचना निरस्त मानी जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कानून के तहत ना केवल सरकार, बल्कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों का भी कर्तव्य है कि वे समाज के वंचित वर्ग के छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। अनुच्छेद 21-ए के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश लगभग निरपेक्ष है। अदालत ने कहा कि आरटीई अधिनियम के प्रावधान यह कहते हैं कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल भी इस तरह के अनिवार्य कर्तव्य का हिस्सा होंगे। पीठ ने कहा कि यदि आरटीई अधिनियम का उद्देश्य पूरी तरह से हासिल नहीं किया गया, तो इसका परिणाम लोगों को संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत उल्लिखित मौलिक अधिकार से वंचित करना होगा। हालांकि, पीठ ने कहा कि मई में अधिसूचना के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से पहले कुछ निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों ने छात्रों को प्रवेश दिया था।

न्यायालय ने 2024 में नीट-एसएस आयोजित न करने के फैसले के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2024 में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस) आयोजित नही करने के राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और अन्य से जवाब मांगा। नीट-एसएस उन चिकित्सकों के लिए आयोजित की जाती है, जिनके पास एमडी, एमएस और डीएनबी जैसी स्नातकोत्तर डिग्री या सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समकक्ष योग्यता है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को 13 उम्मीदवारों की ओर से पेश एक वकील ने बताया कि एनएमसी ने इस साल परीक्षा आयोजित नही करने का फैसला किया है।

पेज 1 का शेष

वैश्विक स्तर...

का उपयोग कर रहे हैं। हमारे आकलन से पता चलता है कि केवल 10 बैंकों और एनबीएफसी में मामूली व्यवधान थे जिन्हें या तो हल कर लिया गया है या हल किया जा रहा है। कुल मिलाकर बयान में कहा गया है कि रिज़र्व बैंक के क्षेत्र में भारतीय वित्तीय क्षेत्र वैश्विक आउटेज से अछूता है।ऑटो प्रमुख मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा कि यह माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम के वैश्विक आउटेज से आंशिक रूप से प्रभावित हुआ और उत्पादन और प्रेषण परिचालन कुछ समय के लिए रुक गया। हालाँकि, कंपनी ने कहा कि वह परिचालन फिर से शुरू करने में सक्षम है। ऑस्टिन, टेक्सास स्थित कंपनी के नैस्डैक-ट्रेडेड शेयर शुक्रवार की शुरुआत में प्रीमार्केट ट्रेडिंग में लगभग 15 प्रतिशत नीचे थे।

न्यूजीलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, डेविड सेमुर ने कहा कि देश में अधिकारी संभावित प्रभावों को समझने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो यह दर्शाती हो कि यह एक साइबर सुरक्षा खतरा है।अमेरिका में एफएए ने कहा कि यूनाइटेड, अमेरिकन, डेल्टा और एलीगेंट सभी एयरलाइंस को बंद कर दिया गया है। यूके में एयरलाइंस और रेलवे भी प्रभावित हुए, प्रतीक्षा समय सामान्य से अधिक बढ़ गया। जर्मनी में, बर्लिन-ब्रैंडेनबर्ग हवाई अड्डे ने यात्रियों की जाँच में कठिनाइयों के कारण कई घंटों तक उड़ानें रोक दीं, जबकि ज्यूरिख हवाई अड्डे पर लैंडिंग निलंबित कर दी गई और हंगरी, इटली और तुर्की में उड़ानें बाधित हो गईं। डच वाहक केएलएम ने कहा कि उसे अपने अधिकांश परिचालन को निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एम्स्टर्डम के शिफोल हवाई अड्डे ने चेतावनी दी कि इस रुकावट का व्यस्त यूरोपीय केंद्र से आने-जाने वाली उड़ानों पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलियाई हवाई अड्डों पर व्यापक समस्याएं दर्ज की गईं, जहां लाइनें बढ़ गईं और कुछ यात्री फंसे हुए थे क्योंकि ऑनलाइन चेक-इन सेवाएं और स्वयं-सेवा बूथ अक्षम कर दिए गए थे - हालांकि उड़ानें अभी भी चल रही थीं। भारत, हांगकांग और थाईलैंड में, कई एयरलाइनों को यात्रियों की मैन्युअल जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा। केन्या में एक एयरलाइन भी व्यवधान की रिपोर्ट कर रही थी। जबकि दुनिया भर में बिजली कटौती का अनुभव किया जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया इस मुद्दे से गंभीर रूप से प्रभावित दिखाई दिया।

देश में कई...

सेवाएं प्रभावित हुई हैं और वह यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए काम कर रहा है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर औसतन 51 मिनट की देरी हुई, दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर इसकी सेवाओं में लगभग 40 मिनट की देरी हुई। बेंगलुरु में, टर्मिनल 1 से संचालित होने वाली 90 प्रतिशत उड़ानें प्रभावित हुई हैं और एयरलाइंस यात्रियों की जांच के लिए मैन्युअल तरीकों का उपयोग कर रही हैं। हैदराबाद हवाई अड्डे पर 160 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं।चूंकि चेक-इन मैन्युअल रूप से किया जा रहा है, इसलिए धीमी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को लगभग तीन घंटे पहले (यहां तक ??कि घरेलू उड़ानों के लिए भी) हवाईअड्डों पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। जबकि अभी तक यहां कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई थी और चेक-इन मैन्युअल तरीके से होने के कारण फ्लाइट्स में देरी हो रही थी। डीजीसीए ने तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए एयरलाइंस से यात्रियों को यथासंभव देरी के बारे में सूचित करने को कहा है।अधिकांश एयरलाइंस ने फ्लायर्स के साथ अपडेट साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का सहारा लिया। एयर इंडिया ने कहा कि उसके डिजिटल सिस्टम वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण अस्थायी रूप से प्रभावित हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप देरी हुई है। इंडिगो ने चेतावनी दी कि चेक-इन धीमा हो सकता है और कतारें लंबी हो सकती हैं।कम लागत वाले वाहक ने यह भी कहा कि उड़ान को दोबारा बुक करने या रिफंड का दावा करने का विकल्प अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। स्पाइसजेट ने कहा कि वह व्यवधानों को कम करने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अकासा एयर ने कहा कि उसकी ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। विस्तारा ने भी कहा कि वह तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रही है और इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 23 उड़ानें - 12 प्रस्थान और 11 आगमन - देखी गईं, जिनमें विशाखापत्तनम, तिरूपति, अहमदाबाद और बेंगलुरु के लिए इंडिगो की उड़ानें भी रद्द की गईं। जीएमआर द्वारा संचालित हवाईअड्डा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा गया, हम अपने यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए अपने सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप कृपया अपनी उड़ान की जानकारी के अपडेट के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

सीएम योगी...

कि वे कहां बैठे हैं। नकवी ने फैसले की आलोचना की और कहा कि जल्दबाजी में दिए गए आदेश से छुआछूत की बीमारी को बढ़ावा मिल सकता है। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अस्पृश्यता को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से इस सलाह का विरोध करते हुए कहा कि वह जाति या धर्म के नाम पर किसी भी विभाजन का 'बिल्कुल समर्थन या प्रोत्साहन नहीं करेंगे'। उन्होंने कहा, हमें इन दो वर्गों के लोगों के बीच की खाई को पाटने की जरूरत है। गरीबों के लिए काम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें समाज के सभी वर्ग जैसे दलित, पिछड़े, ऊंची जातियां और मुस्लिम भी शामिल हैं। सभी वहां हैं। हमें इसकी जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, जब भी जाति या धर्म के नाम पर इस तरह का विभाजन होता है, तो मैं न तो इसका समर्थन करता हूं और न ही इसे प्रोत्साहित करता हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र का कोई भी शिक्षित युवा, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से आता हो। ऐसी चीजों से प्रभावित होता है। उन्होंने आगे कहा, जब भी जाति या धर्म के नाम पर इस तरह का विभाजन होता है, तो मैं न तो इसका समर्थन करता हूं और न ही इसे प्रोत्साहित करता हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र का कोई भी शिक्षित युवा, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से आता हो। ऐसी चीजों से प्रभावित होता है। एक अन्य भाजपा सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) ने भी उस सलाह की आलोचना की, जिस पर पुलिस ने जोर दिया है, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कांवड़ियों के बीच कोई भ्रम न हो और कोई कानून न हो- एवं-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस निर्देश की आलोचना की और इसे 'भारत की संस्कृति पर हमला' बताया, आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार को सामान्य बनाना है। प्रियंका गांधी ने कहा, हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ठेले, खोमचे और दुकानों के मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझा विरासत पर एक हमला है। योगी के नवीनतम संदेश पर नकवी ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश से उत्पन्न 'भ्रम' को दूर कर दिया है, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था और कहा कि अब उसने पवित्रता के लिए एक दिशानिर्देश दिया है।

राज्यपालों के...

अदालत ने इस मामले से निपटने में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से सहायता करने को कहा। महिला का नाम न्यायिक रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। महिला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने सुनवाई की शुरुआत में कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जांच ही न हो। सबूत अभी एकत्र किए जाने चाहिए। राज्यपाल के पद छोड़ने तक इसे अनिश्चित काल के लिए टाला नहीं जा सकता। याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 361 के खंड दो के तहत राज्यपालों को दी गई छूट जांच पर रोक नहीं लगा सकती और वैसे भी, ऐसे मामलों की जांच में समय का बहुत महत्व है। पीठ ने राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी करते हुए अपने आदेश में कहा, याचिका में संविधान के अनुच्छेद 361 के खंड (2) के तहत राज्यपाल को दिए गए संरक्षण के दायरे से संबंधित मुद्दा उठाया गया है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों के संरक्षण से संबंधित है और इसका खंड दो कहता है- राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। महिला याचिकाकर्ता ने राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन से छूट प्रदान करने के संबंध में विशिष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है, इस अदालत को यह तय करना है कि क्या याचिकाकर्ता जैसी पीड़िता के पास राहत पाने का कोई उपाय नहीं है, जबकि एकमात्र विकल्प आरोपी के पद छोड़ने तक इंतजार करना है और सुनवाई के दौरान यह देरी अतार्किक होगी और पूरी प्रक्रिया महज दिखावा बनकर रह जाएगी, जिससे पीड़िता को कोई न्याय नहीं मिलेगा।

खेडकर के...

दिया गया। उन्हें सिविल सेवा परीक्षा 2022 में योग्य घोषित किया गया था। यूपीएससी द्वारा पिछले साल घोषित परिणामों के आधार पर खेडकर को आईएएस और उनके गृह राज्य महाराष्ट्र को कैडर के रूप में आवंटित किया गया था। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा-2022 की अनंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवार सुश्री पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के दुर्व्यवहार की विस्तृत और गहन जांच की है। आयोग ने कहा, इस जांच से पता चला है कि उसने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर/हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी पहचान बदलकर धोखाधड़ी से परीक्षा नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयास का लाभ उठाया। इसलिए, यूपीएससी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें पुलिस अधिकारियों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करके आपराधिक मुकदमा चलाना शामिल है और 'सिविल सेवा परीक्षा -2022 की उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस' जारी किया है। सिविल सेवा परीक्षा-2022 के नियमों के अनुसार, भविष्य की परीक्षाओं/चयनों से वर्जित किया जाएगा। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था ने कहा, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में, यूपीएससी अपने संवैधानिक जनादेश का सख्ती से पालन करता है और सभी परीक्षाओं सहित अपनी सभी प्रक्रियाओं को बिना किसी समझौते के उचित परिश्रम के उच्चतम क्रम के साथ आयोजित करता है, इसमें कहा गया है कि यूपीएससी ने अत्यंत निष्पक्षता और नियमों के सख्त पालन के साथ अपनी सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की पवित्रता और अखंडता सुनिश्चित की है। बयान में कहा गया है, यूपीएससी ने जनता, विशेषकर उम्मीदवारों से उच्च स्तर का विश्वास और विश्वसनीयता अर्जित की है।

आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल हो : शाह

भाषा। नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में उभरते सुरक्षा खतरे के परिदृश्य से निपटने के लिए आतंकी नेटवर्क और उसके सहायक परिवेश को खत्म करने के लिए, सुरक्षा और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल पर शुक्रवार को जोर दिया। शाह ने एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुरक्षा एजेंसियों और अन्य खुफिया और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के प्रमुखों को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। गृह मंत्री ने खुफिया ब्यूरो के मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) के कामकाज की भी समीक्षा की, जिसके पास देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि शाह ने देश में उभरते सुरक्षा खतरे के परिदृश्य से निपटने के लिए आतंकी नेटवर्क और उसके सहायक परिवेश को खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एमएसी को विभिन्न हितधारकों के बीच कार्वाई योग्य खुफिया जानकारी को सक्रिय और वास्तविक समय पर साझा करने को लेकर एक मंच के रूप में 24 घंटे सातों दिन काम करना जारी रखना चाहिए। देश की समग्र आंतरिक सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की समीक्षा करते हुए, गृह मंत्री ने बैठक के सभी हितधारकों से एमएसी के साथ जुड़ाव बढ़ाने और इसे एक सुसंगत मंच बनाने पर जोर दिया, जो निर्णायक और त्वरित कार्वाई के लिए, सभी कानून प्रवर्तन, मादक पदार्थ निरोधक, साइबर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को एक साथ लाए। बैठक के दौरान, शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियों से युवा, तकनीकी रूप से कुशल और उत्साही अधिकारियों की एक टीम गठित करने पर भी जोर दिया, ताकि बड़े डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग आधारित विश्लेषण और तकनीकी प्रगति का उपयोग करके आतंकवाद के तंत्र को नष्ट किया जा सके।

कांग्रेस परजीवी पार्टी, गठबंधन सहयोगियों को ही कमजोर करती है पार्टी : नड्डा

पुरी (ओडिशा)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कांग्रेस को एक परजीवी पार्टी करार दिया, जो दूसरों के वोटों की बैसाखी पर खड़ी है और गठबंधन सहयोगियों को कमजोर कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा की ओडिशा इकाई की कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, जिन लोगों ने संविधान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है, वे अब सत्ताधारी दल को सिखा रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जाए। नड्डा ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा, कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन गई है और दूसरों के वोटों की बैसाखी पर खड़ी है। जिन लोगों ने संविधान को सबसे ज्यादा चोट

पहुंचाई है, वे अब हमें सिखा रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जाए। राहुल गांधी को पता नहीं है कि उनकी दादी (इंदिरा गांधी) ने संविधान का किस अलग तरीके से इस्तेमाल किया था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने अतीत में 90 बार निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया जबकि केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कभी भी अन्य दलों की सरकारों को बर्खास्त नहीं किया है। नड्डा ने भारत के लोगों के बीच भाजपा की स्वीकार्यता पर प्रकाश डालते हुए दावा किया कि देश की 57 प्रतिशत आबादी भाजपा का समर्थन करती है और पार्टी की सरकारें देश के 58 प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई हैं। नड्डा ने कहा, हम (भाजपा) एक अखिल भारतीय पार्टी हैं, जिसकी 18 राज्यों में गठबंधन की सरकार हैं और इनमें से 13 में अकेले भाजपा की सरकार है। दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख सहित 13 राज्यों में कांग्रेस शून्य है।

असम 2041 तक मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा: हिमंत

भाषा। गुवाहाटी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में लगभग 30 प्रतिशत बढ़ रही है और 2041 तक वे बहुसंख्यक हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सांख्यिकीय नमूने के अनुसार असम में मुस्लिम आबादी 40 प्रतिशत है। शर्मा ने कहा, 2011 में असम में 1.4 करोड़ मुसलमान थे। 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। यह एक वास्तविकता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, असम में कुल मुस्लिम आबादी 1.07 करोड़ थी जो कुल 3.12 करोड़ निवासियों का 34.22 प्रतिशत थी। राज्य में 1.92 करोड़ हिंदू थे जो कुल आबादी का लगभग 61.47 प्रतिशत था। मुख्यमंत्री ने कहा, हर 10 साल में असम में मुस्लिम आबादी 11 लाख बढ़ जाती है... यह हिमंत विश्व शर्मा का डेटा नहीं है, बल्कि भारतीय जनगणना का डेटा है। ए सभी प्रकाशित डेटा हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय की आबादी हर 10 साल में लगभग 16 प्रतिशत बढ़ रही है। शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कई लोगों ने हमारी मदद भी की है। अगर निजुत मोइना योजना सफल होती है तो लड़कियां चिकित्सक और इंजीनियर बनेंगी। फिर वे (बच्चों को) जन्म नहीं देंगी। इस योजना के तहत असम सरकार बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को अगले पांच वर्षों तक 2,500 रुपए तक का मासिक मानदेय प्रदान करती है। उन्होंने कहा,"पिछले तीन वर्षों में हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से हमें कुछ परिणाम मिलेंगे, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा, 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा।

असम में दो वर्षों में किशोरावस्था में गर्भधारण के मामलों में 64 प्रतिशत की कमी आई: सीएम

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को दावा किया कि बाल विवाह के खिलाफ सरकार के अभियान के परिणामस्वरूप पिछले दो वर्ष में राज्य में किशोरावस्था मे गर्भधारण के मामलो मे लगभग 64 प्रतिशत की कमी आई है। शर्मा ने कहा कि यह प्रवृत्ति एक राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा हाल में किए गए आकलन में देखी गई, जिसने बाल विवाह के खिलाफ कड़े कानूनों की उपयोगिता पर असम के 3,000 गांवों का सर्वेक्षण किया था।शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बाल विवाह के खिलाफ हमारा अभियान न केवल सामाजिक परिवर्तन ला रहा है,।

श्रृंगेरी के शारदा मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए परिधान के नियम अनिवार्य किए गए

चिक्कमगलुरू (कर्नाटक)। (श्रृंगेरी स्थित शारदम्बा मंदिर ने 15 अगस्त से मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए परिधान संबंधी नियम लागू किया है। मंदिर प्रशासन के एक बयान के अनुसार मंदिर में दर्शन के लिए आने वालों को केवल पारंपरिक भारतीय परिधान पहनने की अनुमति होगी। इसमे स्पष्ट किया गया है कि श्रद्धालुओं को श्रृंगेरी शारदा मंदिर और तुंगा नदी के पार स्थित शंकराचार्य गुरु के मठ में जाते समय पारंपरिक भारतीय पोशाक पहननी होगी। परिधान संबंधी नियमों का पालन नही करने वालो को अर्ध मंडपम के बाहर से ही भगवान के दर्शन करने की अनुमति होगी। उन्हें गर्भगृह और आंतरिक परिक्रमा तक पहुंचने की अनुमति नही होगी। मंदिर मे आने वाले सभी भक्तो पर परिधान संबंधी यह नियम 15 अगस्त से सख्ती से लागू होगा। इसमे कहा गया है कि निर्धारित परिधान मे पुरुषो के लिए धोती और अंगवस्त्रम और महिलाओं के लिए साड़ी-ब्लाउज, सलवार-दुपट्टा शामिल है।

ओला इलेक्ट्रिक वाहनों पर देगा जोर

नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक अपने ओला एस1 स्कूटरों की खरीद पर 25,000 रुपये तक के आकर्षक बेनेफिट्स प्रदान कर रहा है। 22 जुलाई तक लागू इन ऑफरों में एस1 एक्स पर 10,000 रुपये और एस1 प्रो एवं एस1 एयर पर 5ए000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी चुनिंदा क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर ग्राहकों को 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दे रही है। इन ऑफ.रों के अलावा ग्राहकों को ईएमपीएस 2024 के अंतर्गत 10,000 रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी। इन आकर्षक ऑफ़रों का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को कीमतें बढ़ने से पहले ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदकर उसे रजिस्टर कराना होगा। ओला इलेक्ट्रिक एक विशाल एस1 पोर्टफोलियो पेश करता है, जिसमें आकर्षक मूल्य में छः उत्पाद हैं, जो विभिन्न रेंज की जरूरत वाले ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं।

इसुज़ू का मॉनसून कैम्प' 22 जुलाई तक

मुंबई। इसुज़ू मोटर्स इंडिया ने वाहन स्वामित्व का बेहतरीन और अतुलनीय अनुभव प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ पूरे देश में 'इसुज़ू आई केयर मॉनसून कैम्प' की घोषणा की है। इसुज़ू डी-मैक्स पिक-अप और एसयूवी के लिए डिजाइन किए गये ये शिविर पूरे देश में इसुज़ू वाहन मालिकों को आकर्षक लाभ और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जाँच प्रदान करेंगे। इसुज़ू केयर' द्वारा 10 से 22 जुलाई 2023 (ये दोनों दिन भी शामिल) के बीच सभी अधिकृत इसुज़ू डीलर सर्विस आउटलेट्स पर एक मॉनसून कैम्प लगाया जा रहा है। इस अवधि में ग्राहकों को उनके वाहनों के लिए विशेष ऑफर और लाभ दिये जा रहे हैं। इस शिविर में आने वाले ग्राहकों को निम्नलिखित लाभ होंगे। मुफ़्त 37-पॉइंट विस्तृत जाँच, लेबर पर 10प्रतिशज की छूट,पार्ट्स पर 5प्रतिशत की छूट,ल्यूब और फ्लूइड पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

राज्यपाल के खिलाफ ममता बनर्जी ने दायर की अपील

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष अपील दायर करके एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमे उन्हे और तीन अन्य को राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस के खिलाफ कोई मानहानिकारक या गलत बयान देने से रोक दिया गया था। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने राज्यपाल द्वारा दायर मानहानि वाद पर मंगलवार को यह अंतरिम आदेश पारित किया था। तृणमूल कांग्रेस के दो नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण से जुड़े विवाद पर बोलते हुए बनर्जी ने कुछ टिप्पणियां की थी, जिसके खिलाफ बोस ने वाद दायर किया है। बनर्जी ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी, जो 14 अगस्त तक के लिए है। अब इसे एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

विश्व धरोहर समिति का सत्र भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को कहा कि जी20 की मेजबानी के बाद 21 से 31 जुलाई तक यहां आयोजित विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र मील का पत्थर साबित होगा। सत्र से पहले यहां एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। हालांकि, बाद में संस्कृति मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 21 जुलाई को सत्र का उद्घाटन करेंगे। यह पहली बार है जब सत्र भारत में आयोजित किया जा रहा है। शेखावत ने कहा कि विश्व धरोहर समिति (डब्ल्यूएचसी) का सत्र भारत को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अपने स्थलों के रख-रखाव और प्रबंधन तथा भारत द्वारा अपनी विरासत को दी जाने वाली प्राथमिकता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। यह पूछे जाने पर कि इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए मेजबान शहर के रूप में दिल्ली को किस मानदंड के तहत चुना गया, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण इस आयोजन के लिए दिल्ली स्वाभाविक पसंद थी। डब्ल्यूएचसी के सत्र से पहले, सरकार ने हाल में एक लोक कला परियोजना शुरू की है, जिसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत और देश के यूनेस्को विरासत स्थलों पर आधारित कार्य शामिल हैं। विश्व धरोहर सम्मेलन का सत्र भारत मंडपम में होगा, जो जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल भी था।

ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर चार हुई

भाषा। गोंडा

उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई है, जबकि 31 लोग घायल हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद शुक्रवार की शाम पहली मालगाड़ी चलाई गई। इस बीच घटना के कारणों की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) 21 जुलाई को हादसे की जांच करेंगे। गोंडा की जिलाधिकारी ने भी घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में रेल पटरियों के मरम्मत का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। रेल प्रशासन का दावा है कि देर रात तक आवागमन बहाल कर दिया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा-गोरखपुर रेल खंड पर मोतीगंज और झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच बृहस्पतिवार दोपहर को ट्रेन के आठ डिब्बे पटरी से उतर गए थे। गोंडा की जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा, अब तक चार यात्रियों की मौत हो चुकी है और 32 घायल हैं। घायलों में से करीब छह की हालत गंभीर है। शर्मा ने कहा, मृतकों में राहुल (38), सरोज कुमार सिंह (31) तथा दो अज्ञात शामिल हैं। अज्ञात में से एक व्यक्ति का शव आज सुबह बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप घायल दो यात्रियों का उपचार लखनऊके ट्रामा सेंटर में किया जा रहा है। आधिकारिक बयान में शर्मा ने कहा कि दुर्घटना के कुछ घंटों बाद बृहस्पतिवार रात जब चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 600 यात्रियों को एक विशेष ट्रेन से असम के लिए रवाना किया गया वह उस समय मनकापुर जंक्शन पर मौजूद थीं। जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने कई यात्रियों से बातचीत की और उनमें से किसी ने भी अपने सहयोगी के लापता होने की शिकायत नहीं की। उन्होंने यह भी बताया कि रेल की पटरियों की मरम्मत का काम जारी है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी शर्मा सुबह में जिला अस्पताल पहुंचीं तथा यहां भर्ती घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना।

रूसी सशस्त्र बलों में कार्यरत 50 भारतीय छोड़ना चाहते हैं नौकरी : विदेश मंत्रालय

भाषा। नई दिल्ली

रूस के सशस्त्र बलों में कार्यरत भारतीयों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत और रूस काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ और नौ जुलाई की दो दिवसीय मॉस्को यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें लगभग 50 भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी है जो वर्तमान में रूसी सशस्त्र बलों की नौकरी छोड़ना चाहते हैं। प्रवक्ता ने अपने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, ए ऐसे मामले हैं जिनमें व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों ने उनकी सेवा की यथाशीघ्र समाप्ति सुनिश्चित करने में सहायता के लिए हमसे संपर्क किया है। जायसवाल ने कहा कि इस मुद्दे को रूस के साथ नेतृत्व स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने अपनी हालिया रूस यात्रा के दौरान इस मामले को उठाया था।

विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने यूक्रेनी समकक्ष के साथ फोन पर बात की

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को फोन पर यूक्रेन के अपने समकक्ष दमित्रो कुलेबा के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मॉस्को यात्रा के करीब दस दिन बाद दोनो नेताओं के बीच यह वार्ता हुई है। जयशंकर ने कहा कि बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने पर केंद्रित थी। दोनो देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत मोदी की आठ-नौ जुलाई की मॉस्को यात्रा की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की द्वारा आलोचना किए जाने की पृष्ठभूमि मे हुई। जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, आज दोपहर मे यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा के साथ एक अच्छी बातचीत हुई।

गुजरात के कुछ जिलों में भारी बारिश, पोरबंदर तालुका में 36 घंटे में 565 मिमी वर्षा

भाषा। पोरबंदर

गुजरात के पोरबंदर, जूनागढ़ और देवभूमि द्वारका जिले में शुक्रवार शाम छह बजे तक पिछले 36 घंटे की अवधि में भारी बारिश हुई। वहीं, पोरबंदर तालुका में इस अवधि के दौरान 565 मिलीमीटर बारिश हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अगले चार दिनों में पोरबंदर में और बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण इन जिलों के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे कुछ सड़कें, पुल और अंडरपास बंद होने से यातायात बाधित हुआ और लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, सौराष्ट्र क्षेत्र के पोरबंदर तालुका में शाम छह बजे तक पिछले 36 घंटे की अवधि में सबसे ज्यादा 565 मिमी बारिश हुई। इसके बाद देवभूमि द्वारका के कल्याणपुर तालुका में 412 मिमी, जूनागढ़ के केशोद तालुका में 401 मिमी, वंथली में 353 मिमी और पोरबंदर के राणावाव में 330 मिमी बारिश हुई। पोरबंदर के जिलाधिकारी केडी लखानी ने संवाददाताओं को बताया, भारी बारिश और तटीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है।

राष्ट्रपति ने सेनाध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया

भाषा। नई दिल्ली

राष्ट्रतपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को राष्ट्र के प्रति उनकी विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक (पीवीएसएम) से सम्मानित किया। रक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के 94 कर्मियों को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। रक्षा अलंकरण समारोह का पहला चरण पांच जुलाई को आयोजित किया गया था। उस समय राष्ट्रपति ने कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस और असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के 10 जवानों को कीर्ति चक्र प्रदान किए थे जिनमें से सात को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। कीर्ति चक्र भारत में शांतिकाल के दौरान वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा शीर्ष अलंकरण हैं। विज्ञप्ति के मुताबिक, शुक्रवार को आयोजित समारोह के दूसरे चरण में राष्ट्रपति ने 31 पीवीएसएम, चार यूवाईएसएम (उत्तम युद्ध सेवा पदक), दो एवीएसएम (अति विशिष्ट सेवा पदक) और 57 एवीएसएम (अति विशिष्ट सेवा पदक) प्रदान किए। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी को शुक्रवार को पीवीएसएम से सम्मानित किया गया। पीवीएसएम से सम्मानित होने वाले अन्य अधिकारियों में लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिन्द्र कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि, लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू और एयर मार्शल रवि गोपाल कृष्ण कपूर के अलावा सेना और भारतीय वायु सेना के कई सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन ने एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में समारोह की तस्वीरें साझा कीं।
सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक पोस्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया।

एनसीएपी कोष का दो-तिहाई हिस्सा धूल प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया गया: रिपोर्ट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 131 शहरों को आवंटित धनराशि का लगभग दो-तिहाई हिस्सा धूल प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया गया है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रतिशत से भी कम का उपयोग किया गया है। एक नई रिपोर्ट में शुक्रवार को यह बात कही गई। साल 2019 में शुरू किया गया एनसीएपी स्वच्छ वायु लक्ष्य निर्धारित करने का भारत का पहला राष्ट्रीय प्रयास है। इसका लक्ष्य 2017 को आधार वर्ष मानकर 2024 तक पीएम10 प्रदूषण में 20-30 प्रतिशत की कमी लाना है। संशोधित लक्ष्य 2019-20 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करते हुए 2026 तक इस प्रदूषण में 40 प्रतिशत की कटौती का है।

धार्मिक गलियारेः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रकाश और ध्वनि शो शुरू करने का निर्देश दिया

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर बनने वाले धार्मिक गलियारों या लोक पर विभिन्न घटनाओं को दर्शाने वाले प्रकाश और ध्वनि शो विकसित किए जाने चाहिए। यादव ने मप्र में बनाए जा रहे विभिन्न धार्मिक गलियारों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि ओरछा में निर्माणाधीन रामराजा लोक में भगवान राम के वनवास से संबंधित घटनाओं को दर्शाया जाए। उन्होंने इन स्थानों के महत्व को उजागर करने के लिए ऐसे गलियारों पर प्रकाश और ध्वनि शो बनाने का भी आदेश दिया। एक अधिकारी ने मुख्यमंत्री के हवाले से बताया कि इन गलियारों के लिए संस्कृति, पर्यटन, बंदोबस्त, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास विभाग जैसे संबंधित विभागों के स्थानीय स्तर पर समन्वय किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि राज्य पर्यटन विभाग 18 लोक विकसित कर रहा है, जिसमे 14 धर्म पर आधारित और चार संस्कृति पर आधारित हैं। धर्म पर आधारित 10 और संस्कृति पर आधारित चार लोक पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियो से श्रद्धालुओ और आगंतुकों के लिए आसपास के बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं का विकास सुनिश्चित करने को कहा।

भाजपा के पास अपने 10 साल के कार्यकाल का एक भी काम दिखाने के लिए नहीं हैः भूपेंद्र हुड्डा

रोहतक। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस 2014 से सत्ता मे न रहने के बावजूद भी अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि राज्य मे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास अपने 10 साल के कार्यकाल का एक भी काम दिखाने के लिए नही है। हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कुछ भी हासिल नही कर पाई इसलिए वह अपने काम का हिसाब नही दे पा रही है और कांग्रेस से जवाब मांग रही है। हरियाणा मे इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 15 जुलाई को हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया, जिसके तहत वह बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और किसानों की समस्याओं सहित कई मुद्दों पर भाजपा को आड़े हाथों ले रही है। हुड्डा ने कहा, सत्ता पक्ष विपक्ष से हिसाब मांग रहा है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी हास्यास्पद बात हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए या विपक्ष में रहते हुए हमेशा अपने काम का हिसाब दिया है क्योंकि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र मे विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की है। हुड्डा ने भाजपा नेता अमित शाह के महेंद्रगढ़ के हालिया दौरे का भी जिक्र किया, जिस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर हुड्डा पर निशाना साधा था।

टाटा प्ले बिंज से लें मानसून का आनंद

मुंबई। इस बारिश के मौसम में टाटा प्ले बिंज ने अपने दर्शको के लिए बनाया एक बेहतरीन लिस्ट जिनका लुफ्त गर्मागर्म चाय और भजिए के साथ उठाया जा सकता है। इन सुहाने दिनों में अगर पूरा दिन बिस्तर पर लेटकर मौसम का आनंद लेने की योजना हो या फिर बारिश के कारण बाहर जाने की योजना निरस्त हो गई हो, दोनों ही स्थितियों में टाटा प्ले बिंज आपके मनोरंजन का उत्तम साथी है। टाटा प्ले बिंज पर बारिश के मौसम के लिए विभिन्न ओटीटी मंचों के बेहतरीन कार्यक्रमों का संग्रह पेश किया गया है। अगर आप अपनी जेब पर भार डाले बिना ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं, तो इसका हल टाटा प्ले बिंज के पास है। इस अकेले ऐप पर आप एक ही छत के नीचे सबसे कम सदस्यता शुल्क में 30 से ज्यादा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ऐप्स के कार्यक्रम देख सकते हैं। इस मौसम में अमेज़न प्राईम के पंचायत एवं अन्य कार्यक्रम, डिज़्नी हॉटस्टार पर लीजेंड्स ऑफ हनुमान, सोनी लिव के गुल्लक और ओटीटी की दुनिया के कई अन्य बेहतरीन कार्यक्रम टाटा प्ले बिंज पर देखिए। इसलिए टाटा प्ले बिंज डाउनलोड करके बारिश के मौसम को और ज्यादा मनोरंजक बनाईये! मिर्जापुर;सारे सीज़न- अमेज़न प्राईम वीडियो- मिर्जापुर एक दिलचस्प भारतीय अपराध थ्रिलर है, जो उत्तर प्रदेश के एक अराजकतापूर्ण शहर की कहानी पेश करता है। इस सीरीज़ में गुड्डू और बबलू पंडित ताकत, ड्रग्स, और हिंसा की दुनिया में उतर पड़ते हैंए जिस पर एक निर्दयी माफिया डॉन, कालीन भैया का राज चलता है। सनफ्लॉवर सभी सीज़न- ज़ी5-सनफ्लॉवर अपनी तरह की एक अलग मौत की गुत्थी पर आधारित सीरीज़ है। इसमें पहले धारावाहिक से ही दिलचस्पी बन जाती है। इसमें सनफ्लॉवर नाम की एक मध्यमवर्गीय आवासीय संस्था के निवासियों का दैनिक जीवन दिखाया गया है।

मोबाईल इमेजिंग को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली। ऑनर ने भारत में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए आज ऑनर 200 सीरीज़ लॉन्च की। यह इसकी प्रतिष्ठित नंबर सीरीज़ में सबसे नया लॉन्च है। इस सीरीज़ में ऑनर 200 प्रो 5जी और ऑनर 200 5जी हैं, जो पॉवर और क्रिएटिविटी के दायरे बढ़ाकर ग्राहकों को अत्याधुनिक एआई पॉवर्ड पोर्ट्रेट क्षमताएंए आकर्षक डिस्प्लेए मजबूत हार्डवेयर परफॉर्मेंस, और इन्ट्यूटिव यूज़र केंद्रित एआई अनुभव प्रदान करेंगे। ऑनर 200 प्रो 5जी दो खूबसूरत रंगों . ओशन स्यान और ब्लैक में 57ए999 रुपये में 20 जुलाई अर्द्धरात्रि 12 बजे से अमेज़न इन पराए ब्रांड की वेबसाईट पर और आपके नजदीकी मेनलाइन रिटेल स्टोर्स पर मिलना शुरू होगा। 20 और 23 जुलाई को यह स्मार्टफोन खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 8000 रुपये की तत्काल छूट मिलेगी। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 3000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके अलावा ग्राहकों को कुछ चुनिंदा मेनलाइन स्टोर्स में 8ए499 रुपये मूल्य के मुफ़्त ऑनर उपहार मिलेंगे या इसके बदले 2000 रुपये की तत्काल कूपन छूट दी जाएगी। ऑनर 200 5जी भी दो रंगों के विकल्पों . मूनलाईट व्हाईट और ब्लैक में उपलब्ध होगा। यह स्मार्टफोन दो वैरिएंट्स में मिलेगा। इसके 12जीबी512जीबी वैरिएंट का मूल्य 39ए999 रुपये और 8जीबी256जीबी वैरिएंट का मूल्य 34,999 रुपये होगा। इस लॉन्च के बारे में सी पीण् खंडेलवाल जॉईंट मैनेजिंग डायरेक्टर एचटेक ने कहा कि ऑनर 200 सीरीज़ का लॉन्च भारत में स्मार्टफोन का अत्याधुनिक अनुभव प्रदान करते रहने के हमारे सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पीतांबर आचार्य को ओडिशा का नया महाधिवक्ता

भुवनेश्वर। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए मुकदमा लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पीतांबर आचार्य को शुक्रवार को ओडिशा का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। इस संबंध मे जारी एक अधिसूचना मे कहा गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के खंड(1) के अनुसरण में, ओडिशा के राज्यपाल उड़ीसा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पीतांबर आचार्य को तत्काल प्रभाव से राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करते हुए प्रसन्नता महसूस करते है। आचार्य (59) ने 2019 के विधानसभा चुनाव में हिन्जिली सीट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था।

शेरवानी पैबल्स जंगल के अनुभव का शानदार संयोजन

लखनऊ। हॉस्पिटेलिटी उद्योग के जानेमाने नामों में से एक शेरवानी होटल्स ने 48 कमरों के बुटीक होटल शेरवानी पैबल्स एण्ड पाइन्स कॉर्बेट का लॉन्च किया हैए जो आराम और एडवेंचर का अनूठा संयोजन होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थित यह होटल प्रकृति एवं रोमांच प्रेमियों को खूब लुभाएगाए जहां आने वाले मेहमान जंगल की भव्यता का यादगार अनुभव पा सकेंगे। तो जंगल के नज़ारों और आवाज़ों में खो जाने के लिए तैयार हो जाएंए क्योंकि यहां प्रकृति के साथ बिताया गया हर पल हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। जंगल सफारी हो या नदी के नज़दीक आकर्षक पल या शहर की हलचल से दूर शांत माहौल, जिम कॉर्बेट का बुटीक होटल अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। शेरवानी पैबल्स एण्ड पाइन्स कॉर्बेट में 48 कमरे और सुईट्स हैं, जिन्हें स्मार्ट तरीके से सजाया गया हैए ये कमरे मेहमानों की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। इसके अलावा होटल की सफारी डेस्क, जंगल सफारी की सुविधा भी पेश करती है, जहां आप प्राकृतिक आवास में रहने वाले राजसी रॉयल टाइगर को देखने का दुर्लभ अवसर पा सकते हैं।

भारत भूटान के साथ और घनिष्ठ करेगा संबंध

विदेश सचिव मिसरी की पहली विदेश यात्रा

भाषा। थिम्पू

भारत ने शुक्रवार को भूटान के साथ अपने घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुष्टि की तथा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता का संकल्प जताया। विदेश सचिव मिसरी ने यहां प्रधानमंत्री ल्योंछेन दाशो शेरिंग तोबगे को भूटान के विकास के लिए एकजुटता की भावना से अवगत कराया। भूटान स्थित भारतीय मिशन ने बैठक की तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए कहा, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मुलाकात की। विदेश सचिव ने भूटान के साथ भारत के घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुष्टि की तथा भूटान की शाही सरकार और जनता की प्राथमिकताओं के अनुरूप भारत-भूटान संबंधों को और मजबूत करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले, मिसरी ने प्रधानमंत्री तोबगे से मुलाकात की, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपसी विश्वास और लाभ पर आधारित घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध निरंतर मजबूत होने चाहिए। मिसरी अपने समकक्ष पेमा चोडेन के साथ भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह-अध्यक्षता करने के लिए दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर शुक्रवार को यहां पहुंचे। कार्यभार संभालने के एक सप्ताह से भी कम समय में यह उनकी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है। विदेश

सचिव मिसरी ने प्रधानमंत्री तोबगे से मुलाकात की। इस दौरान तोबगे ने मिसरी को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। तोबगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह जानकर खुश हूं कि विक्रम मिसरी ने भारत के विदेश सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति के मात्र चार दिन बाद ही अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में भूटान का दौरा करने का फैसला किया है। मैं उनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई देता हूं। हमारी वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा। हमने भूटान और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों पर जोर दिया तथा इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आपसी विश्वास और लाभ पर आधारित हमारी साझेदारी निरंतर मजबूत होनी चाहिए। तोबगे ने कहा, मैंने सरकार और भारत के लोगों के प्रति उनके दृढ़ समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया..।

भारत के साथ घनिष्ठ संबंध निरंतर मजबूत होने चाहिए : भूटान के प्रधानमंत्री तोबगे

थिम्पू। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने शुक्रवार को भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मुलाकात की, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपसी विश्वास और लाभ पर आधारित घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध निरंतर मजबूत होने चाहिए। मिसरी अपने समकक्ष पेमा चोडेन के साथ भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह-अध्यक्षता करने के लिए दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर शुक्रवार को यहां पहुंचे। कार्यभार संभालने के एक सप्ताह से भी कम समय में यह उनकी पहली आधिकारिकविदेश यात्रा है। विदेश सचिव मिसरी ने प्रधानमंत्री तोबगे से मुलाकात की। इस दौरान तोबगे ने मिसरी को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। तोबगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह जानकर खुश हूं कि विक्रम मिसरी ने भारत के विदेश सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति के मात्र चार दिन बाद ही अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में भूटान का दौरा करने का फैसला किया है। मैं उनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई देता हूं।

संरा की शीर्ष अदालत ने क्षेत्रों पर इजराइल के कब्जे की वैधता पर विशेषज्ञ राय देने के लिए बैठक बुलाई

भाषा। हेग (नीदरलैंड्स)

संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने फलस्तीनी राष्ट्र के लिए मांगी गई भूमि पर इजराइल के 57 वर्षों के कब्जे की वैधता पर एक गैर-बाध्यकारी सलाहकारी राय देने के लिए सुनवाई शुरू की है। यह निर्णय इजरायल की नीतियों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय राय पर अधिक प्रभाव डाल सकता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवाफ सलाम को विश्व भर के 15 न्यायाधीशों की समिति की राय पढ़ने में लगभग एक घंटे का समय लगने की उम्मीद है।शुक्रवार की सुनवाई गाजा पर इजराइल के 10 महीने के भीषण सैन्य हमले की पृष्ठभूमि में हो रही है। दक्षिणी इजराइल में हमास के हमलों के बाद उसने यह जवाबी कार्वाई शुरू की थी। एक अलग मामले में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय दक्षिण अफ्रीका के इस दावे पर विचार कर रहा है कि गाजा में इजराइल का अभियान नरसंहार के बराबर है। इस दावे का इजराइल पुरजोर खंडन करता है।पश्चिम एशिया युद्ध में इजरायल ने 1967 में पश्चिमी तट, पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। फलस्तीनी तीनों क्षेत्रों को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में चाहते हैं।इजराइल पश्चिमी तट को विवादित क्षेत्र मानता है, जिसका भविष्य बातचीत से तय किया जाना चाहिए। उसने हालांकि अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वहां बस्तियां बसा दी हैं। उसने पूर्वी यरुशलम पर कब्जा कर लिया है,।

मालदीव में भारतीय सहायता से बन रहा नया हवाई अड्डा पूरा होने के करीब

माले। मालदीव ने कहा है कि भारतीय सहायता से बन रहे हनीमाधू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का लगभग 68 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। भारत ने कहा है कि इस परियोजना का द्वीपसमूह देश के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। बुनियादी ढांचा मंत्रालय ने घोषणा की है कि हनीमाधू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य 67.5 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जिसे भारत सरकार द्वारा 80 करोड़ एमवीआर (मालदीव की मुद्रा) ऋण सहायता से वित्त पोषित किया जा रहा है। परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। समाचार पोर्टल ट्रस्टएमवीडॉटकॉम ने बृहस्पतिवार को कहा, सितंबर में भारत की जीएमसी को सौंपे गए हवाई अड्डे के विस्तार में 2.7 किलोमीटर की हवाईपट्टी, 13 लाख यात्री क्षमता वाला टर्मिनल और जेट ईंधन भंडारण सुविधा शामिल है।

वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख गुएन फु ट्रोंग का 80 वर्ष की उम्र में निधन

हनोई। वियतनाम की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और देश के सबसे कद्दावर नेता गुएन फु ट्रोंग का कई महीनों तक बीमार रहने के बाद निधन हो गया। आधिकारिक मीडिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।वह 80 वर्ष के थे। हान डान समाचार पत्र की खबर के मुताबिक, पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव गुएन फु ट्रोंग का 19 जुलाई 2024 को एक बजकर 38 मिनट पर 108 केंद्रीय सैन्य अस्पताल में वृद्धावस्था और गंभीर बीमारी के कारण निधन हो गया। ट्रोंग को 2011 में पार्टी प्रमुख चुना गया था, जिसके बाद से वह वियतनाम की राजनीति पर छाए हुए थे।ट्रोंग ने अपने कार्यकाल के दौरान वियतनाम की एकदलीय राजनीतिक व्यवस्था मे कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत को मजबूत करने का काम किया।

रूस की अदालत ने अमेरिकी पत्रकार को कारावास की सजा सुनाई

एकातेरिनबर्ग। रूस की एक अदालत ने शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गेर्शकोविच को जासूसी के मामले में दोषी ठहराते हुए 16 साल के कारावास की सजा सुनाई। गेर्शकोविच के नियोक्ता और अमेरिका ने पूरी प्रक्रिया को पाखंड बताकर आरोपों को खारिज किया है। देश की राजनीतिक प्रभाव वाली कानूनी प्रणाली में त्वरित मुकदमे के तहत गेर्शकोविच को 16 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। गेर्शकोविच (32) को मार्च 2023 में यूराल पर्वतीय शहर एकातेरिनबर्ग की रिपोर्टिंग यात्रा के दौरान हिरासत में लिया गया था और उन पर अमेरिका के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था।

उत्तरी चिली में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप

सैंटियागो (चिली)। अर्जेंटीना की सीमा के पास उत्तरी चिली मे बृहस्पतिवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने यह जानकारी दी।इस भूकंप के कारण जान-माल के नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नही मिली है। यूएसजीएस के अनुसार, भूकंप चिली के समयानुसार रात नौ बजकर 51 मिनट पर 117 किलोमीटर गहराई में आया। इसका केंद्र चिली के सैन पेड्रो डी अटाकामा से 45 किलोमीटर (28 मील) दक्षिण-पूर्व में था।चिली प्रशांत महासागर में तथाकथित रिंग ऑफ फायर मे स्थित है और यहां अक्सर भूकंप आते रहते है।

पाक में आतंकवादियों के हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत

पेशावर। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों द्वारा शुक्रवार को एक पुलिस चौकी पर किए गए हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। हमला सूबे के मरदान जिले में तख्तभाई तहसील स्थित पुलिस चौकी पर हुआ। इसमे एक पुलिस कर्मी की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने हमले की निंदा की और पुलिस से मामले में रिपोर्ट तलब की है। उन्होने कहा, आतंकवाद का खात्मा करने के लिए यह पुलिस का बलिदान है। यह अभियान ऐसे कायराना हमलो से नही रुकेगा। एक अन्य घटना मे एक व्यक्ति की उस समय मौत हो गई जब सूबे में रिमोट संचालित बम से विस्फोट किया गया।

ब्रिटेन में दंगे में बस में आगजनी, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़

लंदन। उत्तरी इंग्लैंड के लीड्स में दंगा भड़कने के दौरान पथराव और अव्यवस्था के बीच एक डबल डेकर बस में आग लगा दी गई और एक पुलिस वाहन को पलट दिया गया। स्थानीय परिषद ने इसे पारिवारिक घटना बताया है। लीड्स नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम रिओर्डन ने शुक्रवार को बीबीसी को बताया, अब स्थिति शांत हो गई है। हमने पहले ही घटनास्थल पर सफाई का काम शुरू कर दिया है।

अमेरिकी लोगों की सेवा करने वाली सरकार देने को प्रतिबद्ध : ट्रंप

मिलवाउकी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर जानलेवा हमले के बाद अमेरिकी जनता द्वारा दिए गए समर्थन और प्यार के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वह अपने संकल्प पर अडिग हैं और अमेरिकी जनता की सेवा करने वाली सरकार बनाने को प्रतिबद्ध हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान आगामी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से नामांकन स्वीकार करने से पहले दिया। रिपब्लिकन पार्टी ने मिलवाउकी में बृहस्पतिवार को आयोजित अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में ट्रंप को तीसरी

बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। ट्रंप (78) ने कहा, आज रात मैं श्रद्धा और आस्था से एवं गर्व से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन स्वीकार करता हूं। पेनसिल्वेनिया में शनिवार को ट्रंप पर असफल जानलेवा हमला किया गया था जिसके बाद अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि वह अमेरिकियों के साथ विश्वास, ताकत और उम्मीद के साथ खड़े हैं। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज से चार महीने बाद हमारी शानदार जीत होगी और हम अपने देश के इतिहास में चार सर्वश्रेष्ठ सालों की शुरुआत करेंगे। हम एक साथ मिलकर सुरक्षा, समृद्धि और सभी जातियों, धर्मों, रंगों और नस्लों के लोगों की आजादी के लिए नए युग की शुरुआत करेंगे।

यमन के हूती विद्रोहियों ने ली तेल अवीव में हवाई हमले की जिम्मेदारी, एक मौत और 10 लोग घायल

तेल अवीव। यमन के हूती विद्राहियों ने इजराइल के तेल अवीव पर शुक्रवार तड़के हुए ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला ऐसे स्थान पर किया गया जो अमेरिकी दूतावास के काफी नजदीक था। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 10 लोग घायल हो गए। हवाई हमले से सड़कों पर छें गिरने लगे तथा कांच के टुकड़े चारों ओर फैल गए। इजराइल और हमास के बीच नौ माह से युद्ध जारी है।

ब्रिटेन, रूस के और भीतरी इलाकों में हमले के लिए यूक्रेन की मदद करे : जेलेंस्की

भाषा। लंदन

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ब्रिटेन की नई सरकार से आग्रह किया कि वह यूक्रेन की सेना को रूस के और भीतरी इलाकों पर हमला करने में मदद करे ताकि उनके देश पर रूस के घातक मिसाइल हमलों को रोका जा सके। उन्होंने एक दुलर्भ घटनाक्रम में ब्रिटेन की कैबिनेट (मंत्रिमंडल) बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। जेलेंस्की ने कहा कि जहां रूसी हथियार रखे गए हैं उन केंद्रों को नष्ट करने के लिए लंबी दूरी की मारक क्षमता हासिल करना यूक्रेनी रक्षा पंक्ति के लिए अहम है। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर से कहा, पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल को लेकर यूक्रेन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए मैं आपसे नेतृत्व करने के लिए कहता हूं। रूस ने विनाशकारी अग्नेयास्त्र तैनात किए हैं क्योंकि वह गर्मी से ही पूर्वी यूक्रेन में हमला जारी रखे हुए है। रूस के हमले से जहां गांव के गांव मलबे में तब्दील हो गए हैं, वहीं यूक्रेन की सेना को कई स्थानों से पीछे हटना पड़ा है। रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। इन हमलों में कीव स्थित बच्चों के अस्पताल समेत अन्य संरचानाओं को निशाना बनाया गया है। कीव के कुछ सहयोगी यूक्रेन को रूसी क्षेत्र पर हमला करने के लिए अपने हथियारों का उपयोग करने देने के प्रति अनिच्छुक हैं क्योंकि उन्हें चिंता है कि इससे पश्चिमी देशों का

रूस से सीधा टकराव हो सकता है। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि जब तक कि अंतरराष्ट्रीय कानून कायम है तब तक यह यूक्रेन पर निर्भर है कि वह ब्रिटेन द्वारा आपूर्ति की गई मिसाइलों का उपयोग कैसे करे। बीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में जेलेंस्की ने कहा कि वह रूस में स्थित ठिकानों के खिलाफ ब्रिटेन से प्राप्त स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का उपयोग करने की यूक्रेन की क्षमता के बारे में स्पष्टीकरण मांग रहे थे।

अमेरिका ने यूक्रेन के मुद्दे पर भारत से समर्थन मांगा

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रो मे भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग को रेखांकित करते हुए कहा है कि अमेरिका चाहता है कि भारत यूक्रेन में स्थाई और न्यायपूर्ण शांति स्थापित करने के उसके प्रयासों का समर्थन करे। विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मॉस्को मे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हाल मे हुई बैठको के बारे में बृहस्पतिवार को पूछे गए एक सवाल के जवाब मे ए बाते कही। उन्होने कहा भारत अनेक प्रमुख क्षेत्रों में हमारा साझेदार है, और यह बात पिछले ग्रीष्मकाल में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी राजकीय यात्रा पर अमेरिका आए थे। पटेल ने कहा, इसके अलावा, यूक्रेन-रूस के बीच जारी जंग और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता पर उसके प्रभाव के संदर्भ में, हम भारत समेत अपने सभी साझेदारों से यूक्रेन में स्थाई व न्यायपूर्ण शांति स्थापित करने के प्रयासों का समर्थन करने का अनुरोध करते है। विदेश मंत्रालय ने रूस से कहा कि वह यूक्रेन के संप्रभु क्षेत्र से अपने सैनिक वापस बुलाए। मोदी 22वे भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 8-9 जुलाई को रूस मे थे। यूक्रेन मे जारी संघर्ष के बीच पश्चिमी देशो की इस शिखर सम्मेलन पर गहरी नजर थी। रूस और यूक्रेन के बीच 2022 मे युद्ध शुरू होने के बाद से मोदी की यह पहली रूस यात्रा थी। नौ जुलाई को पुतिन के साथ वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में संभव नही है और शांति के प्रयास बम व गोलियो के बीच सफल नही होते है। भारत रूस के साथ अपने संबंधो का दृढ़तापूर्वक बचाव करता रहा है तथा यूक्रेन संघर्ष के बावजूद दोनो देशो के संबंध मजबूत रहे है

बाइडन के समर्थन में कमी, फिर भी दौड़ में बने रहेंगे : प्रचार टीम के अध्यक्ष

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की प्रचार टीम ने इस बात पर जोर दिया है कि वह चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में कई शीर्ष स्तर के नेता हैं जो चाहते हैं कि बाइडन इस बात पर विचार करें कि कैसे 2024 के राष्ट्रपति पद चुनाव से हटकर नए उम्मीदवार के लिए रास्ता बनाया जा सकता है ताकि पार्टी को नवंबर में व्यापक नुकसान से बचाया जा सके। बाइडन ने इस बात पर जोर दिया है कि वह रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हरा सकते हैं। बाइडन कोविड से संक्रमित होने के बाद फिलहाल डेलावेयर स्थित

अपने आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब वह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें बढ़ते दबाव के आगे झुककर राष्ट्रपति पद की दौड़ से हट जाना चाहिए, वह परिवार के साथ हैं और कुछ पुराने सहयोगियों पर भरोसा कर रहे हैं। बाइडन प्रचार अभियान की अध्यक्ष जेन ओ मैली डिलियन ने राष्ट्रपति के समर्थन में कमी होना स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि वह निश्चित रूप से दौड़ में बने रहेंगे और प्रचार अभियान टीम ट्रंप को हराने के लिए कई रास्ते देखती है। उन्होंने एमएसएनबीसी के मॉर्निंग जो से कहा, हमें अमेरिकी लोगों को यह भरोसा दिलाने के लिए बहुत काम करना है कि हां, वह बूढ़े हैं, लेकिन वह जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाइडन की नेतृत्व करने की योग्यता के बारे में चिंतित मतदाता ट्रंप को वोट देने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा, उनके पास सवाल हैं, लेकिन वे जो बाइडन के साथ बने रहेंगे।

बांग्लादेश में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं और आंसू गैस के गोले दागे

भाषा। ढाका

बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर जारी प्रदर्शनों के बीच शुक्रवार को पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं और आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही राजधानी ढाका में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंसक प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। राजधानी ढाका और कुछ स्थानों पर प्रदर्शन कुछ सप्ताह पहले शुरू हुए थे लेकिन सोमवार से इनमें तेजी आ गई। ए विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए अहम चुनौती हैं। उन्होंने जनवरी में हुए चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल की थी। प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की आज की घटना के एक दिन पहले भी काफी हिंसा हुई थी जिसमें स्थानीय मीडिया के अनुसार 22 लोगों की मौत हो गई थी। समय टीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि शुक्रवार को चार और लोग मारे गए। इन आंकड़ों की तुरंत पुष्टि करने के लिए अधिकारियों से संपर्क नहीं किया जा सका। एसोसिएटेड प्रेस के एक रिपोर्टर ने देखा कि सीमा रक्षक अधिकारियों ने 1000 से अधिक प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलियां चलाईं।

लंबी कोविड पहेली अब सुलझने लगी है - तस्वीर परेशान करने वाली है

भाषा। सेंट लुइस (अमेरिका)

2020 के बाद से, लंबे कोविड -19 के रूप में जानी जाने वाली एक स्थिति व्यापक विकलांगता का कारण बन गई है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है और कर्मचारियों की उत्पादकता में कमी और कार्यबल में समग्र गिरावट के कारण अर्थव्यवस्थाओं को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। लंबे कोविड को लेकर किए गए गहन वैज्ञानिक प्रयासों के परिणामस्वरूप 24,000 से अधिक वैज्ञानिक प्रकाशन हुए हैं, जिससे यह रिकॉर्ड किए गए मानव इतिहास के किसी भी चार वर्षों में सबसे अधिक शोध वाली स्वास्थ्य स्थिति बन गई है। लॉन्ग कोविड एक शब्द है जो सार्स-कोव-2 वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों का वर्णन करता है। इनमें लगातार श्वसन संबंधी लक्षण, जैसे सांस की तकलीफ, दुर्बल करने वाली थकान या मस्तिष्क कोहरा, जो लोगों की काम करने की क्षमता को सीमित करता है, और दिल की विफलता और मधुमेह जैसी स्थितियां शामिल हैं, जो जीवन भर रहने के लिए जानी जाती हैं।मैं एक चिकित्सा वैज्ञानिक हूं, और मैं महामारी के शुरुआती दिनों से ही लंबे कोविड के अध्ययन में गहराई से डूबा रहा हूं। मैंने लॉन्ग कोविड पर एक विशेषज्ञ गवाह के रूप में अमेरिकी सीनेट के समक्ष गवाही दी है, इस पर बड़े पैमाने पर प्रकाशित किया है और इस क्षेत्र में मेरे शोध के लिए 2024 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में मुझे नामित किया गया था। 2024 की पहली छमाही में, लंबे समय तक कोविड पर रिपोर्टों और वैज्ञानिक पत्रों की बाढ़ ने इस जटिल स्थिति में स्पष्टता ला दी। इनमें, विशेष रूप से, यह अंतर्दृष्टि शामिल है कि कैसे प्रारंभिक वायरल संक्रमण के वर्षों बाद भी कोविड -19 कई अंगों में कहर बरपा सकता है, साथ ही वायरल दृढ़ता और प्रतिरक्षा शिथिलता पर उभरते साक्ष्य जो प्रारंभिक संक्रमण के बाद महीनों या वर्षों तक बने रहते हैं।कोविड शरीर पर कितने समय तक प्रभाव डालता है ?एक नया अध्ययन जिसे मैंने और मेरे सहकर्मियों ने 17 जुलाई, 2024 को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित किया, उससे पता चलता है कि महामारी के दौरान लंबे समय तक रहने वाले कोविड का जोखिम कम हो गया। 2020 में, जब सार्स-कोव-2 का पैतृक तनाव प्रभावी था और टीके उपलब्ध नहीं थे।

बढ़ रही रोबोटिक सर्जरियां

इस समय रोबोटिक सर्जरी का प्रचलन बढ़ता रहा है। कानपुर के नोबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने भारत में निर्मित सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम एसएसआई मंत्रा के द्वारा रोबोटिक सर्जरियों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। यह इस क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है। डॉ अमिताभ सिंह सीनियर कन्सलटेन्ट यूरो-ओंकोलोजी राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड रीसर्च संह्रटर के मार्गदर्शन तथा डॉ अनिल जैन डायरेक्टर] कन्सलटेन्ट यूरोलोजिस्ट किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के नेतृत्व में नोबल हॉस्पिटल की सर्जिकल टीम ने बेहद सटीकता और दक्षता के साथ रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी को अंजाम दिया। यह सफल प्रक्रिया मरीज उन्मुख देखभाल तथा चिकित्सा उत्कृष्टता के लिए नोबल अस्पताल की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है तथा कानपुर और आस-पास के शहरों में हेल्थकेयर इनोवेशन में इसकी स्थिति एवं नेतृत्व को और अधिक मजबूत बनाती है। डॉ अनिल जैन डायरेक्टर कन्सलटेन्ट यूरोलोजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लान्ट सर्जन नोबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा एसएसआई मंत्रा को इंस्टॉल करना सभी के लिए उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह सफलता मरीज-उन्मुख देखभाल एवं चिकित्सा उत्कृष्टता के लिए नोबल अस्पताल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और साथ ही कानपुर में हेल्थकेयर इनोवेशन में अस्पताल की स्थिति को मजबूत बनाती है। अस्पताल द्वारा गोल्ड-स्टैण्डर्ड की सेवाओं को उपलब्ध कराया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि अब दूसरे स्तर के शहरों के मरीजों को उपचार के लिए महानगरों में जाने की जरूरत नहीं। यह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बात करते हुए डॉ विश्वा श्रीवास्तव प्रेजीडेन्ट एवं सीओओ एसएस इनोवेशन्स ने कहा यह उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है।

क्विक न्यूज

पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 38 लाख, देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह

इस्लामाबाद। पाकिस्तान मे हिंदुओं की आबादी वर्ष 2017 के 35 लाख से बढ़कर 2023 में 38 लाख हो गई जो इन्हें इस इस्लामी राष्ट्र का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह बनाती है। पिछले साल की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो (पीबीएस) ने बृहस्पतिवार को 7वीं आबादी और आवास जनगणना 2023 के नतीजे जारी किए। 2023 में पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 2,40,458,089 थी।इससे पता चलता है कि कुल आबादी मे मुसलमानों की हिस्सेदारी 2017 में 96.47 प्रतिशत से थोड़ी कम होकर 2023 में 96.35 प्रतिशत रह गई जबकि सभी प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी पिछले छह वर्षों में बढ़ी है। हिंदुओं की आबादी 2017 के 35 लाख से बढ़कर 2023 में 38 लाख हो गई, लेकिन कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी 1.73 से घटकर 1.61 प्रतिशत हो गई है। इससे पता चलता है कि अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी में तेज दर से वृद्धि हुई है।ईसाइयों की जनसंख्या भी 26 लाख से बढ़कर 33 लाख हो गई। कुल जनसंख्या में ईसाइयों की हिस्सेदारी 1.27 से बढ़कर 1.37 प्रतिशत हो गई है। अहमदियों की वास्तविक जनसंख्या के साथ-साथ कुल जनसंख्या मे उनकी हिस्सेदारी में भी गिरावट देखी गई। उनके समुदाय की आबादी 2017 के1,91,737 (कुल आबादी का 0.09 प्रतिशत) से 29,053 कम होकर 162,684 (कुल आबादी का 0.07 प्रतिशत) रह गई।

श्रीलंका : 2019 में ईस्टर पर आतंकी हमलों के मामले में पुलिस अधिकारी को अनिवार्य छुट्टी पर भेजा गया

कोलंबो। श्रीलंका मे वर्ष 2019 मे ईस्टर के मौके पर हुए आत्मघाती हमलो मे आपराधिक लापरवाही के लिए दोषी ठहराए गए एक शीर्ष पुलिस अधिकारी को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया है। हमलों में 11 भारतीयों सहित 270 से अधिक लोग मारे गए थे।स्वतंत्र पुलिस आयोग ने बल में दूसरे नंबर के वरिष्ठ अधिकारी उपमहानिरीक्षक नीलांथा जयवर्धने को बृहस्पतिवार से अनिवार्य छुट्टी पर भेजे जाने की घोषणा की।श्रीलंका में 2019 में ईस्टर के मौके पर हुए आत्मघाती बम हमले की जांच में दायर मौलिक अधिकार याचिकाओ के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने जयवर्धने के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्वाई शुरू करने का आदेश दिया। उसके बाद उन्हे अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया।जयवर्धने उन शीर्ष रक्षा अधिकारियों मे एक है, जिन्हें ईस्टर के दिन आत्मघाती बम विस्फोटों में आपराधिक लापरवाही के लिए दोषी ठहराया गया है। स्थानीय इस्लामी चरमपंथी समूह, नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) के नौ आत्मघाती हमलावरों ने 21 अप्रैल, 2019 को तीन कैथोलिक गिरजाघरों और कई आलीशान होटलों में सिलसिलेवार धमाके किए थे जिनमें 11 भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों सहित लगभग 270 लोग मारे गए और 500 से अधिक घायल हुए थे। पुलिस आयोग के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय ने 12 जनवरी, 2023 को जयवर्धने के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्वाई करने की सिफारिश की थी।जयवर्धने हमले के समय पुलिस की राज्य खुफिया सेवा के प्रमुख थे।

पाकिस्तानः कई आरक्षित सीट पर न्यायालय के फैसले को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में विचार-विमर्श शुरू

इस्लामाबाद-लाहौर। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सहित अपने गठबंधन सहयोगियो के साथ कई आरक्षित सीट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर शुक्रवार को विचार-विमर्श शुरू किया। न्यायालय के फैसले से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी संसद मे सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी।सत्तारूढ़ गठबंधन के कई नेता उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से आशंकित दिखाई दिए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी के प्रमुख नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने शीर्ष अदालत के इसे फैसले के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा, मै उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो से कहना चाहूंगी कि वे देश को काम करने दें। पीएमएल-एन पार्टी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा 15 जुलाई को खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी को कई आरक्षित सीट आवंटित करने के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की है। सीट से कम सीट जीती है।

अलकायदा के एक प्रमुख सदस्य को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गिरफ्तार किया गया

लाहौर। अलकायदा के सरगना रहे ओसामा बिन लादेन के करीबी सहयोगी अमीन उल हक को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से गिरफ्तार किया गया और देश में बड़े पैमाने पर आतंकवादी साजिश को विफल कर दिया गया। आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) के अधिकारियो ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सीटीडी के डीआईजी उस्मान अकरम गोनाडल ने कहा, आतंकवादी को खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान पकड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित हक को पंजाब प्रांत मे गुजरात जिले के सराय आलमगीर कस्बे से गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस के सीटीडी के प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, क्योंकि विभाग ने विभिन्न खुफिया एजेंसियो के साथ मिलकर पंजाब प्रांत में एक योजनाबद्ध अभियान के दौरान हक को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने एक बयान मे कहा कि हक 1996 से ओसामा बिन लादेन का करीबी सहयोगी था और उसने पूरे प्रांत में आतंकी गतिविधियो की कथित तौर पर साजिश रची थी और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानो और हस्तियो को निशाना बनाना चाहता था।

ओमान में मस्जिद पर हुए हमले में मारे गए चार पाकिस्तानियों के शव स्वदेश लाए गए

इस्लामाबाद। ओमान मे शिया मस्जिद पर हुए हमले मे जान गंवाने वाले चार पाकिस्तानियो के शव स्वदेश लाकर शुक्रवार को मृतकों के परिवारों को सौंप दिए गए। अधिकारियो ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) की उड़ान के इस्लामाबाद और लाहौर हवाई अड्डो पर उतरने के समय पीड़ितों के रिश्तेदार मौजूद थे। विमानन कंपनी के प्रवक्ता अब्दुल्ला हफीज ने बताया कि सरकार के आदेश पर शव वापस लाए गए और दफनाने के लिए पीड़ितों के रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। बाद में, सैकड़ों शोक संतप्त लोग मृतकों के गृह नगरों मे उनके अंतिम संस्कार मे शामिल हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ओमान के राजदूत के साथ बैठक के दौरान हमले की निंदा की। हथियारबंद लोगों ने ओमान की राजधानी मस्कट की एक मस्जिद पर सोमवार को हमला किया, जो मोहर्म के दसवें दिन (आशूरा) की पूर्व संध्या पर खास इबादत के लिए आए लोगो से भरी थी।

आर्मीनिया में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, दो लोगों की मौत

एरेवान। आर्मीनिया में एक सैन्य विमान शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक दल के दोनों सदस्यो की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।अधिकारियों ने बताया कि पूर्ववर्ती सोवियत संघ मे निर्मित एंटोनोव एन-2 विमान आर्मीनिया के सबसे बड़े शहर और राजधानी एरेवान से 20 किलोमीटर उत्तर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ।उन्होने कहा कि विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था। दुर्घटना का कारण तत्काल ज्ञात नही हो सका।पूर्ववर्ती सोवियत संघ में निर्मित एंटोनोव एन-2 एक इंजन वाला हवाई जहाज है जो 12 यात्रियों को ले जा सकता है। 1947 में इस विमान के उत्पादन के बाद से परिवहन और उपयोगिता भूमिकाओ में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। पूर्ववर्ती सोवियत संघ और अन्य देशो में ऐसे हजारो विमान बनाए गए।दुनिया भर मे अभी भी ऐसे कई विमान संचालित हो रहे है।

भारतीय महिला टीम का जीत से आगाज

● एशिया कप में गत चैम्पियन ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराया

भाषा। दाम्बुला

गत चैम्पियन भारत ने गेंदबाजों के बाद शीर्ष क्रम बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन से शुक्रवार को यहां महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तानी टीम को सात विकेट से हराया। अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और बेहतरीन क्षेत्ररक्षण की बदौलत पाकिस्तान को 19.2 ओवर में महज 108 रन पर समेटने के बाद भारत ने तीन विकेट पर 109 रन बनाकर जीत दर्ज की। भारतीय गेंदबाजों में पूजा वस्त्राकर और रेणुका सिंह ने पाकिस्तान को शुरूआती झटके देते हुए दो दो विकेट लिए। दीप्ति शर्मा ने 20 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। श्रेयंका पाटिल को भी दो विकेट मिले। फिर भारत ने सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (40 रन) और स्मृति मंधाना (45 रन) के अर्धशतकों तथा दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 57 गेंद में 85 रन की साझेदारी से यह लक्ष्य महज 14.1 ओवर में हासिल कर लिया। शेफाली (29 गेंद, छह चौके, एक छक्का) ने पहले ही ओवर में सादिया इकबाल पर स्क्वायर लेग में शानदार चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए और फिर इसी गेंदबाज के दूसरे ओवर में मिडविकेट और एक्स्ट्रा कवर पर दो चौके और जड़े। मंधाना शुरू में सतर्क होकर खेली, उन्होंने दूसरे ओवर में फातिमा सना पर मिडविकेट पर अपनी पारी का पहला चौका जड़ा। इसके बाद आक्रामकता दिखाते हुए उन्होंने 31 गेंद में नौ बार गेंद सीमारेखा के पार कराई। दोनों अच्छी लय में थीं और दनादन शॉट्स लगाकर अर्धशतक की ओर बढ़ रही थीं। लेकिन दोनों ही चूक गईं। इस दौरान शेफाली ने छठे ओवर में पारी का पहला छक्का तुबा हसन की गेंद को स्क्वायर लेग में स्वीप करते हुए जड़ा। विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहीं मंधाना ने आठवें ओवर में तुबा हसन की गेंदों को धुनते हुए पांच चौके जड़कर इस ओवर से टीम के स्कोर में 21 रन जोड़े। पर सईदा अरूब शाह की गेंद पर शार्ट मिडविकेट पर आलिया रियाज को कैच देकर पवेलियन लौट गईं। उनकी जगह क्रीज पर उतरीं दयालन हेमलता ने आते ही 11वें ओवर में नशरा संधू पर लगातार तीन चौके जड़ दिए।

स्कोरबोर्ड

पाकिस्तान : फिरोजा का हरमनप्रीत बो वस्त्राकर 05, मुनीबा का जेमिमा बो वस्त्राकर 11, अमीन का राधा बो रेणुका 25, रियाज का जेमिमा बो श्रेयंका 06, डार का हेमलता बो दीप्ति 08, हसन का राधा बो दीप्ति 22, जावेद पगबाधा बो रेणुका 00, सना नाबाद 22, सैयदा अरूब शाह रन आउट 02, नशरा का ऋचा बो दीप्ति 00, सादिया बो श्रेयंका 00, अतिरिक्त : 07, कुल योग : 19.2 ओवर में 108 रन पर सभी आउट, ***विकेट पतन*** : 1-9, 2-26, 3-41, 4-59, 5-61, 6-61, 7-92, 8-94, 9-94, **गेंदबाजी** : रेणुका 4-0-14-2, पूजा वस्त्राकर 4-0-31-2, दीप्ति 4-0-20-3, यादव 4-0-26-0, पाटिल 3.2-0-14-2

भारत : शेफाली बो सईदा अरूब शाह 40, मंधाना का आलिया रियाज बो सईदा अरूब शाह 45, हेमलता का तुबा हसन बो नशरा संधू 14, कौर नाबाद 05, रोड्रिग्स नाबाद 03, अतिरिक्त : 02, कुल योग : 14.1 ओवर में तीन विकेट पर 109 रन, **विकेट पतन** : 1-85, 2-100, 3-102, **गेंदबाजी** : इकबाल 2.1-0-18-0, फातिमा सना 2-0-15-0, डार 1-0-10-0, हसन 2-0-36-0, संधू 4-0-20-1, अरूब शाह 3-0-9-2

भारत की कप्तानी से नजरअंदाज किए जाने के बाद हार्दिक का मुंबई इंडियंस के नेतृत्व करने पर संदेह

भाषा। नई दिल्ली

टी20 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले हार्दिक पंड्या के लिए राष्ट्रीय टीम में चीजें काफी बदल गई है। टी20 विश्व कप के दौरान भारत के उपकप्तान रहे हार्दिक को श्रीलंका दौरे के लिए टी20 टीम की कमान नहीं सौंपी गई। सूर्यकुमार यादव खेल के सबसे छोटे प्रारूप में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। भारत की कप्तानी के दायित्व से मुक्त होने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस इस हरफनमौला खिलाड़ी को कप्तान बनाए रखेगी। मुंबई की फ्रेंचाइजी ने आईपीएल के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा की जगह पिछले सत्र से पहले हार्दिक को कप्तान बनाया था। टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के बाद रोहित भारतीय खेल जगत में महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए है। आईपीएल की इस साल बड़ी नीलामी होनी है और ऐसे में यह देखना होगा कि रोहित मुंबई की टीम के साथ बने रहेंगे या नहीं। हार्दिक और रोहित के अलावा सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह भी टीम की अगुवाई करना चाहते हैं। आईपीएल संचालन समिति ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि वे कितने खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति देंगे। इस बात की संभावना है कि फ्रेंचाइजी को एक विदेशी सहित चार खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति मिले। फ्रेंचाइजी टीमों को अगले कुछ वर्षों के लिए मजबूत टीम बनाने पर कुछ कठोर फैसले लेने होंगे। गुजरात टाइटंस के लिए कमाल करने वाले हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।

एशिया कप: नेपाल ने यूएई को छह विकेट से हराया

दांबुला। सलामी बल्लेबाज समझाना खड़का के नाबाद अर्धशतक और तेज गेंदबाज इंदु बर्मा के तीन विकेट की मदद से नेपाल ने शुक्रवार को यहां महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 23 गेंद शेष रहते हुए छह विकेट से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। खड़का ने 45 गेंद पर नाबाद 71 रन बनाए, जिसमें 11 चौके शामिल हैं। उनकी इस पारी की मदद से नेपाल ने 116 रन का लक्ष्य 16.1 ओवर में हासिल कर दिया। नेपाल ने 4 विकेट पर 118 रन बनाए।अमीरात की टीम इससे पहले 8 विकेट पर 115 रन ही बना पाई थी। उसकी तरफ से खुशी शर्मा ने 36 और कविशा एगोडेज ने 22 रन का योगदान दिया। बर्मा नेपाल की सबसे सफल गेंदबाज रही। उन्होंने 19 देकर तीन विकेट लिए। नेपाल को भी कुछ मुश्किल पलों से गुजरना पड़ा। ऑफ स्पिनर एगोडेज (12 रन देकर 3 विकेट) ने अमीरात को वापसी दिलाने का अच्छा प्रयास किया लेकिन खड़का ने एक छोर संभाले रखा और टीम को आसानी से लक्ष्य तक पहुंचाया।

विधात्री ने बतौर पेशेवर डब्ल्यूपीजीटी के नौवें चरण में पहला खिताब जीता

होसुर (तमिलनाडु)। भारतीय गोल्फर विधात्री उर्स ने शुक्रवार को यहां हीरो महिला प्रो गोल्फ टूर (डब्ल्यूपीजीटी) 2024 के नौवें चरण का खिताब अपने नाम किया। विधात्री ने अंतिम दौर के शुरूआत में बर्डी की हैट्रिक लगाई और दो शॉट से खिताब जीत लिया। विधात्री ने एक अंडर 70 का कार्ड खेला। इससे पहले उन्होंने दो दिन में 68 और 69 के कार्ड खेले थे। इससे उनका कुल स्कोर छह अंडर 207 रहा। यह विधात्री की बतौर पेशेवर गोल्फर पहली जीत थी। हालांकि एमेच्योर के तौर पर वह पहले भी टूर पर खिताब जीत चुकी है।

विश्व जूनियर स्क्वाश टीम स्पर्धा में भारत की जीत के साथ शुरूआत

ह्यूस्टन। भारत ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप में जीत के साथ शुरूआत की जब लड़के और लड़कियों की टीम ने अपने अपने मुकाबले अच्छे अंतर से जीते। लड़कों ने कुवैत को ग्रुप एफ के मुकाबले में 3-0 से हराया जबकि राष्ट्रीय चैम्पियन अनाहत सिंह की अगुवाई में लड़कियों ने ग्रुप डी में चीनी ताइपै को इसी अंतर से मात दी। अब लड़कों का सामना शुक्रवार को ब्राजील से होगा जबकि लड़कियों की टीम को ब्राजील और आस्ट्रेलिया से खेलना है।

गोवा चैलेंजर्स के सामने शुरूआती मैच में जयपुर पैट्रियट्स की चुनौती

चेन्नई। गत चैंपियन गोवा चैलेंजर्स 22 अगस्त से सात सितंबर तक यहां होने वाले अल्टीमेट टेबल टेनिस (यूटीटी) के शुरूआती मैच में नई टीम जयपुर पैट्रियट्स का सामना करेगा। इस फ्रेंचाइजी-आधारित लीग में दो नई टीमें जुड़ी है। आठ टीमों के इस लीग के सभी 23 मैच यहां के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसमें 16 अंतरराष्ट्रीय सहित कुल 48 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें विश्व रैंकिंग में 10वें स्थान पर काबिज बर्नाडेट स्जोक्स, विश्व नंबर 16 नीना मित्तेल्हम, और नाइजीरिया के दिग्गज और वर्तमान विश्व नंबर 19 कादरी अरूणा भाग लेने वाले शीर्ष अंतरराष्ट्रीय खिलाडियो में शामिल है।

नौरी को हराकर नडाल नॉर्डिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में

बस्ताड (स्वीडन)। रफेल नडाल ने पांचवी वरीयता प्राप्त कैमरन नौरी को 6-4, 6-4 से हराकर नॉर्डिया ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। दूसरे सेट के पहले गेम में नडाल गिर गए और खून बहने लगा जिससे उन्हें मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ी। उन्होने मैच के आखिरी पांच गेम जीतकर जनवरी के बाद पहली बार किसी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। नडाल ने 2005 में 19 वर्ष की उम्र में यहां खिताब जीता था जिसके बाद वह पहली बार यहां खेल रहे है। वह पेरिस में रोलां गैरो पर ओलंपिक में खेलने की तैयारी में है।

ओलंपिक में खेलेगी इस्राइली फुटबॉल टीम

ज्यूरिख। फीफा ने इस्राइल को अंतरराष्ट्रीय फुटबाल से प्रतिबंधित करने के फलस्तीन के प्रस्ताव पर फैसला टाल दिया है जिससे इस्राइली फुटबॉल टीम पेरिस ओलंपिक में खेल सकेगी। दो महीने पहले फलस्तीन के प्रस्ताव पर निष्पक्ष कानूनी आकलन की घोषणा के बाद फीफा को आमसभा की असाधारण बैठक में शनिवार को इस पर फैसला लेना था। यह फैसला ओलंपिक की फुटबॉल स्पर्धा शुरू होने से चार दिन पहले आता जिसमें इस्राइल को जापान, माली और पराग्वे के साथ एक ग्रुप में रखा गया है।

2047 में खेलों में भी शीर्ष पांच में रहने का लक्ष्य : मांडविया

भाषा। नई दिल्ली

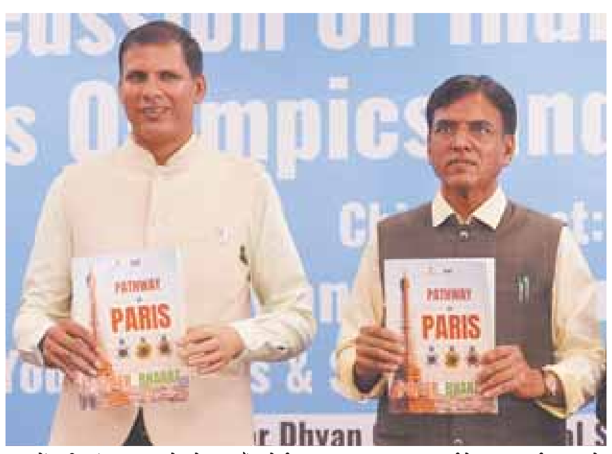

नए भारत के निर्माण में खेलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कहा कि 2047 में आजादी की सौवीं सालगिरह पर भारत का खेलों में भी शीर्ष पांच में रहने का लक्ष्य रहेगा। खेलमंत्री ने कहा , पिछले दस साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है और आजादी की सौंवी सालगिरह पर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। जब देश कोरोना लॉकडाउन में था , तब सरकार 2047 का रोडमैप तैयार कर रही थी। नवनिर्माण के इस रोडमैप का हिस्सा खेल भी है और जब हम विकसित राष्ट्र होंगे तो खेलों में भी शीर्ष पांच में रहेंगे। उन्होंने कहा , भारत विविधताओं का देश है और यहां खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रतिभा को तलाशकर उसे इको सिस्टम में लाने और मौके देने की जरूरत भर है। मैने कोरोना के दौरान अनुभव किया है कि भारत में मैन पावर और ब्रेन पावर की कमी नहीं है और उसके दम पर ही हमने कामयाबी पाई है। पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे मांडविया ने कहा , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में वह इको सिस्टम तैयार हुआ है जिसमें विभिन्न कार्य योजनाओं के जरिए खिलाड़ियों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में मदद की जा रही है। मैं पेरिस ओलंपिक में भाग लेने जा रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। खेलमंत्री ने पेरिस ओलंपिक और पैरालम्पिक के लिए भारत की तैयारियों को लेकर दिल्ली खेल पत्रकार संघ द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर आयोजित परिचर्चा कहा , पेरिस ओलंपिक में पदकों की संभावना को लेकर मैं कोई आंकड़ा तो नहीं दूंगा लेकिन उम्मीद है कि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन होगा। हमने तोक्यो में सात पदक जीते थे और अब उससे आगे जाएंगे। भारत ने तोक्यो ओलंपिक 2020 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण समेत सात पदक जीते थे। 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में भारत 117 सदस्ईय दल भेज रहा है जो तोक्यो ओलंपिक (121) के बाद सबसे बड़ा है। इस

अबकी बार 25 पार , पैरालम्पिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का लक्ष्य : झाझडिया

नई दिल्ली। भारतीय पैरालम्पिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझडिया ने शुक्रवार को कहा कि पेरिस पैरालम्पिक में भारत को न सिर्फ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का यकीन है बल्कि पूरी उम्मीद है कि पदक संख्या 25 पार जाएगी। भारतीय पैरालम्पिक दल ने तोक्यो में इतिहास रचते हुए पांच स्वर्ण पदक समेत 19 पदक जीते थे। झाझडिया ने पेरिस ओलंपिक और पैरालम्पिक के लिए भारत की तैयारियो को लेकर एक परिचर्चा मे कहा , मुझे लगता है कि पेरिस मे हमारा प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ होगा। हमारा स्लोगन है अबकी बार 25 पार। मै खिलाड़ियों के संपर्क मे हूं और तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है। तीन बार के पैरालम्पिक पदक विजेता झाझडिया ने 2004 एथेंस ओलंपिक और 2016 रियो ओलंपिक मे एफ 46 भालाफेंक मे स्वर्ण पदक जीता था जबकि तोक्यो मे उन्होने रजत पदक जीता। उन्होने कहा , खिलाड़ी शारीरिक ही नही मानसिक रूप से भी सुपर फिट है। उन्हें टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) से पूरी सुविधाएं मिल रही है। हम कोबे में विश्व चैम्पियनशिप मे पांचवे स्थान पर रहे जो बड़ी बात है। पेरिस पैरालम्पिक 28 अगस्त से शुरू होंगे। झाझडिया ने कहा कि पिछले दस साल में भारत में खेलो का परिदृश्य बहुत बदल गया है। उन्होंने पैरालम्पिक के अपने सफर के बारे में कहा , 2004 में एथेंस में मै अपने खर्च पर गया था जहां विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। रियो ओलंपिक मे स्वर्ण जीतने के बाद चोटो के कारण खेल छोड़ने का मन बनाया लेकिन फिर तोक्यो ओलंपिक खेला। तोक्यो खेलो से पहले हमने कोरोना का दौर देखा जिस समय मै गांधीनगर में अभ्यास करता था। वहां सिर्फ दस लोग थे और पूरा परिसर खाली था लेकिन हमारी तैयारी पुख्ता रही।

कीर्ति के तहत 100 दिन में एक लाख खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी

नई दिल्ली। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कीर्ति परियोजना के दूसरे चरण की शुरूआत की, जिसका लक्ष्य 100 दिन के अंदर एक लाख युवा खिलाड़ियों की पहचान करना है। खेल मंत्री का मानना है कि खेलो इंडिया उदीयमान प्रतिभा पहचान (कीर्ति) भारत को 2047 तक ओलंपिक खेलो मे शीर्ष पांच देशो मे शामिल करने की दिशा मे महत्वपूर्ण कदम होगा।मांडविया ने यहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मे कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ करने के बाद कहा, भारत विविधता और संभावनाओं से भरा देश है। भारत में कभी बुद्धि, जनशक्ति या प्रतिभा की कमी नही रही है। उन्होने कहा, केवल शहर कि नही, दूर दराज के क्षेत्रों जैसे उत्तर-पूर्व, तटीय, हिमालई और आदिवासी क्षेत्रो मे भी अच्छे खिलाड़ी हो सकते है। कीर्ति कार्यक्रम के इस चरण मे खेलो इंडिया योजना के सभी 20 खेल शामिल होंगे।

देश को कुछ देने के जज्बे से खेले हॉकी टीम, पेरिस में पदक पक्का : अशोक ध्यानचंद

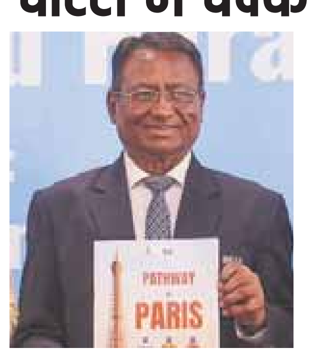

नई दिल्ली। भारतीय हॉकी के ओलंपिक मे गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए पूर्व धुरंधर अशोक ध्यानचंद ने कहा कि पेरिस ओलंपिक मे कठिन पूल के बावजूद भारत की तैयारी इतनी पुख्ता है कि पदक पक्का लग रहा है। तोक्यो ओलंपिक मे कांस्य पदक जीतकर 41 साल का इंतजार खत्म करने वाली भारतीय टीम को पेरिस मे पूर्व चैम्पियन अर्जेंटीना, बेल्जियम और आस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीमो के पूल मे जगह मिली है। अशोक कुमार ने पेरिस ओलंपिक और पैरालम्पिक की तैयारियो पर दिल्ली खेल पत्रकार संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित परिचर्चा मे कहा , मै टीम से इतना ही कहूंगा कि पूल पर ध्यान नही दें और मैच दर मैच प्रदर्शन पर फोकस रखें। प्रो लीग मे हमारा प्रदर्शन अच्छा नही रहा लेकिन यह टीम उस मुकाम पर है कि अपना दिन होने पर किसी को भी हरा सकती है। उन्होंने कहा , कई खिलाड़ियो का यह आखिरी ओलंपिक है और पदक जीतने के लिए वे कोई कोर कसर नही छोड़ेंगे। कांस्य को अब स्वर्ण पदक में बदलने की जरूरत है। विश्व कप 1975 मे भारत की खिताबी जीत के नायक रहे अशोक कुमार ने कहा , मैने 1972 मे अपना पहला ओलंपिक खेला तब खेल मंत्रालय नही होता था।

आईकू के गेमिंग एप युवाओं को जोड़ेंगे

नई दिल्ली। हाई-परफॉरमेंस स्मार्टफोन ब्रांड आईकू ने हाल ही में आईकू जेड 9 लाइट 5जी लॉन्च किया है, जो इसकी फुली लोडेड जेड सीरीज का लेटेस्ट एडिशन है। आईकू 9 लाइट 5जी कल से आईकू ई-स्टोर और अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। यह स्मार्टफोन पहली बार 5जी इस्तेमाल करने वालों के लिए एक शानदार विकल्प है, जिसमें एक शक्तिशाली प्रोसेसर, शानदार डिज़ाइन और सोनी का प्राइमरी कैमरा है। इसकी 8-कोर सीपीयू आर्किटेक्चर, लेटेस्ट 6एनएम प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो 414के+ से अधिक का प्रभावशाली स्कोर प्राप्त करती है, जो सीमलेस मल्टीटास्किंग, लैग-फ्री गेमिंग और आसान ऐप स्क्रॉलिंग सुनिश्चित करती है। आईकू 9 लाइट दो शानदार कलर आप्शन एक्वा फ्लो और मोका ब्राउन में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। आईकू 9 लाइट, एक पूरी तरह से लोडेड 5जी स्मार्टफोन है, जो मीडियाटेक डाइमेंसिटी6300 5जी मोबाइल प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित है। आईकू के मेक इन इंडिया के वादे को जारी रखते हुए - आईकू लाइट का निर्माण वीवो की ग्रेटर नॉएडा फैसिलिटी में किया जाएगा।

राइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ
राइट्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
शिखर, प्लॉट सं. 1, सैक्टर-29, गुरुग्राम-122001
सीआईएन : L74899DL1974GOI007227

जनशक्ति की नियुक्ति:

वीसी सं.	पद	रिक्तियों की संख्या
187/24	रेजिडेंट इंजीनियर – सिविल संविदा पर	05
188/24	रेजिडेंट इंजीनियर – मैकेनिकल संविदा पर	06
189/24	रेजिडेंट इंजीनियर – इलेक्ट्रिकल संविदा पर	03
190/24	उप महाप्रबंधक (ईएस एंड टी) नियमित आधार पर	02

पद, पारिश्रमिक, योग्यता, अनुभव, आयु, तिथि और स्थान, चयन प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, उम्मीदवार राइट्स की वेबसाइट www.rites.com पर कैरियर सेक्शन के अंतर्गत पोस्ट किए गए विस्तृत विज्ञापन को देख सकते हैं।

वीसी संख्या 187/24, 188/24 एवं 189/24 के लिए लिखित परीक्षा 18.08.2024 को गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर और गुरुग्राम में आयोजित की जाएगी।

अतीत में ओलंपिक पदक के करीब पहुंच कर भारतीय खिलाड़ियों को मिली निराशा

भाषा। नई दिल्ली

अक्सर कहा जाता है कि ओलंपिक मे चौथा स्थान हासिल करना किसी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी निराशा होती है। किसी प्रतियोगिता मे आखिरी स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को अगर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो वही चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को पदक चूकने की टिस रहती है। खेल के सबसे बड़े वैश्विक मंच पर भारतीय खिलाड़ी कई बार बेहद करीब से ओलंपिक पदक जीतने से चूक गए।

मेलबर्न ओलंपिक , 1956

भारतीय फुटबॉल टीम ने क्वार्टर फाइनल मे मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल मे जगह बनाई। इस मैच मे ही नेविल डिसूजा ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाले पहले एशियाई बने। नेविल ने सेमीफाइनल मे यूगोस्लाविया के खिलाफ टीम को बढ़त दिला कर अपने प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश की लेकिन यूगोस्लाविया ने दूसरे हाफ मे जोरदार वापसी करते हुए मुकाबले को अपने पक्ष मे कर लिया। कांस्य पदक मुकाबले मे भारत बुल्गारिया से 0-3 से हार गया। भारत के महान खिलाड़ी पीके बनर्जी अक्सर अपनी इस पीड़ा को साझा करते थे।

रोम ओलंपिक, 1960

महान मिल्खा सिंह 400 मीटर फाइनल मे पदक के दावेदार थे लेकिन वह सेकंड के 10वे हिस्से से कांस्य पदक जीतने से चूक गए। विभाजन के बाद अपने माता-पिता को खोने के बाद इसे उनकी सबसे बुरी याद के रूप मे याद किया जाएगा। इस हार के बाद फ्लाइंग सिख ने खेल लगभग छोड़ ही दिया था। उन्होंने इसके बाद 1962 के एशियाई खेलो मे दो स्वर्ण पदक जीते लेकिन ओलंपिक पदक चूकने की टिस हमेशा बरकरार रही।

मास्को ओलंपिक, 1980

नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन जैसे शीर्ष हॉकी देशो ने अफगानिस्तान पर तत्कालीन सोवियत संघ के आक्रमण पर मास्को खेलो का बहिष्कार किया था, भारतीय महिला हॉकी टीम के पास अपने पहले प्रयास मे ही पदक जीतने का बड़ा मौका था। टीम को हालांकि पदक से चूकने की निराशा का सामना करना पड़ा। टीम अपने आखिरी मैच मे सोवियत संघ से 1-3 से हारकर चौथे स्थान पर रही।

लास एंजिलिस ओलंपिक, 1984

लास एंजिलिस ओलंपिक ने मिल्खा की रोम ओलंपिक की यादे फिर से ताजा कर दी जब पीटी उषा 400 मीटर बाधा दौड़ मे सेकंड के 100वे हिस्से से कांस्य पदक से चूक गईं। जिससे यह किसी भी प्रतियोगिता मे किसी भारतीय एथलीट के लिए अब तक की सबसे करीबी चूक बन गई। पय्योली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर उषा रोमानिया की क्रिस्टीना कोजोकारू के बाद चौथे स्थान पर रही। वह हालांकि अपनी इस साहसिक प्रयास के बाद घरेलू नाम बन गई।

एथेंस ओलंपिक 2004 : दिग्गज लिएंडर पेस और महेश भूपति की टेनिस मे भारत की संभवतः सबसे महान युगल जोड़ी एथेस खेलो मे पुरुष युगल मे पोडियम पर पहुंचने से चूक गई।पेस और भूपति क्रोएशिया के मारियो एनसिक और इवान ल्युबिसिक से मैराथन मैच मे 6-7, 6-4, 14-16 से हारकर कांस्य पदक से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे।इस जोड़ी को इससे पहले सेमीफाइनल मे निकोलस किफर और रेनर शटलर की जर्मनी की जोड़ी से सीधे सेटो मे 2-6, 3-6 से हार का सामना करना पड़ा था। इन खेलो मे कुंजारानी देवी महिलाओ की 48 किग्रा भारोत्तोलन प्रतियोगिता मे चौथे स्थान पर रही, लेकिन वह वास्तव मे पदक की दौड़ मे नही थी। वह क्लीन एवं जर्क वर्ग मे 112.5 किग्रा वजन उठाने के अपने अंतिम प्रयास मे अयोग्य घोषित कर दी गईं। कुंजारानी 190 किग्रा के कुल प्रयास के साथ कांस्य पदक विजेता थाईलैंड की एरी विराथावोर्न से 10 किग्रा पीछे रही।

लंदन ओलंपिक, 2012

निशानेबाज जॉयदीप करमाकर ने इस सत्र मे कांस्य पदक विजेता से एक स्थान पीछे रहने के निराशा का अनुभव किया। करमाकर पुरुषो की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड मे सातवे स्थान पर रहे थे और फाइनल मे वह कांस्य पदक विजेता से सिर्फ 1.9 अंक पीछे रहे।

तोक्यो आंलपिक, 2020

मास्को खेलो के चार दशक के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम को एक बार फिर करीब से पदक चूकने का दंस झेलना पड़ा। भारतीय टीम तीन बार की ओलंपिक चैम्पियन ऑस्टेलिया को हराकर सेमीफाइनल मे पहुंची लेकिन उसे अंतिम चार मैच मे अर्जेंटीना से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। रानी रामपाल की अगुवाई वाली टीम को इसके बार कांस्य पदक मैच मे ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ 3-2 की बढ़त को बरकरार नही रख सकी और 3-4 से हार गई। इसी ओलंपिक मे अदिति अशोक ऐतिहासिक पदक जीतने से चूक गई।

सीएमवाईके प्रिंटेक के लिए तथा उसी की ओर से मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा टिन टिन प्रिंटेक प्रा.लि. सी–33 अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज लखनऊ से मुद्रित एवं चौथी मंजिल, सहारा शापिंग सेंटर, फैजाबाद रोड, लखनऊ (फोन: 0522–4036600) से प्रकाशित। प्रधान सम्पादक: शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: विजय प्रकाश सिंह। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।